

20 मई, 2022 \* वर्ष 31, पृष्ठ संख्या 60, अंक-5

# राजस्थान सुजस

जल ही  
जीवन है

जल संसाधन विशेषांक



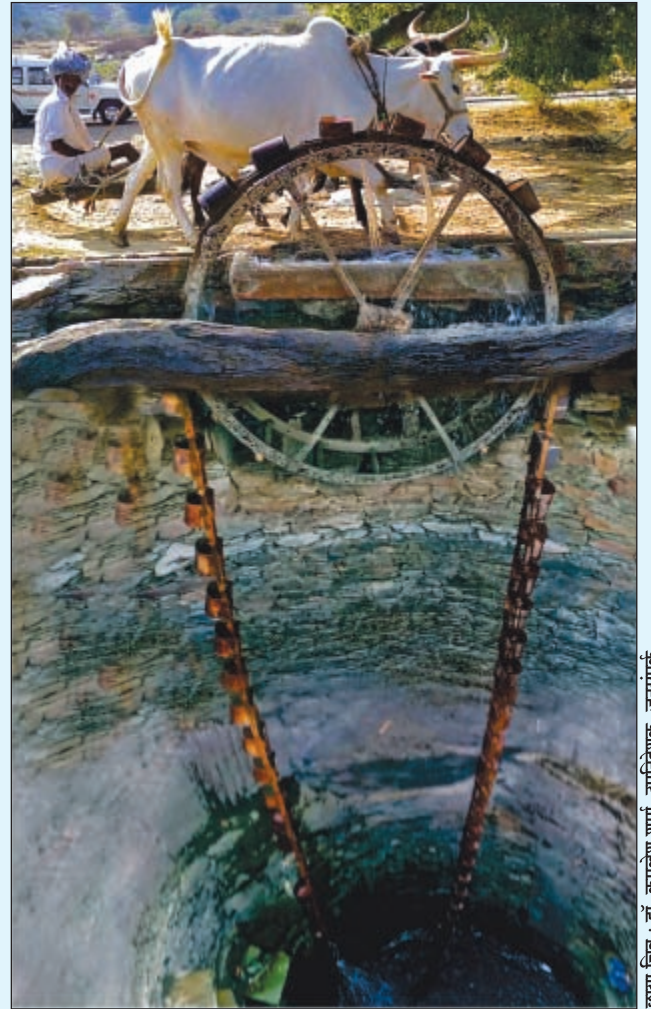


आज भी अस्तित्व में है

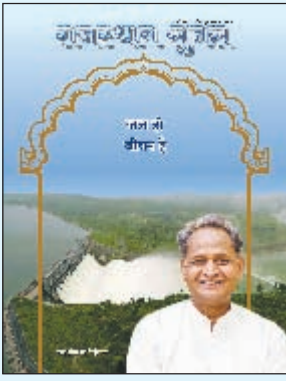
## रहट

सिंचाई की परंपरागत पद्धति

**रा**जस्थान के दक्षिणांचल मेवाड़ वागड़ में आज भी सिंचाई की परंपरागत पद्धतियां दिखाई देती हैं। रहट भी ऐसी ही तकरीबन 5 हजार साल पुरानी सिंचाई पद्धति है। बुजुर्ग बताते हैं कि पुराने समय में तो रहट, चड़स तथा ढेंकुली ही सिंचाई के साधन थे। अब तो इनके दर्शन ही दुर्लभ हैं। रहट या चड़स पद्धति, जिसे पर्शियन वेल के नाम से जाना जाता है, भारत की नहीं अपितु बाहर से आयी पद्धति है और अभी भी कई जगह काम में ली जा रही है। बताया जाता है कि पहले लकड़ी से भी रहट बनाए जाते थे, डिब्बों के विकल्प के तौर पर मिट्टी की गेड़ों का इस्तेमाल भी होता था। उदयपुर जिले के गोगुंदा उपखंड क्षेत्र में रहट का प्रचलन आज भी दिखाई देता है।



छाया चित्र : डॉ. कमलेश शर्मा, उपनिदेशक, जनसंपर्क



प्रधान सम्पादक  
पुरुषोत्तम शर्मा

संपादक  
अलका सक्सेना

सह-संपादक  
डॉ. लोकेश चन्द्र शर्मा

उप-संपादक  
सम्पत राम चान्दोलिया  
आशाराम खटीक

कला  
विनोद कुमार शर्मा

आवरण छाया  
डॉ. कमलेश शर्मा

राजस्थान सुजस में प्रकाशित सामग्री में व्यक्त विचार लेखकों के अपने एवं आंकड़े परिवर्तनशील हैं। आवश्यक नहीं कि शासन उनसे सहमत हो। सुजस में प्रकाशित सामग्री का विभाग किसी भी रूप में उपयोग कर सकेगा।

ग्राफिक डिजाइनिंग  
कृष्णा प्रिंटर्स

सम्पर्क  
सम्पादक

राजस्थान सुजस (मासिक)  
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग  
सचिवालय, जयपुर-302005  
मो. नं. 94136-24352

e-mail :  
publication.dipr@rajasthan.gov.in  
editorsujas@gmail.com

Website :  
www.dipr.rajasthan.gov.in



छाया : लक्ष्मण शर्मा

## सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान का मासिक

वर्ष : 31 अंक : 05

इस अंक में

मई, 2022

### इंदिरा गांधी नहर परियोजना



05

### गांव-ढाणी तक पहुंच रहा पेयजल



22

### पाली में रेल से पानी



42

लोक जीवन	02
सम्पादकीय	04
प्रदेश में बदलाव का उद्यम	15
महू प्रदेश से हरित प्रदेश...	20
साक्षात्कार : जल संसाधन मंत्री	24
साक्षात्कार : जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री	26
बातचीत : प्रमुख सचिव, जल संसाधन	28
ईसरदा बांध पेयजल परियोजना	32
सामयिकी	35
जाना-अनजाना राजस्थान	36
राजस्थान की गौरवमयी गाथा	38
गढ़सीसर...जैतसर...	44
पोकरण परमाणु परीक्षण...	45
ज्ञान-विज्ञान	47
महिला सशक्तीकरण	48
नवाचार	50
उपभोक्ता की समस्या का हल...	54
बड़बेला तालाब...	55
अजमेर का नया आकर्षण है झीलें...	56
मेवाड़ अंचल का विश्व विख्यात जलतंत्र	58
धरोहर	59
तब और अब	60

### बेहतर जल प्रबंधन...



30-31

राजस्थान सुजस के आगामी अंक के लिए  
मौलिक, अप्रकाशित सामग्री भिजवायें।  
कृपया अपने आलेख एवं फोटोग्राफ सम्पादक  
को e-mail : editorsujas@gmail.com पर अथवा  
डाक से भेजें।

### पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना



12

### परवन वृहद बहुउद्देशीय परियोजना

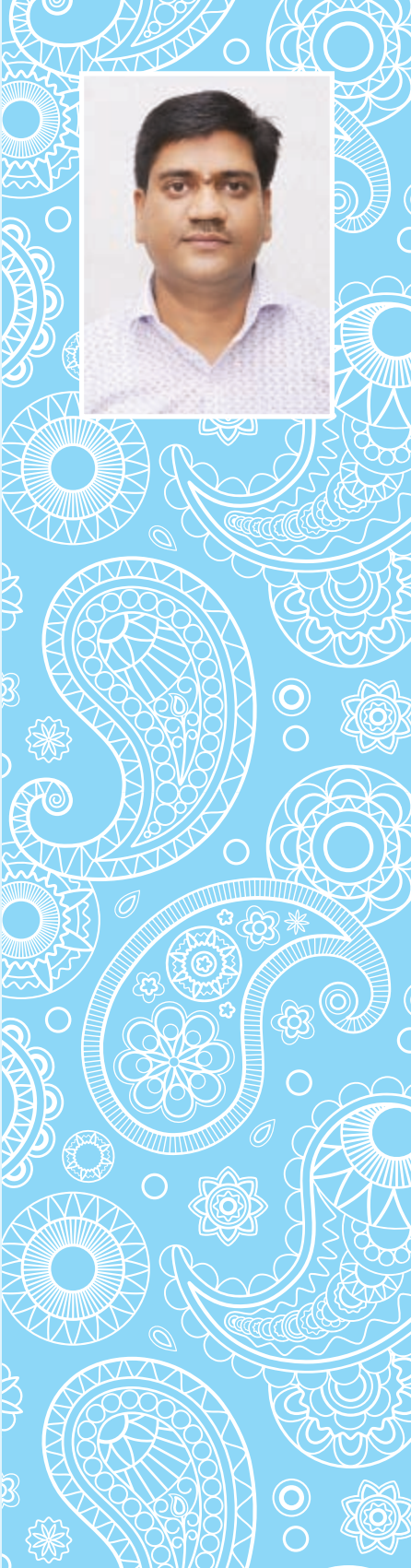


34

### जल जीवन मिशन



52



## जल संरक्षण के लिए सतत प्रयास

पानी जीवन के लिए अनमोल है। यह सच है कि जल है तो कल है। इसलिए हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जल संकट का समाधान जल के संरक्षण से ही है। जल के संरक्षण में जन-जन की भागीदारी आवश्यक है। हम सभी को मिल-जुल कर सतत प्रयास करते हुए जल के संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण कार्य में भागीदारी निभानी होगी। यह संदेश हमें हमारी भावी पीढ़ी को भी देना होगा। हम बहुत समय से सुनते आ रहे हैं कि जल ही जीवन है। जल के बिना सुनहरे कल की कल्पना नहीं की जा सकती। जीवन के सभी कार्यों के निष्पादन हेतु जल की आवश्यकता होती है। इसलिए सुदृढ़ भविष्य के लिए जल संरक्षण के अभियान में निरन्तर सभी को प्रयास करने हैं।

राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। यहां की भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि यहां पानी की उपलब्धता अधिक नहीं है। राज्य सरकार ने गर्मियों के मौसम में प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जनता को निर्बाध एवं नियमित रूप से पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जिलों में कलक्टर्स को सुचारू जलापूर्ति और उपलब्ध जल संसाधनों के व्यवस्थित प्रबंधन के निर्देश दिये हैं।

प्रदेश में सुचारू जलापूर्ति के लिए कंटीजेंसी प्लान के तहत आवश्यक स्वीकृतियां जारी कर समय पर कार्य, हैंडपम्प एवं नलकूप मरम्मत के कार्यों को अभियान के रूप में पूरा किया जा रहा है। आमजन की पेयजल संबंधित शिकायतों की सतत मॉनिटरिंग कर उनका संवेदनशीलता से समाधान किया जा रहा है।

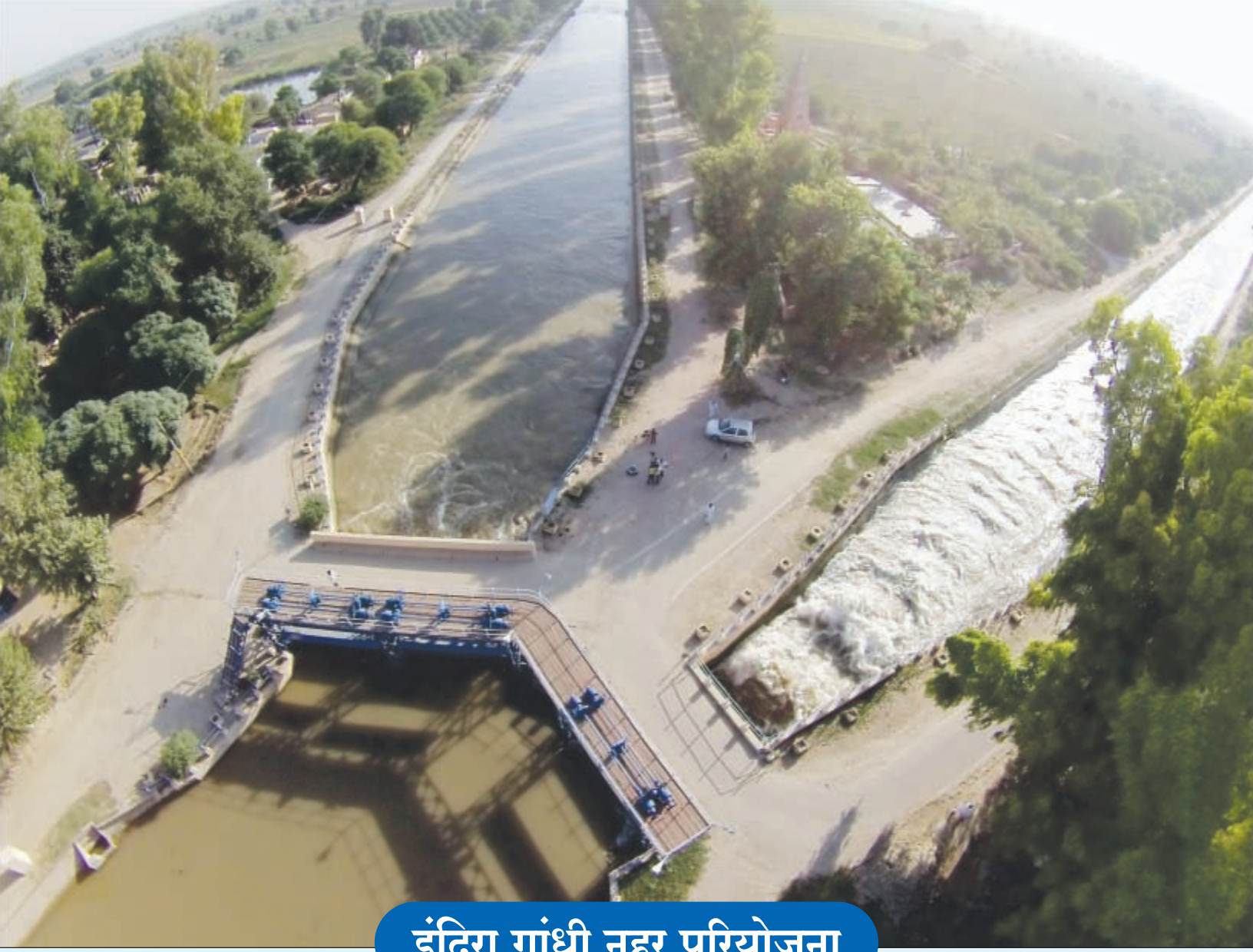
राजस्थान सुजस का मई माह का “जल संसाधन” पर आधारित अंक आपके समक्ष प्रस्तुत है। प्रस्तुत अंक में प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर जल संसाधनों से जुड़ी रोचक सामग्री के साथ अन्य ज्ञानवर्धक व उपयोगी जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। जल संसाधनों की विभिन्न परियोजनाओं की जानकारी, सामयिक, जाना-अनजाना राजस्थान, राजस्थान की गौरवमयी गाथा और ज्ञान-विज्ञान से जुड़े कॉलम में ग्रहों की रोचक जानकारी के साथ प्रदेश की ज्ञानवर्धक और उपयोगी जानकारी पहुंचाने के अनुष्ठान में हम निरन्तर प्रयत्नशील हैं।

आपके बहुमूल्य सुझाव एवं प्रतिक्रियाओं का सदैव की भांति स्वागत है।

अभिवादन एवं मंगलकामनाओं सहित

(पुरुषोत्तम शर्मा)

प्रधान संपादक



## इंदिरा गांधी नहर परियोजना

### जिसने बदल दिया राजस्थान का भूगोल

**हि** मालय से निकली यह नहर न सिर्फ तीन राज्यों के करोड़ों लोगों के गले तर कर रही है बल्कि इसके पानी से ही लाखों किसानों की फसलें खेतों में लहलहा रही हैं। यकीन मानिए राजस्थान जैसे भौगोलिक विषमताओं वाले प्रदेश में इंदिरा गांधी नहर किसी वरदान से कम नहीं। वो भी ऐसा वरदान, जिसने राजस्थानी माटी का भूगोल हमेशा के लिए बदलकर रख दिए।

आजादी मिलने से पहले और उसके बाद के हालातों में कौन सोच सकता था कि रेतीले धोरों में बहार आ सकती है। रेगिस्तान में भी फसलें लहलहा सकती हैं या फिर दूर-दराज के इलाकों तक पानी पहुंचाया जा सकता है। ये सारी बातें आज भले आसान लगें, लेकिन उस वक्त लगभग नामुमकिन थीं। उस दौर में तो बिल्कुल, जब पीने का

अनिल कुमार शाक्य

जनसम्पर्क अधिकारी, श्रीगंगानगर

साफ पानी भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। खेती-बाड़ी सरीखे दूसरे कारोबार के लिए लोग बादलों का मुंह ताकते थे। अनियमित बारिश और मीलों फैले रेगिस्तान में बिन पानी जीवों से लेकर जानवर तक सब बेहाल। ऐसे मुश्किल हालात में अकाल जैसी विभीषिका जब कोढ़ में खाज बनने लगीं, तब तत्कालीन बीकानेर रियासत ने रेतीले धोरों में पानी लाने की सोची। मौजूदा हालातों में देखें तो इस बात को तकरीबन सौ साल बीत चुके हैं परन्तु ये भी सच है कि लंबा-चौड़ा क्षेत्रफल सिंचित होने के बावजूद गंगानगर-हनुमानगढ़ में ही पानी के लिए आंदोलन होते हैं। फिर भी इसमें कोई दो राय नहीं कि नहरी पानी की

बदौलत ही रेतीले धोरों की तकदीर बदली और अधिकांश: उद्योग-धंधे पनपे। इस नाते, श्रीगंगानगर को ऐश्वर्य-समृद्धि के साथ-साथ पूरी दुनिया में नाम देने वाली इंदिरा गांधी नहर और गंगनहर के पानी से परिचय जरूरी है।

### गंगानगर में नहरी पानी का इतिहास

राज्य के उत्तरी हिस्से श्रीगंगानगर जिले में तीन नहर प्रणालियों के अलावा मौसमी नदी घग्घर से मानसून के दिनों में प्रचुर मात्रा में पानी मिल जाता है लेकिन पानी के मामले में समृद्धि पाने के लिए श्रीगंगानगर जिले सहित तत्कालीन बीकानेर रियासत ने बहुत संघर्ष किया है। यहां भी राजस्थान के अन्य जिलों की तरह कभी पानी का जबरदस्त संकट था। यहां के लोग केवल पशुपालन और मानसून की बरसात पर निर्भर थे। दुनिया के सबसे कम बरसात वाले क्षेत्रों में से एक मरुस्थल के अंतिम छोर पर स्थित तत्कालीन बीकानेर रियासत के हिस्से श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ ने पानी की एक-एक बूंद के लिए लंबा संघर्ष किया है। 19वीं सदी के अंतिम वर्षों तक यहां फिरोजशाह नहर की टेल थी। इसका एक हिस्सा भादरा तहसील क्षेत्र के कुछ गांवों में सिंचाई पानी देता था और दूसरा हिस्सा तलवाड़ा झील क्षेत्र तक पहुंचता था। बाद में तलवाड़ा झील क्षेत्र के इस छोटे से रजबाहे (नहर) के स्थान पर साउथ घग्घर कैनाल बनाकर इसे उसमें समाहित कर दिया। फिरोजशाह नहर गर्मियों में लगभग बंद हो जाती थी। इससे उस क्षेत्र के लोग पेयजल के लिए तरस जाया करते थे।

फिरोजशाह नहर जिसे नया नाम पश्चिम यमुना नहर दिया गया था, उसकी बीकानेर राज्य में 32 किलोमीटर लंबाई थी। बीच में इसमें पानी आना बंद हो गया। बहुत प्रयत्न करने पर भादरा तहसील की 184 हैक्टेयर भूमि इससे सिंचित करने की अनुमति पंजाब (तत्कालीन ब्रिटिश सरकार) ने दी। बाद में सन् 1893 में इस नहर में पानी आना बंद हो गया। इसका कारण बताया गया कि पंजाब में बहुत अधिक बरसात से यह नहर टूट गई। फिर इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। जिले के लोगों का कहना है कि तब बीकानेर रीजेंसी (धारा सभा) ने प्रस्ताव के जरिए सरस्वती नदी बेसिन क्षेत्र को आधार मान पंजाब से अपने अधिकार के पानी की मांग उठाई। इसी आधार पर कालांतर में गंगनहर के जरिए पानी मिला।

दूसरी नहर, घग्घर की नहर थी। जब तत्कालीन पंजाब में जाखल के पास बांध बनाकर घग्घर से एक नहर निकाली गई, तो बीकानेर राज्य के इस जिले में घग्घर का पानी आना बंद हो गया। राज्य ने पंजाब सरकार से इसकी कई बार शिकायत की तो सन् 1896 में अंग्रेज सरकार और बीकानेर रियासत के सम्मिलित खर्च से ओटू नामक स्थान में बांध बनाकर उससे उत्तरी और दक्षिणी दोनों तरफ नहरें निकलवाने का प्रबंध किया गया। आज की नॉर्थ घग्घर और साउथ घग्घर कैनाल का यहीं से उदय हुआ था। ये नहरें 1897 में तैयार हुईं, जिनकी कुल

लंबाई 153 किलोमीटर थी। बीकानेर रियासत की सीमा के भीतर उत्तरी और दक्षिणी नहरों की लंबाई 85 किलोमीटर और वितरिकाओं की लंबाई 37 किलोमीटर थी। इन नहरों के बनवाने में कुल 6 लाख रुपए खर्च हुए। इनमें से लगभग आधा बीकानेर स्टेट ने दिया। इन नहरों का प्रबंध पंजाब के सिंचाई विभाग ने 1897 से 31 मार्च 1904 तक किया। इस दौरान वार्षिक औसत सिंचाई का क्षेत्र 2636 हैक्टेयर (1888 हैक्टेयर खरीफ में और 748 हैक्टेयर रबी में) था। बीकानेर राज्य ने इन नहरों का प्रबंध 1 अप्रैल 1904 से संभाला। अधिकांश पानी पंजाब में ले लिए जाने से राज्य के भीतर सिंचाई का औसत कम रहा। फिर भी बार-बार लिखा-पढ़ी होने पर 1931 से राज्य में पहले से अधिक अर्थात् 2844 हैक्टेयर भूमि सिंचाई के लिए पानी प्राप्त होने लगा।

बीकानेर रियासत ने सिंधु सरस्वती बेसिन क्षेत्र के कारण नदियों में अपने हिस्से के पानी का दावा नहीं छोड़ा और बार-बार की लिखा-पढ़ी और सतत प्रयासों के कारण बहावलपुर, पंजाब और बीकानेर के संयुक्त प्रयासों से सतलुज नदी में से हिस्से का पानी लेने के लिए स्वीकृति मिली। 4 सितंबर 1920 को समझौता हुआ और तीनों सरकारों ने यह योजना स्वीकार की। इस समझौते के पश्चात ही इस पर काम शुरू कर दिया गया और इसका शिलान्यास तत्कालीन महाराजा गंगासिंह ने 5 दिसंबर 1925 में फिरोजपुर के हुसैनीवाला में किया। इस पर 3 करोड़ रुपए खर्च हुए। उद्घाटन तत्कालीन वायसराय लार्ड इरविन ने 26 अक्टूबर 1927 में किया। यह एक ऐतिहासिक दिन था जबकि इस क्षेत्र के 2560 वर्ग किलोमीटर में सिंचाई के लिए पानी मिला, जहां सदियों से जमीन प्यासी चली आ रही थी। इस अवसर पर हुसैनीवाला हैड वर्क्स पर अनेक राजा-महाराजा एवं भारत के विख्यात पुरुष उपस्थित थे, जिनमें पंडित मदनमोहन मालवीय का नाम उल्लेखनीय है। यही नहर वर्तमान में गंगनहर है।

नहर से सिंचाई रबी सीजन में 1928 से शुरू हुई। शुरुआत में बीकानेर राज्य के हिस्से 2104 क्यूसेक पानी मिला। इसमें 2,80000 हैक्टेयर भूमि की सिंचाई क्षमता थी, परंतु बाद में और अधिक के लिए



दावा करने पर गंगनहर में 2720 क्यूसेक पानी मिला। यह फैसला 1937 के एंडरसन अवार्ड के नाम से विख्यात है, जिससे सतलुज के पानी को पंजाब, बीकानेर और बहावलपुर के बीच बांटा गया। भारत विभाजन के काफी समय बाद हुसैनीवाला हैड से गंगनहर की आरडी 42 तक नहर बंद करके हरिके हैड से निकलने वाली सरहिंद फीडर के जरिए उसकी टेल आरडी-55 से फिरोजपुर फीडर निकालकर आरडी-42 पर लिंक दिया गया। यहां से हमारी नई गंगनहर (बीकानेर कैनाल) आती है। इसका पानी राज्य में खरखां हैड से प्रवेश करता है।

यह भगीरथ प्रयास राज्य के लिए बड़ा लाभदायक साबित हुआ। कालांतर में इसी के जरिए भाखड़ा और इंदिरा गांधी नहर निर्माण का रास्ता खुला। भाखड़ा परियोजना के अंतर्गत नहरों का निर्माण 1952 में शुरू हुआ, जो 1957 में पूरा हुआ। इस पर लगभग 4 करोड़ 58 लाख रुपये खर्च हुए। इस परियोजना के तहत सिंचाई जुलाई, 1954 में शुरू हुई। इसके नीचे आने वाला क्षेत्र 3 लाख 68 हजार हैक्टेयर से अधिक रहा। राज्य का सबसे बड़ा जल स्रोत रावी, व्यास, सतलुज नदी से मिलने वाला पानी है, जिससे पंजाब व हरियाणा को भी पानी उपलब्ध होता है। इन तीनों नदियों से प्राप्त पानी व पानी का वितरण, प्रबंधन, रख-रखाव समस्त कार्य भाखड़ा व्यास प्रबंधन निगम के पास है। वैसे, राज्य को रावी-व्यास के अतिरिक्त पानी में से जो हिस्सा देना तय हुआ, उसमें से 0.17 एमएएफ पानी आज तक राज्य को उपलब्ध नहीं हो पाया है। यह पानी पंजाब, हरियाणा व राजस्थान के मुख्यमंत्रियों ने 15 जनवरी 1982 के निर्णय से पहले ही राज्य का 1 लाख एकड़ फीट पानी कम कर दिया था। इसके बाद 0.47 एमएएफ पानी देना तय हुआ, जिसमें से 0.30 एमएएफ पानी राजस्थान को दक्षिणी घग्घर एवं जंडवाला वितरिका के लिए उपलब्ध है। शेष 0.17 एमएएफ पानी 1 लाख 70 हजार एकड़ फीट पानी भाखड़ा मैन लाइन के मार्फत सिद्धमुख नोहर क्षेत्र को देना तय था लेकिन यह पानी उपलब्ध नहीं करवाया गया।

### बीबीएमबी में मिल सकेगा राजस्थान को भी प्रतिनिधित्व

तकरीबन चार दशकों के बाद केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने मार्च 2022 के पहले सप्ताह में एक अधिसूचना जारी कर भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) के नियमों में बदलाव किया। इस अधिसूचना के मुताबिक बीबीएमबी में हरियाणा और पंजाब के सदस्य जरूरी नहीं होंगे। तय मानक पूरे करने पर किसी भी राज्य के सदस्य की नियुक्ति बीबीएमबी में हो सकेगी। जल संसाधन विभाग उत्तर संभाग हनुमानगढ़ के मुख्य अभियंता श्री अमरजीत मेहरड़ा ने बताया कि केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर बीबीएमबी सदस्यों की नियुक्ति के लिए पात्रता निर्धारित की है। ऊर्जा मंत्रालय की ओर से नियमों में बदलाव करते हुए अन्य राज्यों को भी सदस्यता का विकल्प प्रदान किया गया है।

### परियोजना की जानकारी

इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल-व्यास तथा सतलुज नदियों के संगम पर स्थित हरिके बैराज है। जल उपलब्धता/आवंटन-रावी व्यास नदियों के अधिशेष जल में राजस्थान के हिस्से (8.6 एम.ए.एफ.) में से 7.59 एम.ए.एफ. पानी इंगानप के लिए आवंटित है। इंदिरा गांधी फीडर (राजस्थान फीडर) की लंबाई 204 किमी (170 किमी पंजाब व हरियाणा में तथा 34 किमी राजस्थान में) है। हरिके हैड पर फीडर नहर की क्षमता 18500 क्यूसेक है। इंदिरा गांधी मुख्य नहर का उद्गम इंदिरा गांधी फीडर के अन्तिम छोर से है। मुख्य नहर की लंबाई 445 किमी है जबकि राजस्थान में नहर हनुमानगढ़ जिले के मसीतावाली हैड से शुरू होती है।

प्रथम चरण में हरिके हैड से फीडर नहर एवं मुख्य नहर के 189 किमी पूंगल (बीकानेर) तक तथा इससे निकलने वाली वितरण प्रणाली (मुख्य नहर से निकलने वाली साहवा लिफ्ट प्रणाली के अतिरिक्त) का निर्माण हुआ जबकि इंदिरा गांधी मुख्य नहर के 189 किमी पूंगल





(बीकानेर) से अन्तिम छोर मोहनगढ़ (जैसलमेर) तक तथा इससे निकलने वाली वितरण प्रणाली साहवा लिफ्ट प्रणाली दूसरे चरण में बनी।

इस महत्वाकांक्षी परियोजना की रूपरेखा प्रथम बार बीकानेर रियासत के मुख्य सिंचाई अभियंता श्री कंवरसेन ने अपने अध्ययन 'बीकानेर राज्य में पानी की आवश्यकता' के रूप में 1948 में प्रस्तुत की। तत्कालीन महाराजा गंगासिंह गंगनहर की सफलता से श्रीगंगानगर क्षेत्र में हुई खुशहाली से प्रेरित होकर सतलुज एवं व्यास नदियों के पानी में से और अधिक हिस्सा प्राप्त करने के लिए पहले से ही प्रयासरत थे। उन्हीं के प्रयासों को अमलीजामा पहनाने के लिए इस परियोजना की रूपरेखा 1948 में केन्द्र सरकार को प्रेषित की गई। इसका मुख्य उद्देश्य रावी व व्यास नदियों के जल से राजस्थान को आवंटित 8.6 एमएएफ पानी में से 7.59 एमएएफ पानी का उपयोग कर पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई व पेयजल सुविधाओं का विस्तार, मरुस्थलीकरण रोकना, पर्यावरण सुधार, वृक्षारोपण, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, पशु संपदा का संरक्षण व विकास तथा कृषि उत्पादन को बढ़ाना था। राजस्थान में पानी की आवश्यकता को देखते हुए केन्द्र सरकार ने अंततः यह परियोजना मंजूर कर ली। 31 मार्च 1958 को तत्कालीन गृहमंत्री श्री गोविन्द बल्लभ पंत ने राजस्थान की जीवन रेखा (लाइफ लाइन) कही जाने वाली इस महत्वपूर्ण परियोजना की आधारशिला रखी। परियोजना निर्माण के लिए 1958 में आईजीएनपी बोर्ड गठित किया गया। कुल लंबाई 649 किमी है जबकि वितरण प्रणाली की कुल

लंबाई 9413 किमी है। इंदिरा गांधी फीडर की गहराई 21 फीट एवं राजस्थान सीमा पर फीडर के तले की चौड़ाई 134 फीट है।

### इंदिरा गांधी नहर की प्रमुख शाखाएं

इंदिरा गांधी नहर से निम्न मुख्य शाखाएं निकाली गई हैं-

1. रावतसर शाखा: यह हनुमानगढ़ जिले में निकाली गई नहर की पहली शाखा है। यह नहर के बाईं तरफ है।
2. सूरतगढ़ शाखा: श्रीगंगानगर जिले में सूरतगढ़, श्रीविजयनगर और अनूपगढ़ तहसील क्षेत्र को सरसब्ज करती है।
3. अनूपगढ़ शाखा: गंगानगर के श्रीविजयनगर और अनूपगढ़ तथा कुछ बीकानेर जिले की खाजूवाला तहसील के अलावा यह नहर घड़साना तहसील क्षेत्र को हरा-भरा करती है।
4. पूंगल ब्रांच-बीकानेर: दंतोर वितरिका-बीकानेर।
5. बिरसलपुर-बीकानेर: चारणवाला-बीकानेर, जैसलमेर।
6. शहीद बीरबल शाखा-जैसलमेर।
7. सागरमल गोपा नहर-जैसलमेर।

इसके अतिरिक्त नहर के अंतिम छोर मोहनगढ़ (जैसलमेर) से दो बड़ी उपशाखाएं-लीलवा व दीघा एवं सागरमल गोपा शाखा के अंतिम छोर से गडरा रोड (बरकतुल्ला खां उपशाखा वर्तमान नाम बाबा रामदेव शाखा) उप शाखा भी निकाली गई हैं। सागरमल गोपा शाखा के अंतिम छोर से आगे बाबा रामदेवजी (गडरा रोड शाखा) 34 शाखा की बुर्जी 315 तक निर्माण के लिए पानी उपलब्ध है। गडरा रोड उप शाखा व



इसकी वितरिकाओं पर कार्य जारी है। परियोजना की विभिन्न शाखाओं-अनूपगढ़, पूगल, सूरतगढ़, चारणवाला व बिरसलपुर पर लघु पन विद्युत गृह स्थापित किए गए हैं।

मुख्य नहर के बाईं ओर का इलाका ऊंचा होने एवं पानी के स्वतः प्रवाहित न होने के कारण नहर प्रणाली पर निम्न 7 लिफ्ट नहरें बनाई गई हैं-

1. चौधरी कुंभाराम लिफ्ट (नोहर, साहवा लिफ्ट नहर), हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, झुंझुनूं।
2. कंवरसेन लिफ्ट नहर (बीकानेर-लूणकरणसर लिफ्ट नहर) बीकानेर एवं श्रीगंगानगर। यह योजना की सातों लिफ्ट में सबसे लम्बी (151.64 किमी) लिफ्ट नहर है।
3. पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर (गजनेर लिफ्ट नहर) बीकानेर एवं नागौर जिले। इससे निकलने वाली कानासर वितरिका से नागौर जिले एवं बीकानेर के कोलायत व नोखा के कुछ गांवों को पानी दिया जाता है।
4. वीर तेजाजी लिफ्ट नहर (भैरुदान छालानी (बांगड़सर) लिफ्ट नहर) बीकानेर।
5. डॉ. करणीसिंह लिफ्ट नहर (कोलायत लिफ्ट नहर) जोधपुर व बीकानेर
6. गुरु जम्भेश्वर लिफ्ट नहर (फलौदी लिफ्ट नहर) जोधपुर, बीकानेर एवं जैसलमेर
7. जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर (पोकरण) जैसलमेर, जोधपुर

### इंदिरा गांधी नहर परियोजना में कब, क्या हुआ

1. 29.10.1948 में बीकानेर रियासत के मुख्य सिंचाई अभियंता श्री आर. बी. कंवरसेन ने योजना की प्रारंभिक रिपोर्ट बनाकर केन्द्र सरकार को भेजी। 1953 में केन्द्रीय सिंचाई एवं नौवहन आयोग ने इस नहर परियोजना की प्रथम परियोजना रिपोर्ट तैयार की। इसे विश्व बैंक की टीम ने स्वीकृत कर लिया। 1957 में राजस्थान सरकार ने परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट बनाकर योजना आयोग को भेजी। योजना आयोग ने यह योजना मंजूर की।
2. मार्च, 1958 में नहर के निर्माण कार्य का शुभारंभ तत्कालीन केन्द्रीय गृह मंत्री श्री गोविन्द बल्लभ पंत ने किया।
3. 19.12.1958 में राजस्थान नहर बोर्ड का गठन। श्री कंवरसेन प्रथम अध्यक्ष बनाए गए।
4. 11.30.1961 में राजस्थान नहर में उपराष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधा कृष्णन ने प्रथम बार नौरंगदेसर वितरिका से पानी छोड़ा।
5. 1963 में लिफ्ट कैनाल स्कीम को योजना में शामिल किया गया।
6. जून, 1964 में राजस्थान फीडर (हरिके बैराज से मसीतावाली

हनुमानगढ़ तक 204 किमी) का निर्माण पूर्ण हुआ।

7. 5.7.1968 में योजना की प्रथम लिफ्ट नहर लूणकरणसर लिफ्ट नहर (अब कंवरसेन लिफ्ट नहर) पर निर्माण कार्य प्रारंभ।
8. 1974 में इस नहर परियोजना क्षेत्र के विकास के लिए कमाण्ड एरिया विकास प्राधिकरण का गठन।
9. जून, 1975 में मुख्य नहर (मसीतावाली से छतरगढ़, पूगल, बीकानेर तक) का 189 किमी का निर्माण पूरा।
10. दिसंबर, 1976 में लूणकरणसर लिफ्ट नहर पूर्ण।
11. 31.10.83 में लूणकरणसर लिफ्ट नहर से बीकानेर शहर को पेयजल की आपूर्ति शुरू।
12. नवंबर, 1984 में राजस्थान नहर का नाम परिवर्तित कर इंदिरा गांधी नहर परियोजना (आईजीएनपी) किया गया।
13. दिसंबर, 1986 में मुख्य नहर (पूगल से मोहनगढ़ जैसलमेर तक 256 किमी.) पूर्ण।
14. 1.01.1987 में द्वितीय चरण की मुख्य नहर में पानी छोड़ा गया। मोहनगढ़ (जैसलमेर) अंतिम छोर तक पानी पहुंचा।
15. 1989 में लूणकरणसर लिफ्ट नहर का नाम कंवरसेन लिफ्ट नहर किया गया।
16. 1992 में इंदिरा गांधी नहर परियोजना प्रथम चरण का कार्य पूर्ण।
17. नवंबर, 2000 में गजनेर, बांगड़सर एवं कोलायत लिफ्ट नहरों के 5 पम्पिंग स्टेशन का उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने किया।

### इंदिरा गांधी नहर परियोजना की पेयजल योजनाएं

इंदिरा गांधी नहर का निर्माण राजस्थान के उत्तरी व पश्चिमी मरू प्रदेश में सिंचाई सुविधाएं एवं पेयजल उपलब्ध कराने के लिए किया गया है। पेयजल उपलब्ध कराने के लिए (आईजीएनपी) की निम्न मुख्य पेयजल परियोजनाएं हैं-

1. **कंवरसेन लिफ्ट परियोजना:** बीकानेर शहर एवं रास्ते के 228 गांवों (बीकानेर एवं श्रीगंगानगर जिले के) को पेयजल तथा बीकानेर जिले की लूणकरणसर तहसील में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में 5 जुलाई, 1968 को इस लिफ्ट नहर का प्रारम्भ तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया ने किया। यह लिफ्ट नहर मुख्य नहर के बिरधवाल हैड से निकाली गई है तथा 151.64 किमी लम्बी है। योजना की सातों लिफ्ट नहरों में इसका निर्माण सर्वप्रथम किया गया था। इसका प्रारंभिक नाम बीकानेर-लूणकरणसर लिफ्ट नहर योजना था, जिसे 1989 में बदल कर कंवरसेन लिफ्ट नहर योजना कर दिया गया। यह नहर 1976 में पूर्ण हुई और इसकी कुल 179.72 किमी लम्बी वितरण प्रणाली

मार्च, 1989 में बनकर पूर्ण हुई। यह बीकानेर शहर की जीवन रेखा है। इसमें बीकानेर शहर की जल की मांग की पूर्ति के लिए बीछवाल में जल भण्डारण के लिए विशाल जलाशय का निर्माण किया गया है।

2. **राजीव गांधी लिफ्ट नहर योजना (जोधपुर लिफ्ट नहर योजना):** जोधपुर शहर एवं रास्ते के 158 गांवों में पीने के लिए इंदिरा गांधी नहर का पानी उपलब्ध कराने के लिए यह योजना प्रारम्भ की गई। इस योजना में जल मुख्य नहर की आरडी 1109 से लिया गया है। इसमें 176 किमी लम्बी नहर, 30 किमी लम्बी पाइप लाइन एवं 8 पम्पिंग स्टेशन हैं। इनसे पानी कुल 219 मीटर तक ऊंचा उठाया गया है। बाद में इसका नाम परिवर्तित कर राजीव गांधी

जलोत्थान नहर परियोजना कर दिया गया। यह परियोजना की सबसे लम्बी लिफ्ट नहर है।

3. **आपणी योजना (गंधेली-साहवा परियोजना):** हनुमानगढ़, चूरू एवं झुंझुनू जिलों के कस्बों एवं गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा गांधी नहर की नोहर साहवा लिफ्ट स्कीम से यह योजना आपणी योजना के नाम से जर्मनी की कम्पनी के वित्तीय सहयोग से प्रारंभ की गई। इसके प्रथम चरण में चूरू एवं हनुमानगढ़ जिलों के 370 गांव एवं तीन कस्बों में जल उपलब्ध कराया गया। द्वितीय चरण में चूरू व झुंझुनू जिले के गांवों एवं कस्बे पेयजल का उपयोग कर सकेंगे। ●



## नहरबंदी के बाद बनेगी बात

### रिलाइनिंग पर आएगी 250 करोड़ की लागत

पिछले कई वर्षों की भांति इस बार भी राजस्थान की मरु गंगा यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना में बंदी ली गई है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 21 मार्च 2022 से शुरू हुई नहरबंदी तकरीबन साठ दिनों तक प्रभावी रहेगी जबकि श्रीगंगानगर जिले की जीवन्रेखा यानि गंगनहर में 5 से लेकर 20 अप्रैल तक नहरबंदी रही। दोनों नहरों में बंदी के मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा समय रहते पेयजल के पर्याप्त इंतजाम

किए गए। नहरबंदी के बाद दोनों नहरों में पेयजल और सिंचाई के लिए अतिरिक्त पानी मिलने की उम्मीद है।

नहरी जिलों के हिसाब से देखें तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना या गंगनहर में बंदी होना नया नहीं है, लेकिन इस नहरबंदी की अच्छी बात ये है कि अबकि बार राजस्थान के अलावा पंजाब के हिस्से में भी एक साथ रिलाइनिंग करवाई गई। इससे दोनों राज्यों के किसानों को दोगुना फायदा होगा। एक तो अलग-अलग समय में बंदी नहीं होने से नहर में पानी की उपलब्धता रहेगी। दूसरा- रिलाइनिंग के बाद नहर में पानी की मात्रा बढ़ेगी। जल संसाधन (उत्तर) संभाग हनुमानगढ़ के मुताबिक 250 करोड़ रुपये की लागत से इंदिरा गांधी नहर के राजस्थान हिस्से में रिलाइनिंग कार्य होंगे। 235 अभियंताओं की टीम नियमित रूप से रिलाइनिंग कार्य की निगरानी करेगी जबकि क्वालिटी कंट्रोल के अधिकारी रिलाइनिंग में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की जांच करेंगे।

नहरबंदी को लेकर पंजाब सरकार की सहमति मिलने के बाद दोनों राज्यों में एक साथ इंदिरा गांधी नहर परियोजना में रिलाइनिंग कार्य करवाए जा रहे हैं। इससे जहां एक ओर नहर के पानी में छीजत में कमी आएगी, वहीं मानसून अवधि में राजस्थान के किसानों को अतिरिक्त पानी मिल सकेगा। अभी लाइनिंग डैमेज होने से नहर में लगभग 11000-11500 क्यूसेक पानी प्रवाहित होता है जबकि क्षमता



18500 क्यूसेक है। इस वजह से हरिके बैराज के डाउन स्ट्रीम में बरसात का पानी ज्यादा आने के बावजूद इंदिरा गांधी नहर में ज्यादा पानी नहीं लिया जा सकता। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा और रिलाइनिंग के बाद अधिक पानी मिलेगा, जिससे टेल के अंत तक के किसानों को पानी मिल सकेगा। साथ ही राजस्थान के लाखों किसान सिंचाई सुविधा के रूप में लाभान्वित होंगे। नहर में 25 अप्रैल से पूर्ण बंदी ली गई जबकि इससे पहले आंशिक बंदी रही। 20 मई तक प्रस्तावित 26 दिनों की पूर्ण बंदी में इंदिरा गांधी मुख्य नहर और इंदिरा गांधी कैनाल में 68 किलोमीटर के हिस्से में रिलाइनिंग करवाई जा रही है। पंजाब सरकार 52 किलोमीटर में रिलाइनिंग करवा रही है। बंदी के दौरान इंदिरा गांधी नहर के राजस्थान की सीमा (आरडी 555) से बिरधवाल हैड (आरडी 200) तक 93 स्थानों पर 250 करोड़ रुपये से रिलाइनिंग संबंधी कार्य करवाए जाने हैं। रिलाइनिंग होने के बाद हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, चूरू, झुंझुनूं, सीकर और नागौर सहित प्रदेश के 10 जिलों को फायदा होगा। विभाग के अनुसार इस नहरी पानी से गंगानगर में 2 लाख 67 हजार 181 हैक्टेयर और हनुमानगढ़ में 1 लाख 15 हजार 461 हैक्टेयर क्षेत्रफल सहित कुल 4 जिलों के 16 लाख 17 हजार हैक्टेयर में सिंचाई होती है।

इंदिरा गांधी नहर से पहले गंगानहर में बंदी ली गई। गंगानहर में 5 से 20 अप्रैल तक बंदी रखकर पंजाब राज्य में बीकानेर कैनाल व राजस्थान के हिस्से में सफाई करवाई गई। पंजाब में बीकानेर कैनाल की 45 आरडी से खखां हैड तक डिसिल्टिंग, बर्म कटिंग, क्षतिग्रस्त लाइनिंग की मरम्मत व पटड़ा सुदृढीकरण जैसे काम हुए। बीकानेर कैनाल की 45 आरडी से राजस्थान बॉर्डर के खखां हैड तक नहर के पुलों के नीचे कचरा और मिट्टी होने से नहर में पूरी क्षमता से पानी प्रवाहित नहीं हो रहा था। लाइनिंग भी जगह-जगह से क्षतिग्रस्त थी। इसी आवश्यकता को देखते हुए पंजाब में नहरी महकमे के अधिकारियों से बात कर बंदी की कार्ययोजना तैयार की गई।

गत वर्ष भी नहरबंदी के दौरान पंजाब क्षेत्र की बीकानेर कैनाल पर बने पुलों के नीचे से फंसा कचरा निकालकर सफाई की गई थी। कई जगहों से सिल्ट भी निकाली गई, लेकिन इस अवधि के दौरान नहर में नियमित रूप से पानी प्रवाहित होने की वजह से पुल फिर से जाम हो गए। इसके चलते नहर में पानी पूरी गति से प्रवाहित नहीं हो सका। अब बंदी के दौरान गंगानहर में खखां हैड से पीएस हैड तक मुख्य फीडर की सफाई और खखां, शिवपुर, कालूवाला व नेतेवाला हैडों की मरम्मत भी करवाई गई।

इंदिरा गांधी नहर में कुल बंदी 60 दिन की थी, जिसमें से 30 दिन आंशिक बंदी रही। पेयजल विभाग व जल संसाधन विभाग द्वारा बंदी से पूर्व ही भण्डारण व पौण्डिंग की तैयारी की गई। गत वर्ष नहरबंदी के



दौरान 30 दिनों में 47 किलोमीटर रिलाइनिंग का काम हुआ था जबकि इस बार बंदी में 68 किलोमीटर रिलाइनिंग कार्य किया जाना है।

नहरबंदी को लेकर मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत और मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा भी बेहद गंभीर हैं। राज्य सरकार द्वारा लगातार वीसी के माध्यम से अधिकारियों से संबंधित जानकारी लेते हुए निर्धारित समयावधि में उक्त कार्य पूर्ण करने के साथ-साथ पेयजल की निर्बाध आपूर्ति रखने के निर्देश दिए हैं।

इसी की बदौलत जिले की पेयजल परियोजनाओं में भण्डारण की जिम्मेदारी पेयजल विभाग तथा जनता जल योजना की परियोजनाओं में भण्डारण व्यवस्था की जिम्मेदारी विकास अधिकारी संभाल रहे हैं जबकि ग्राम स्तर पर पटवारी, जलदाय, पेयजल तथा ग्राम सेवक जल स्रोतों में पर्याप्त भण्डारण की व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। पेयजल परियोजना लालगढ़, जैतसर के अलावा अन्य योजनाओं में भी आवश्यकता पड़ने पर साइफन से अतिरिक्त पानी लेकर डिगियों में जल भण्डारण किया गया है।

जिला कलक्टर ने आमजन से नहरबंदी के दौरान पानी का उपयोग सावधानीपूर्वक करने की अपील भी जारी करते हुए कहा है कि उपलब्ध पानी का सदुपयोग करते हुए अपनी निजी डिगियों में भी पेयजल का भण्डारण सुनिश्चित किया जाए। बंदी के दौरान स्वच्छ पेयजल मिले, इसके लिए पेयजल विभाग क्लोरीन इत्यादि की व्यवस्था कर शुद्ध पेयजल आपूर्ति कर रहे हैं। नहरबंदी के दौरान टेलों तक पानी पहुंचे, इसके लिए भी जल संसाधन व जलदाय विभाग समन्वय बनाकर काम कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक ने भी आश्वस्त किया है कि नहरी पानी की चोरी न हो।

दोनों नहरों में बंदी की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि संबंधित कार्य पूरे होने के बाद पेयजल-सिंचाई के लिए कितना पानी मिलेगा। इस बार की बंदी में हुए कार्यों से आमजन की पेयजल संबंधी समस्याएं दूर हो सकेंगी और किसानों को अपनी फसलों को पकाने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी भी मिलता रहेगा। ●

# पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना नवनेरा बांध ले रहा है मूर्त रूप प्रदेश के 13 जिलों के लिए भगीरथी साबित होगी परियोजना

**प**ूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में पेयजल एवं औद्योगिक जल की उपलब्धता के लिए राज्य सरकार द्वारा चम्बल बेसिन की विभिन्न सब बेसिनों को जोड़कर पानी के सदुपयोग के लिए शुरू की गई पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का नवनेरा बांध मूर्त रूप लेने जा रहा है। कोटा जिले के दीगोद उपखण्ड के ऐबरा गांव के पास कालीसिंध नदी पर निर्माणाधीन बांध के पूर्ण हो जाने पर माह जून से अक्टूबर तक औसतन 3387.25 मिलियन घन मीटर पानी डायवर्जन किया जाना प्रस्तावित है। इस परियोजना के लिए राज्य सरकार द्वारा 1595.06 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति तथा 1316.32 करोड़ की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति 20 जनवरी 2022 को जारी की जा चुकी है।

पूर्वी राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य



हरिओमसिंह गुर्जर

उपनिदेशक, जनसम्पर्क, कोटा

बाढ़ एवं सूखा नियन्त्रण है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना से पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, दौसा, जयपुर, अजमेर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां व झालावाड़ के विभिन्न कस्बों एवं शहरों में पेयजल एवं औद्योगिक जल की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है। जल संसाधन विभाग के अनुसार “परियोजना से धौलपुर व सवाईमाधोपुर जिले में लगभग 2 लाख हैक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाने के साथ मार्ग में आने वाले विभिन्न तालाबों, जलाशयों के पूर्व सिंचित क्षेत्र की लगभग 2.30 लाख हैक्टेयर भूमि में सिंचाई के लिए अतिरिक्त जल भण्डारण क्षमता सुनिश्चित करना परियोजना का महत्वपूर्ण पहलू है।”

यह परियोजना इन जिलों में पानी के क्षेत्र में क्रान्तिकारी पहल साबित होकर भगीरथी के समान साबित होगी। इसके मूर्त रूप लेने से पूर्वी राजस्थान में पानी के अभाव में खाली रह रहे बांधों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी तथा इस पानी के भण्डारण से चम्बल व यमुना नदी में जा रहे अधिशेष वर्षा जल को रोका जाकर उत्पन्न होने वाली बाढ़ की स्थिति को भी नियन्त्रित किया जा सकेगा। जिस प्रकार पश्चिमी राजस्थान में इन्दिरा गांधी नहर से परिवर्तन आया है इसी प्रकार पूर्वी राजस्थान में इस परियोजना का पानी पहुंचने से कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र में पानी की उपलब्धता होने से क्रान्तिकारी परिवर्तन होंगे। पेयजल की समस्या से स्थाई निजात मिल सकेगी।

## ऐसा होगा बांध

नवनेरा बांध की कुल भराव क्षमता 226.65 मिली घन मीटर होगी जिसमें 54 मिली घन मीटर पानी पेयजल के लिए आरक्षित है जिसमें जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की हिस्सा राशि 444.62 करोड़ है जिससे हाड़ौती के 4 कस्बे (इटावा, कापरेन, केशोराय पाटन, लाखेरी) एवं 752 गांव लाभान्वित होंगे।

बैराज में कुल 27 रेडियल गेट 15 मीटर x 16 मीटर के होंगे। बैराज की कुल लम्बाई 1404 मीटर है जिसमें 522 मीटर का कंक्रीट स्लीप-वे ऑवरफ्लो के लिए, 40 मीटर का नोन ऑवर फ्लो प्रोटेक्शन तथा 842 मीटर का नवनेरा बांध होगा। बांध के डूब क्षेत्र में कुल 3112.15 हैक्टेयर भूमि आ रही है जिसमें 656.347 हैक्टेयर वन भूमि एवं 495.16 हैक्टेयर निजी भूमि है। वन भूमि में कोटा जिले की 580.938 हैक्टेयर तथा बारां जिले की 75.409 हैक्टेयर है जिसकी स्वीकृति केन्द्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा 25 अप्रैल 2022 को अंतिम रूप से जारी की जा चुकी है। परियोजना के क्षेत्र में आ रही निजी खातेदारों की भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है।

## बांध निर्माण की स्थिति

नवनेरा बांध परियोजना के निर्माण का कार्यादेश 601.02 करोड़ रुपये का जारी कर दिया गया है तथा अक्टूबर, 2023 को कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। बांध के निर्माण हेतु मूलभूत संरचनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। बांध के निर्माण में ओवर फ्लो एवं नोन ओवर फ्लो के कुल 30 ब्लॉक में से 27 ब्लॉक में सफाई/कंक्रीट कार्य प्रगतिरत हैं तथा एक ब्लॉक से नदी के जल प्रवाह की निकासी की जा रही है। इस प्रकार लगभग 70 प्रतिशत कार्य किया जा चुका है। बांध के मैकेनिकल कार्य में रेडियल गेटों का निर्माण कार्य प्रगति पर है जिसमें 27 में से 27 गेटों के वर्कशॉप कार्य पूर्ण कर, 7 रेडियल गेटों का साइट पर इंसपेक्शन कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं 33 में से 33 स्टॉप लॉक वर्कशॉप कार्य पूर्ण कर लिया गया है।



## पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना

पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, राजस्थान प्रदेश की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसमें मानसून के दौरान चम्बल बेसिन के सहायक नदी बेसिनों (पार्वती, कालीसिंध, कुन्नू, कूल, मेज) में उपलब्ध अधिशेष जल को न्यून जल वाले नदी बेसिनों में जल अपवर्तन हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर केन्द्रीय जल आयोग को प्रेषित की जा चुकी है। परियोजना की अनुमानित लागत रुपये 37247.12 करोड़ है।

## उद्देश्य

परियोजना के अन्तर्गत उपलब्ध जल 3510 मिलियन घन मीटर में से लगभग 49 प्रतिशत; 1723.5 मिलियन घन मीटर शुद्ध जल का पेयजल हेतु प्रावधान रखा गया है, जिसके द्वारा राजस्थान के 13 जिलों (राज्य की लगभग 40 प्रतिशत जनसंख्या) यथा झालावाड, बारां, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर एवं धौलपुर में वर्ष 2051 तक पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी।





परियोजना के अन्तर्गत निर्मित की जाने वाली फीडर कैनाल से पास के पूर्व निर्मित 26 वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को पानी दिया जाना प्रस्तावित है, जिससे उक्त बांधों में जल उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी एवं पूर्व सृजित 0.8 लाख हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र पुनर्स्थापित किया जा सकेगा।

परियोजना द्वारा 2 लाख हैक्टेयर नये क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई पद्धति से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जाना संभव होगा।

परियोजना अन्तर्गत उद्योगों एवं दिल्ली मुम्बई औद्योगिक गलियारा के उपयोग हेतु 286.4 मिलियन घन मीटर पानी उपलब्ध कराया जा सकेगा।

### मुख्य घटक

परियोजना अन्तर्गत 6 बैराज तथा 1 बांध बनाया जाना प्रस्तावित है। बैराज का निर्माण मुख्यतः जल अपवर्तन हेतु एवं बांध का निर्माण जल का संग्रहण करने के लिए होगा।

1. कुन्नू बैराज: कुन्नू नदी पर राजस्थान मे शाहबाद तहसील, जिला बारां में भराव क्षमता 56.97 एम.सी.एम.
2. रामगढ बैराज: कूल नदी पर राजस्थान में किशनगंज तहसील, जिला बारां में भराव क्षमता 50.49 एम.सी.एम.
3. महलपुर बैराज: पार्वती नदी पर राजस्थान में मंगरौल तहसील, जिला बारां में भराव क्षमता 162.20 एम.सी.एम.
4. नवनेरा बैराज: कालीसिंध नदी पर राजस्थान में पीपलदा

तहसील, जिला कोटा में भराव क्षमता 226.65 एम.सी.एम. का बैराज निर्मित किया जाना है। परियोजना अन्तर्गत इस बैराज की भराव क्षमता सबसे अधिक है। अपवर्तन हेतु महत्त्वपूर्ण बैराज होने से इसका निर्माण कार्य आरम्भ किया जा चुका है।

5. मेज बैराज: मेज नदी पर इन्द्रगढ़ तहसील, जिला बूंदी में भराव क्षमता 50.80 एम.सी.एम.
6. राठौड़ बैराज: बनास नदी पर चौथ का बरवाडा तहसील, जिला सवाईमाधोपुर में भराव क्षमता 143.09 एम.सी.एम.
7. डूंगरी बांध: बनास नदी पर तहसील खण्डार, जिला सवाईमाधोपुर में 2099 एम.सी.एम. भराव क्षमता का बांध बनाया जाना है जो "पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना" अन्तर्गत जल संग्रहण हेतु मुख्य बांध होगा। इस बांध में संग्रहित जल से परियोजना अन्तर्गत सूक्ष्म सिंचाई पर आधारित 2 लाख हैक्टेयर नया सिंचित क्षेत्र विकसित किया जायेगा।

परियोजना के अन्तर्गत फीडर/नहर तंत्र की कुल लम्बाई 1268 कि.मी. है। जिसमें से ग्रेविटी फीडर की लम्बाई 965 कि.मी., टनल की लम्बाई 4.5 कि.मी., पम्पिंग मैन की लम्बाई 141 कि.मी. व नेचुरल स्ट्रीम की लम्बाई 157.5 कि.मी. है। परियोजना में 15 स्थानों पर पम्पिंग स्टेशन निर्मित किये जाने है। ●

## प्रदेश में बदलाव का उद्यम

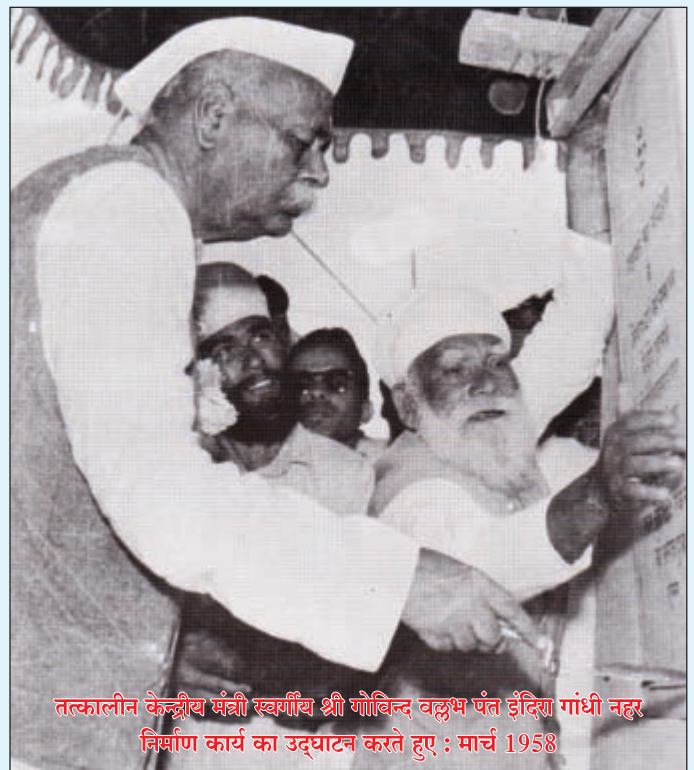
**इं**दिरा गांधी नहर परियोजना प्रकृति की असीम विषमताओं से मनुष्य के अदम्य साहसपूर्ण संघर्ष से उत्पन्न सृजनात्मकता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस अत्यन्त महत्वाकांक्षी परियोजना से पश्चिमी राजस्थान की सदियों से प्यासी मरुभूमि दूरस्थ हिमालय स्थित रावी एवं व्यास नदियों के जल से सिंचित होकर जीवंत हुई है तथा करोड़ों निवासियों को पेयजल उपलब्ध हुआ है।

मरु प्रदेश की जीवनदायिनी कही जाने वाली नहर का उद्गम पंजाब राज्य में स्थित हरिके बैराज से है, जहां से 204 कि.मी. लम्बी फीडर नहर (170 कि.मी. पंजाब, हरियाणा व 34 कि.मी. राजस्थान) निकलती है। राजस्थान में यह नहर हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती है। इन्दिरा गांधी फीडर नहर के अंतिम छोर से 445 कि.मी. लम्बी इन्दिरा गांधी मुख्य नहर आरम्भ होती है, जो गंगानगर व बीकानेर जिलों से निकलती हुई जैसलमेर जिले में मोहनगढ़ के पास समाप्त होती है। इस परियोजना हेतु वर्ष 1981 के अन्तर्राज्यीय समझौते अन्तर्गत रावी व्यास नदियों के अधिशेष जल में से राजस्थान को आवंटित 8.60 एम.ए.एफ.में से 7.59 एम.ए.एफ. पानी का प्रावधान निर्धारित है।

इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो वर्ष 1984 से पूर्व राजस्थान नहर के नाम से जानी जाती थी, का शुभारम्भ वर्ष 1958 में किया गया था। इसके स्वरूप व आकार में समय-समय पर अनेक परिवर्तन हुए।

जितेन्द्र दीक्षित

सचिव, इन्दिरा गांधी नहर बोर्ड





सर्वप्रथम तत्कालीन बीकानेर रियासत के मुख्य अभियन्ता श्री आर.वी. कंवरसेन ने 1948 में परियोजना का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया, जिसमें सतलुज तथा व्यास नदियों के संगम से तीन कि.मी. नीचे (डाउन स्ट्रीम में) एक बैराज बनकर बीकानेर रियासत तथा थार मरुस्थल के अन्य क्षेत्रों के 31.75 लाख एकड़ क्षेत्र को सिंचित करने का प्रावधान था।

राजस्थान राज्य का निर्माण होने के पश्चात् सरकार द्वारा वर्ष 1954-57 में परियोजना क्षेत्र का विस्तृत सर्वेक्षण करवाकर परियोजना का प्राक्कलन बनाया गया। पंजाब में बनाये गये हैड वर्क्स की शेयर कॉस्ट सहित इसकी लागत 66.67 करोड़ रुपये थी। यह प्राक्कलन 22.07.57 को स्वीकृत किया गया। इसमें 3.64 लाख हैक्टेयर में पेरीनियल सिंचाई (रबी व खरीफ में) तथा 9.94 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में नॉन-पेरीनियल सिंचाई (मात्र खरीफ में) प्रस्तावित थी। उस समय मात्र पंजाब में फीडर नहर को पक्का तथा राजस्थान में मुख्य व अन्य नहरों को कच्चा रखा जाना प्रस्तावित था।

परियोजना का शिलान्यास मार्च, 1958 को भारत के तत्कालीन गृह मंत्री श्री गोविन्द वल्लभ पंत के कर कमलों द्वारा किया गया तथा लगभग 3 वर्ष पश्चात् 11 अक्टूबर, 1961 को इसकी नौरंगदेसर वितरिका मे भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्ण द्वारा प्रथम बार जल प्रवाह का शुभारम्भ किया गया।



वर्ष 1960 में भारत-पाकिस्तान के मध्य हुए सिन्धु जल समझौते के पश्चात् अधिक पानी उपलब्धता सुनिश्चित होने पर समय-समय पर परियोजना के स्वरूप व आकार के सम्बन्ध में निर्णय किये गये। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1963, 1970, 1976, 1983, 1984, 1987, 1993, 1995, 1997, 2000 में लिये गये निर्णयों / परियोजना प्राक्कलनों के अनुसार परियोजना में कुल 19.63 लाख हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र (5.53 लाख प्रथम चरण व 14.10 लाख हैक्टेयर द्वितीय चरण) उपलब्ध कराया जाना था। किन्तु वर्ष 2005 में राज्य सरकार द्वारा सिंचाई हेतु पानी की उपलब्धता की समीक्षा की गई तथा पंजाब द्वारा राजस्थान के हिस्से का 0.6 एम.ए.एफ पानी नहीं दिये जाने व पेयजल हेतु पानी की मांग में वृद्धि के कारण सिंचाई जल की उपलब्धता में कमी के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में परियोजना में 16.17 लाख हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र (प्रथम चरण 5.46 लाख हैक्टेयर + द्वितीय चरण 10.71 लाख हैक्टेयर) ही प्राथमिकता से सिंचाई हेतु सृजित करने का निर्णय लिया गया। लक्ष्य अनुसार सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई गई है।



### वर्तमान स्थिति

#### प्रथम चरण :-

हरिके बैराज से पूंगल (बीकानेर जिला) तक कुल 393 कि.मी. (फीडर 204, मुख्य नहर 189) लम्बी मुख्य नहर तथा तत्सम्बन्धी वितरण प्रणाली (साहवा लिफ्ट प्रणाली के अतिरिक्त) को प्रथम चरण कहा जाता है। परियोजना के 16.17 लाख हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र अनुसार इस चरण में 4.84 लाख हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र प्रवाह व 0.62 लाख हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र कंवरसेन लिफ्ट नहर प्रणाली में, कुल 5.46 लाख हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र है। इस चरण में अन्य मुख्य नहर प्रणालियां नौरंगदेसर वितरिका, रावतसर शाखा, अनुपगढ़ शाखा, सूरतगढ़ शाखा, पूंगल शाखा इत्यादि हैं। इस चरण का समस्त कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है तथा इसके अधिकांश भाग के संचालन एवं रखरखाव की व्यवस्था का उत्तरदायित्व (कंवरसेन लिफ्ट नहर के अतिरिक्त) जल संसाधन विभाग को सौंपा जा चुका है।

इन्दिरा गांधी फीडर नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1960 के दशक में किया गया था तब से लगातार जल प्रवाह के कारण इसकी लाइनिंग क्षतिग्रस्त हो जाने से इसकी जल प्रवाह क्षमता 18500 क्यूसेक के





नहर में पानी की आवक

स्थान पर 11500-12000 क्यूसेक रह गई। इसके अतिरिक्त इसके आसपास के क्षेत्र में जल प्लावन के कारण कृषि नुकसान को रोकने के लिए जनवरी 2019 में राजस्थान, पंजाब व केन्द्र सरकार के मध्य एक समझौता किया जाकर उक्त नहर की रीलाइनिंग का कार्य किया जा रहा है। इसी प्रकार प्रथम चरण की अन्य नहरों के निर्माण को भी लगभग 35 से 60 वर्ष व्यतीत हो जाने के कारण लगातार जल प्रवाह से ये नहरों क्षतिग्रस्त हो गई। अतः इनके भी रीलाइनिंग व जीर्णोद्धार का कार्य राजस्थान वाटर सेक्टर री-स्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट अन्तर्गत जल संसाधन विभाग द्वारा करवाया गया।

### द्वितीय चरण

इन्दिरा गांधी मुख्य नहर की बुर्जी 620 से अन्तिम छोर का क्षेत्र एवं तत्सम्बन्धी वितरण प्रणाली (चौधरी कुम्भाराम आर्य लिफ्ट सहित) द्वितीय चरण में है। इस चरण में मुख्य नहर की लम्बाई 256 किलोमीटर है, जो पूगल से मोहनगढ़ (जैसलमेर) तक है। मुख्य नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1986 में पूर्ण किया जा चुका है। परियोजना के 16.17 लाख हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र अनुसार इस चरण में 7.24 लाख हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र प्रवाह व 3.47 लाख हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र 6 लिफ्ट नहर प्रणालियों में है। इस प्रकार द्वितीय चरण का कुल सिंचित क्षेत्र 10.71 लाख हैक्टेयर है। ये सिंचित क्षेत्र नहर निर्माण कार्य पूर्ण कर सिंचाई हेतु उपलब्ध करवाया जा चुका है। 6 लिफ्ट नहर प्रणालिया क्रमशः चौधरी कुम्भाराम आर्य लिफ्ट नहर, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, डॉ. करणी सिंह लिफ्ट नहर, गुरु जम्भेश्वर लिफ्ट

नहर, जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर है। प्रवाह क्षेत्र की मुख्य नहर प्रणालियां दत्तौर वितरिका, बिरसलपुर शाखा, चारणवाला शाखा, नाचना वितरिका, शहीद बीरबल शाखा, सागरमल गोपा शाखा व बाबा रामदेव शाखा इत्यादि है।

वर्तमान में द्वितीय चरण में मुख्यतः लिफ्ट नहर प्रणालियों में प्रेशर सिंचाई प्रणाली विकसित करने व प्रवाह क्षेत्र की नहरों के नवीनीकरण व आधुनिकीकरण कार्य करवाये जा रहे है।

### द्वितीय चरण लिफ्ट योजनाओं में प्रेशर सिंचाई कार्य

परियोजना में सिंचाई हेतु पानी की सीमित उपलब्धता के परिप्रेक्ष्य में लिफ्ट योजनाओं में उपलब्ध जल के अधिकतम व कुशलतम उपयोग हेतु प्रेशर सिंचाई पद्धति विकसित करने का निर्णय किया गया। वर्ष 2007 में 6 लिफ्ट योजनाओं के 27449 हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र में एक स्प्रींकलर पायलट प्रोजेक्ट आरम्भ किया गया। जिसके अन्तर्गत खुले खालों के स्थान पर सिंचित क्षेत्र के चकों में डिगियों, भूमिगत पाइपलाइन व पम्पहाउस का निर्माण किया गया है। नहरों के आउटलेट से फीडर चैनल द्वारा डिगियों में पानी पहुँचाया जाता है। डिगियों पर निर्मित पम्पहाउस द्वारा भूमिगत पाइप लाइनों के माध्यम से काश्तकारों के खेत तक प्रेशर से पानी पहुँचाया जाता है। जहाँ से कृषक स्वयं के फव्वारा/ट्रिप उपकरण लगाकर सिंचाई कर सकते है। पम्प चलाने हेतु विद्युत लाइने बिछाई गई है।

पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के पश्चात् विभाग द्वारा वर्ष 2015-16 में लिफ्ट योजनाओं के शेष 3.20 लाख हैक्टेयर सिंचित

क्षेत्र में भी सिंचाई प्रणाली विकसित करने हेतु भारत सरकार के सी.ए.डी.डब्ल्यू.एम. कार्यक्रम अन्तर्गत प्रोजेक्ट प्रेषित किया गया। भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय द्वारा उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत मार्च, 2016 में रुपये 1658.81 करोड़ के प्रोजेक्ट को 50 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता हेतु स्वीकृति दी गई। स्वीकृति पश्चात विभाग द्वारा 1.68 लाख हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र में कार्य आवंटित कर दिये गये थे, किन्तु वर्ष 2017 में केन्द्र सरकार के नीतिगत निर्णय अनुसार उक्त स्वीकृति प्रभावी नहीं रही। इस कारण उसके पश्चात केन्द्रीय सहायता न मिलने के कारण इन कार्यों की प्रगति रुक गई थी। अतः माह नवम्बर, 2019 में राज्य सरकार द्वारा 865 डिगियों के आवंटित कार्यों में से 468 प्रगतिधीन डिगियों के कार्यों को पूर्ण करने के लिये बजट उपलब्ध कराने की सहमति दी गई। लगभग 450 करोड़ रुपये की लागत से इस कार्य वर्ष 2022-23 में पूर्ण होने पर लगभग 85 हजार हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र में कृषक लाभान्वित होंगे। उपरोक्त आवंटित कार्यों में शेष रही 397 डिगियों सहित अन्य आवश्यक कार्यों को पूर्ण करने हेतु भी 300 करोड़ रुपये का प्रावधान मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा बजट भाषण वर्ष 2022-23 अन्तर्गत किया गया है। शीघ्र ही इन कार्यों को आरम्भ किया जायेगा।

### द्वितीय चरण की नहरों के नवीनीकरण व आधुनिकीकरण कार्य

द्वितीय चरण की नहरों का निर्माण कार्य वर्ष 1975 के दौरान शुरु किया गया था और वर्ष 2004 तक प्रवाह क्षेत्र की अधिकांश नहरों का काम पूरा हो गया था। निरन्तर उपयोग और रखरखाव के लिए पर्याप्त धन की कमी के कारण ये नहरें क्षतिग्रस्त हो गईं, जिसके परिणामस्वरूप अत्यधिक जल हास होता है। इसलिए इंगानप में नहर प्रणालियों के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण की 3 परियोजनायें (बीकानेर संभाग में 2 व जैसलमेर संभाग में 1) वर्ष 2020-21, 2021-22 में नाबार्ड



आर.आई.डी.एफ-XXV, XXVI अन्तर्गत वित्त पोषण से शुरु की गई हैं। बीकानेर संभाग की परियोजनाओं की लागत रुपये 121 करोड़ व और रुपये 134.55 करोड़ तथा जैसलमेर संभाग की परियोजना की लागत 58.42 करोड़ रुपये है। इन कार्यों पर मार्च, 2022 तक 72.92 करोड़ रुपये व्यय हुये है। चारणवाला शाखा के जीर्णोद्धार का कार्य भी नाबार्ड आर.आई.डी.एफ- XXVII अन्तर्गत स्वीकृत हो चुका है जिसे शीघ्र ही आरम्भ करवाया जायेगा।

### परियोजना से लाभ

#### परियोजना के निर्माण से राज्य को लाभ हुए हैं-

1. इस मरुस्थलीय क्षेत्र में जहां कभी पीने के पानी के लिये भी महिलाओं को कई किलोमीटर दूर पैदल जाना पड़ता था, जहां दूर-दूर तक हरियाली का नाम नहीं था वहाँ आज खेतों में फसलें लहलहा रही हैं और पीएचईडी के माध्यम से बीकानेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, चूरू, झुन्झुनूं, नागौर तथा बाड़मेर जिलों के विभिन्न गांवों, कस्बों की लगभग पौने दो करोड़ आबादी को पीने का पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है।
2. यह क्षेत्र खाद्यान्न उत्पादन हेतु राज्य का प्रमुख क्षेत्र बन गया है। विगत 5 वर्षों में परियोजना क्षेत्र में प्रतिवर्ष औसतन लगभग 17.21 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हुई है। वर्ष 2020-21 में लगभग रुपये 700 करोड़ का 40 लाख क्विंटल गेहूं, रुपये 1600 करोड़ का 34 लाख क्विंटल चना, रुपये 3000 करोड़ का 55 लाख क्विंटल सरसों, 1500 करोड़ की 30 लाख क्विंटल मूंगफली तथा 1500 करोड़ की 20 लाख क्विंटल रूई का उत्पादन हुआ है।
3. इस नहर से सूरतगढ़, बरसिंहसर, गुढ़ा, रामगढ़, गिरल, राजवेस्ट (बाड़मेर) की विभिन्न ऊर्जा परियोजनाओं को



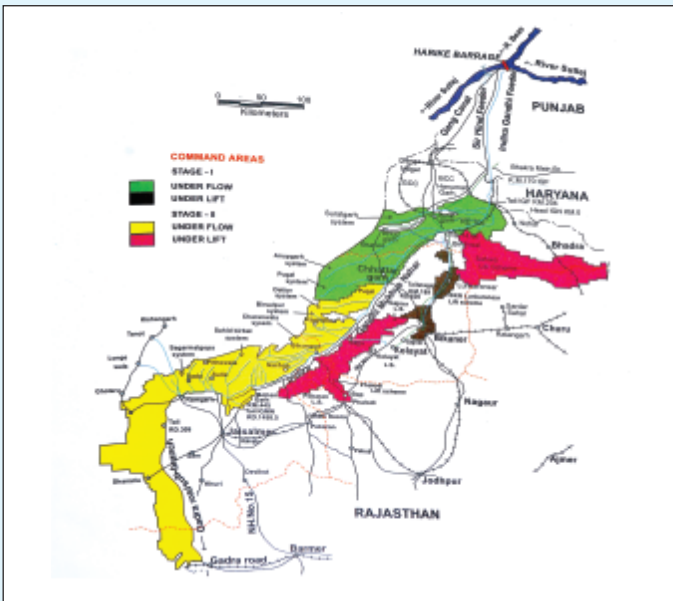
ऊर्जा उत्पादन तथा उद्योगों हेतु पानी उपलब्ध कराया जा रहा है।

4. अन्तरराष्ट्रीय सीमा पर तैनात सैन्य बलों के लिये जल आपूर्ति इसी नहर से होती है।
5. अकाल की स्थितियों की समाप्ति हुई है।
6. इस क्षेत्र में सभी आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि एवं यहाँ के निवासियों की सामाजिक आर्थिक दशा में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

7. क्षेत्र के पशुधन की पेयजल तथा चारे इत्यादि की आवश्यकतापूर्ति तथा रोजगार हेतु अनेक अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।

8. क्षेत्र के भूजल स्तर में वृद्धि हुई है।

परियोजना में नहर प्रणालियों एवं खालों के निर्माण पर अब तक लगभग रुपये 7500 करोड़ व्यय किये गये हैं। जबकि परियोजना से एक वर्ष में मात्र कृषि उत्पादन ही लगभग 8300 करोड़ रुपये हुआ है। पेयजल परियोजनाओं, ऊर्जा संयन्त्रों, उद्योगों को दिये गये पानी के लाभ, इस क्षेत्र के निवासियों के जीवन स्तर में सुधार एवं क्षेत्र के विकास सहित अन्य अप्रत्यक्ष फायदों को देखा जाये तो यह परियोजना राज्य के लिये वरदान सिद्ध हुई है। इसने पश्चिम राजस्थान की जीवन-रेखा बनकर क्षेत्र का कायाकल्प कर दिया है। ●



## मरु प्रदेश से हरित प्रदेश बनने का स्वर्णिम सफर

स्वप्निल कुलश्रेष्ठ स्वाभाविक

स्वतंत्र लेखक, बांसवाड़ा

**अ** रावली पर्वतमाला के पश्चिम में अवस्थित थार का मरुस्थल इतना विशाल है कि जिससे सम्पूर्ण राजस्थान प्रदेश की शुष्क अथवा मरुप्रदेश की छवि बनी हुई है। राज्य के बारह बड़े जिले बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जालौर, पाली, नागौर, चूरू, झुंझुनूं, सीकर आदि इसी के अंतर्गत आते हैं। राजस्थान प्रदेश में थार मरुस्थल का 62 प्रतिशत हिस्सा आता है, वहीं 40 प्रतिशत जनसंख्या यहां निवासरत हैं।

आज के परिप्रेक्ष्य में यदि बात की जाए तो वर्ष 1947 की आजादी और आजादी के बाद के संविधान निर्माण के वक्त प्रत्येक राज्य के हित और खुद राज्य की जनता के विकास के बारे में विभिन्न पहलुओं पर गौर किया गया था। भारतीय गणतंत्र के लागू होने के साथ ही पहली पंचवर्षीय योजना कृषि किसानों पर केंद्रित थी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सदैव किसान हितैषी रहे। विभिन्न केंद्रीय परियोजनाओं के माध्यम से उन्होंने किसानों के हित, उनकी मूलभूत आवश्यकता जल, उपजाऊ ज़मीन पर बहुत जोर दिया, इसीलिए तो अपने शासन के 17 वर्षों तक महात्मा गांधी के स्वप्नों के ग्रामीण भारत को सशक्त और मजबूत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। फिर उनकी इसी परंपरा को आगे बढ़ाया जय जवान - जय किसान का नारा देने वाले महानतम व्यक्तित्व श्री लालबहादुर शास्त्री, प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री राजीव गांधी जैसे देश के नेतृत्वकर्ताओं ने, वहीं इनके दूरदर्शी विचारों को राजस्थान राज्य में मूर्त रूप दिया पूर्व मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया और श्री हरिदेव जोशी

ने, जिनकी बदौलत आज राजस्थान जल संसाधन के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य कर रहा है। इस पथ को आदर्श मान वर्तमान मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान की मरुभूमि को हरितभूमि बनाने के प्रयास सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ रहे हैं।

कहते हैं जिसके पत्थर के पैर हो वही यहां टिक सकता है। यही राजस्थान का एक पहलू है, जो दुनिया में इसकी छवि मरुस्थल की बनाता है। बावजूद इसके प्रदेश का उजियारा पक्ष अभी तक दुनिया से अछूता है, क्योंकि सही मायनों में दूसरा पहलू ही है जो अनाज उत्पादन में राज्य को भारत के शीर्ष 5 राज्यों में जगह देता है। खनिज हो या पशुधन सब में प्रदेश उन्नीस कहीं नहीं है और जिसका मुख्य आधार है जल।

राजस्थान के लोगो ने जल प्रबंधन और नहरीतंत्र के अलावा वैश्विक स्तर के जो बांध बनाये है, वही इस प्रदेश की हरित यात्रा के संवाहक हैं और ये करने वाले कुछ बिरले अनसँग हीरोज हैं, जिन्होंने राजस्थान की भूमि को जलतंत्र की शिराओं और धमनियों का वरदान दिया है। उनमें से कुछ जैसे श्री हरिप्रसाद कुलश्रेष्ठ, श्री प्रद्युम्न कुमार शर्मा (लाइजन् प्रकोरमेंट अधिकारी चंबल व माही परियोजना), श्री ए. के. चार, श्री रामनारायण चौधरी, श्री गोपाल चौधरी, श्री बी.के.मेहरा (मुख्य अभियंता) आदि हैं जिन्होंने माही, चंबल, राजस्थान कैनाल से लेकर कई परियोजनाओं में नींव के पत्थर के रूप में अपनी मेहनत के



पसीने से आहुति दी है।

जल की उपलब्धता के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। जल का उपयोग पेयजल, दैनिक घरेलू कार्य, सिंचाई व उद्योग आदि कार्यों में किया जाता है। जल के समस्त स्रोत जल संसाधन कहलाते हैं। राजस्थान के मुख्य जल स्रोतों में झीलें, नदियाँ और उन पर बने बाँध व नहरें, तालाब, कुएँ एवं नलकूप आदि हैं। नदियों पर बाँध बनाने से जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, पेयजल, वृक्षारोपण, भूमिगत जल स्तर में वृद्धि, बाढ़ नियन्त्रण, मृदा अपरदन और पर्यटन आदि कई प्रकार के उद्देश्य पूरे होते हैं। इन्हीं कारणों से इन्हें बहुउद्देशीय परियोजनाएँ भी कहा जाता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने इन नदी घाटी परियोजनाओं के महत्त्व को देखते हुए इन्हें 'आधुनिक भारत के मंदिर' कहा है। राजस्थान में चम्बल परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना, बीसलपुर परियोजना एवं सरदार सरोवर परियोजना प्रमुख नदी घाटी आदि परियोजनाएँ अपने गौरवशाली गाथाओं और इनके निर्माणकर्ताओं को जीवंत किये हुए हैं।

इनके अतिरिक्त राज्य में पाली जिले में जवाई नदी पर जवाई परियोजना, डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर सोम कमला आम्बा परियोजना, उदयपुर जिले में मानसी वाकल तथा प्रतापगढ़ जिले में जाखम नदी पर जाखम परियोजना भी हैं। जल संसाधन एवं जल संरक्षण के आधुनिक तरीकों में बाँध बनाना सबसे प्रमुख हैं और यही थातियां प्रदेश को अनाज और खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाती है। इसके अलावा जहाँ जल की उपलब्धता कम है, वहाँ संरक्षण के द्वारा लोगो ने जल प्रबंधन को एक दिशा दी है, जो वैश्विक स्तर पर अनुकरणीय हो सकती है। जल संरक्षण हमारा प्रथम दायित्व है। वैसे तो राजस्थान के लोगों के रक्त में वीरता, आतिथ्य और जल संरक्षण घुला हुआ है। फिर भी नयी पीढ़ी के प्रत्येक नागरिक को जल संरक्षण के लिए सरकार और प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि हमें जलाशयों में घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट नहीं डालना चाहिए। पेयजल स्रोतों के निकट स्नान आदि नहीं करना चाहिए। इनके साथ-साथ जल संचयन, जनसंख्या नियंत्रण, सिंचाई की उन्नत विधियों के प्रयोग, वृक्षारोपण में वृद्धि, भूमिगत जल का विवेकपूर्ण उपयोग और जल का पुनः उपयोग आदि प्रयत्नों से जल का संरक्षण किया जाना अति आवश्यक है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों से जल को नहरों के द्वारा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पहुँचा कर जन जीवन और उद्योगों के लिये अनुकूल परिस्थितियाँ सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है।

'रूफ टॉप जल संचयन' विधि में घर की छत पर गिरे वर्षा के जल को घर के नीचे बने कुएं में एकत्र किया जाता है। वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक द्वारा वर्षा के व्यर्थ बहते जल को भूमिगत किया जाता है। पश्चिमी राजस्थान में प्राचीन समय से ही यहाँ के निवासी टाँका, खडीन, जोहड़ आदि का निर्माण कर वर्षा जल का संग्रहण एवं संरक्षण करते हैं। इन जल संसाधन तकनीकों को वृहद् स्तर पर अपनाने की अधिक आवश्यकता है, जिससे राजस्थान की धरा को मरुप्रदेश की छवि से हटकर एक नया नाम मिले 'हरित प्रदेश'। ●





## गांव-ढाणी तक पहुंच रहा पेयजल

**दे**श के अन्य राज्यों के मुकाबले राजस्थान में केवल 1.16 प्रतिशत सतही जल एवं 1.7 प्रतिशत भूजल संसाधन ही उपलब्ध हैं। देश के क्षेत्रफल का 10.45 प्रतिशत हिस्सा राजस्थान में है तथा जनसंख्या की दृष्टि से भारत की 5.5 प्रतिशत जनता राजस्थान प्रदेश में निवास करती है। राज्य में सतही जल एवं वर्षा जल की कमी के कारण औद्योगिक विकास, खाद्यान्न एवं कृषि उत्पादन तथा स्वच्छ एवं अबाध पेयजल के लिए भूजल संसाधनों पर निर्भरता बहुत अधिक है। प्रदेश में करोड़ों वर्षों से संचित भूजल का स्तर अत्यधिक दोहन से चिन्ताजनक स्थिति पर आ गया है। भूजल के 69 प्रतिशत ब्लॉक अति दोहित, 25 ब्लॉक क्रिटिकल एवं 29 ब्लॉक अर्ध क्रिटिकल हैं। भूजल की गुणवत्ता भी लगातार खराब होती जा रही है। प्रदेश के एक बड़े भू-भाग में भूजल पीने योग्य नहीं है, देश के 98 प्रतिशत लवणता प्रभावित एवं 89 प्रतिशत नाइट्रेट प्रभावित गांव एवं ढाणियां राजस्थान में हैं।

जल जीवन मिशन (जेजेएम) कार्यक्रम की शुरुआत मार्च-2024 तक हर घर में पेयजल आपूर्ति के उद्देश्य से की गई है। योजना के बारे में विस्तृत दिशा-निर्देश दिसम्बर, 2019 में जारी किये गए थे। इस कार्यक्रम के तहत वर्ष 2024 तक राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी ग्रामीण परिवारों को 'हर घर जल कनेक्शन' देकर 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के आधार पर पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

राजस्थान ने अपनी विषम भौगोलिक परिस्थितियों, विशाल भू-भाग जिसका दो-तिहाई हिस्सा मरूस्थल है एवं प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता भी न्यूनतम है। पूर्वी राजस्थान के 42 प्रतिशत नल कनेक्शन

मो. मुस्तफा शेख  
सहायक निदेशक, जनसंपर्क

भूजल पर आधारित हैं। इन परिस्थितियों के बाद बावजूद मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन तथा जलदाय मंत्री डॉ. महेश जोशी के प्रयासों से जल जीवन मिशन लागू होने के बाद अभी तक 13 लाख 88 हजार परिवारों को 'हर घर जल कनेक्शन' और दे दिए हैं। जल जीवन मिशन की घोषणा से पहले तक प्रदेश में 'हर घर जल कनेक्शन' वाले ग्रामीण परिवारों की संख्या 11 लाख 74 हजार 131 थी। मिशन के तहत अब तक प्रदेश में 'हर घर जल कनेक्शन' वाले परिवारों की संख्या संख्या 25 लाख 56 हजार 652 हो गई है। इस प्रकार अगस्त, 2019 से अब तक प्रदेश में जेजेएम के आने से पहले जितने 'हर घर जल कनेक्शन' थे, उनमें 118 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी हो गई है। प्रदेश में जल जीवन मिशन पर अब तक 6 हजार 529 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं।

राज्य सरकार वर्ष 2024 तक प्रदेश के सभी ग्रामीण परिवारों को 'हर घर जल कनेक्शन' के माध्यम से स्वच्छ पेयजल आपूर्ति की सुविधा मुहैया कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। नल से जल मिलने पर प्रदेश की बहनों-बेटियों को पीने के पानी जैसी मूलभूत सुविधा के लिए इधर-उधर नहीं भटकना पड़ेगा। इससे उनके समय में बचत होगी और वे पढ़-लिख कर आगे बढ़ेंगी। जल जीवन मिशन प्रदेश में अपेक्षित गति से आगे बढ़ रहा है। राजस्थान में अप्रैल, 2022 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में एक करोड़ 5 लाख 69 हजार ग्रामीण परिवारों को जल जीवन मिशन के तहत जल कनेक्शन दिए जाने हैं। इनमें से 91 लाख 24 हजार परिवारों को 'हर घर जल कनेक्शन' जारी

करने के लिए 38 हजार 447 गांवों में 133 वृहद पेयजल योजनाओं और 9 हजार 633 एकल क्षेत्रीय ग्रामीण जल योजनाओं की स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं, इस पर 67 हजार 263 करोड़ रुपये का व्यय होंगे। प्रदेश में सौर उर्जा संचालित लगभग 750 योजनाएं भी स्वीकृत की गई हैं, जिससे संचालन एवं संधारण की लागत में 6.5 करोड़ रुपये की वार्षिक बचत होगी।

प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थितियों एवं छितराई हुई बसावट के कारण जन सेवाओं की प्रदायगी में अत्यधिक राशि व्यय करनी पड़ती है एवं समय भी अधिक लगता है। इन परिस्थितियों के बावजूद प्रदेश में 90 प्रतिशत जल संबंधों की स्वीकृतियां जारी कर दी गई हैं तथा 50 प्रतिशत जल संबंधों के लिए कार्यादेश भी जारी कर दिये गए हैं। जन सहयोग सहभागिता राशि के रूप में भी 55 करोड़ रुपये प्राप्त किए जा चुके हैं। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा जेजेएम की योजनाओं की समीक्षा कर कार्य न्यूनतम समयवाधि में पूर्ण करने हेतु महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। क्रियान्वयन के पश्चात् योजनाओं के प्रभावी रख-रखाव हेतु संचालन व संधारण पॉलिसी भी तैयार की जा रही है। जेजेएम के तहत प्रदेश के कुल 43 हजार 364 गांवों में से 43,272 गांवों में ग्राम जल स्वच्छता समितियों का गठन किया जा चुका है। करीब 13 हजार ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों का बैंक खाता खोला जा चुका है। इन समितियों के गठन में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। राजस्थान जेजेएम के तहत विलेज एक्शन प्लान तैयार करने में भी देश में सबसे आगे है। अभी तक 43 हजार 208 ग्राम कार्य योजनाएं (विलेज एक्शन प्लान) बनाई जा चुकी हैं, जो कि देश में सर्वाधिक हैं। ग्राम सभाओं के माध्यम से इनका अनुमोदन कराया जा रहा है।

राज्य में महिला सशक्तीकरण एवं नारी शक्ति की सक्रिय भागीदारी में बढ़ोतरी करने के लिए जेजेएम के तहत घरेलू जल संबंध महिला मुखिया के नाम से ही जारी करने का प्रावधान किया है। जेजेएम के कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा पहली बार क्वालिटी एश्योरेंस एवं क्वालिटी कंट्रोल मैनुअल तैयार कर इसे लागू किया जा रहा है। प्रदेश में ऐसे गांव जहां जेजेएम के तहत हर घर जल



कनेक्शन के माध्यम से पेयजल आपूर्ति संभव नहीं हो पा रही है, उन्हें लाभान्वित करने के लिए विभाग ने नवाचार करते हुए सौर ऊर्जा आधारित सामुदायिक एवं व्यक्तिगत टांका निर्माण के कार्य स्वीकृत कराये हैं। इस संबंध में जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग के माध्यम से 356.85 करोड़ रुपये की लागत से अलवर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर एवं पाली के 259 गांवों में 19 हजार 825 टांकों का निर्माण कराया जायेगा। इससे 1 लाख 31 हजार, 254 की आबादी लाभान्वित होगी। ●



## सिंचित क्षेत्र में पानी की बचत के प्रयासों के साथ पेयजल को प्राथमिकता

“ इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के निर्माण के मुख्य उद्देश्य थार मरूस्थल के क्षेत्र में सिंचाई व पेयजल की व्यवस्था कर अकाल की स्थितियों की समाप्ति, विस्तृत भू-भाग के वनीकरण द्वारा रेगिस्तान के विस्तार को रोकना तथा क्षेत्र के सम्पूर्ण विकास के माध्यम से रोजगार के अवसरों में वृद्धि व यहाँ के निवासियों के जीवन स्तर में सुधार थे। उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हो चुकी है। परियोजना से पेयजल की बढ़ती मांग के कारण पेयजल की आपूर्ति को प्राथमिकता देते हुये सिंचित क्षेत्र को 16.17 लाख हैक्टेयर पर सीमित रखते हुए वर्तमान में इस नहर से पेयजल सुविधा का झुंझुनूं, सीकर तथा पाली तक विस्तार किया जा रहा है। ”



जल संसाधन एवं इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीय का सहायक निदेशक सम्पत राम चांदोलिया द्वारा लिये गए साक्षात्कार के महत्वपूर्ण अंश.....

### इंदिरा गांधी नहर परियोजना से कितने जिलों एवं कितने भू-भाग को लाभ मिला है ?

इंदिरा गांधी नहर परियोजना से वर्तमान में 10 जिले लाभान्वित हो रहे हैं। जिनमें से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर (6 जिले) की 16.17 लाख हैक्टेयर भूमि को सिंचाई व पेयजल सुविधा मिल रही है, जबकि 4 जिलों नागौर, बाड़मेर, झुंझुनूं, सीकर को पेयजल सुविधा मिल रही है। इसके अलावा विभिन्न ऊर्जा संयंत्रों, उद्योगों इत्यादि को भी इस परियोजना से पानी मिल रहा है।

### परियोजना से सिंचाई अथवा पेयजल सुविधाओं का विस्तार हुआ है ?

इससे 16.17 लाख हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र में सिंचाई सुविधा व 10 जिलो के लगभग 7339 गांवों व विभिन्न शहरों, कस्बों के लगभग पौने दो करोड़ निवासियों को पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

### इंदिरा गांधी नहर परियोजना के निर्माण से पश्चिमी राजस्थान में बहुमुखी विकास का सपना कहाँ तक साकार हुआ है ?

इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पश्चिमी राजस्थान के विकास में अभूतपूर्व योगदान है। इस नहर के निर्माण से पूर्व जहां कभी पीने के पानी के लिये भी महिलाओं को कई किलोमीटर दूर पैदल जाना पड़ता था, जहां दूर-दूर तक हरियाली का नाम नहीं था, वहां आज खेतों में फसलें लहलहा रही हैं तथा यह क्षेत्र खाद्यान्न उत्पादन हेतु राज्य का

प्रमुख केन्द्र बन गया है, जिसके कारण इस क्षेत्र को निरन्तर पड़ने वाले अकाल की विभीषिका से मुक्ति मिली है। इस नहर से सूरतगढ़, बरसिंहसर, गुढा, रामगढ, गिरल, राजवेस्ट (बाड़मेर) की विभिन्न ऊर्जा परियोजनाओं को ऊर्जा उत्पादन तथा उद्योगों हेतु पानी उपलब्ध हुआ है। खाद्यान्न, पेयजल उपलब्धता, कृषि मंडियों व सड़कों के विकास, विद्युत उत्पादन, विभिन्न उद्योगों की स्थापना के कारण इस क्षेत्र में रोजगार के साधन बढ़ गये हैं, तथा यहाँ के निवासियों का जीवन सुगम हुआ है।

### इस परियोजना को लेकर आगामी कार्य योजना क्या है ?

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के निर्माण के मुख्य उद्देश्य थार मरूस्थल के क्षेत्र में सिंचाई व पेयजल की व्यवस्था कर अकाल की स्थितियों की समाप्ति, विस्तृत भू-भाग के वनीकरण द्वारा रेगिस्तान के विस्तार को रोकना तथा क्षेत्र के सम्पूर्ण विकास के माध्यम से रोजगार के अवसरों में वृद्धि व यहाँ के निवासियों के जीवन स्तर में सुधार थे। उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हो चुकी है। परियोजना से पेयजल की बढ़ती मांग के कारण पेयजल की आपूर्ति को प्राथमिकता देते हुये सिंचित क्षेत्र को 16.17 लाख हैक्टेयर पर सीमित रखते हुए वर्तमान में इस नहर से पेयजल सुविधा का झुंझुनूं, सीकर तथा पाली तक विस्तार किया जा रहा है। सिंचित क्षेत्र में पानी की बचत हेतु द्वितीय चरण लिफ्ट योजनाओं में फव्वारा सिंचाई व्यवस्था स्थापित करने का कार्य प्रगति



पर है। इसे जैसलमेर के कुछ प्रवाह क्षेत्र में भी स्थापित किया जायेगा। पेयजल की बढ़ती हुई मांग की आपूर्ति हेतु मुख्य नहर के निकट 4 स्थानों पर एस्क्रेप जलाशयों का निर्माण प्रस्तावित है, जिसमें वर्षा काल/अधिक पानी की उपलब्धता के समय हरिके बैराज के नीचे व्यर्थ बह कर चले जाने वाले पानी को भरा जायेगा तथा बाद में पेयजल हेतु काम में लिया जायेगा।

**इंदिरा गांधी नहर बनने के बाद पहले की तुलना में उत्पादन में कितनी बढ़ोतरी हुई? क्या किसानों की आय में भी इजाफा हुआ है?**

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के निर्माण से पूर्व यहाँ के निवासियों के लिये खेती तो दूर की बात थी पेयजल के लिये भी उन्हें दूर-दूर तक भटकना पड़ता था। अधिकांश निवासियों की आजीविका पशुपालन पर निर्भर थी इस क्षेत्र में होने वाली अत्यल्प वर्षा से थोड़ा बहुत बाजरा, जौ, चना, ज्वार इत्यादि का उत्पादन हो पाता था। पशुओं के लिये सेवण घास चारे का मुख्य स्रोत थी। इसके अतिरिक्त खेजड़ी, झाल, कैर, बबूल, नीम, थोर, करेल इत्यादि वृक्षों, झाड़ियों के उत्पादनों से यहाँ के निवासियों व पशुओं को जीवन यापन में सहायता मिलती थी।

**जीवनदायिनी नहर के पानी से पश्चिमी क्षेत्र पाकिस्तान को भी सीपेज के जरिए लाभ मिल रहा है, जबकि राजस्थान को पानी की दरकार है। इसके लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं?**

इन्दिरा गांधी फीडर पंजाब में हरिके हैड से उदगमित होती है तथा लगातार प्रवाह के कारण इनकी लाईनिंग जगह-जगह से क्षतिग्रस्त होने के कारण इसकी मूल प्रवाह क्षमता 18,500 क्यूसेक से कम होकर लगभग 11500-12000 क्यूसेक रह गई है।

23.01.2019 को राजस्थान, पंजाब एवं भारत सरकार के मध्य हुए समझौते के अन्तर्गत फीडर के पंजाब भाग की लगभग 97 किलोमीटर लम्बाई में रिलाइनिंग की जानी है। जिसमें से 23 किलोमीटर में रिलाइनिंग की जा चुकी है तथा इस वर्ष लगभग 53 किलोमीटर में रिलाइनिंग कार्य प्रगतिरत है। नहर की मूल प्रवाह क्षमता स्थापित होने से हरिके बैराज से मानसून के दौरान बहकर व्यर्थ पाकिस्तान जा रहे जल का उपयोग राजस्थान में हो सकेगा।

इसी के साथ रेगिस्तान क्षेत्र में राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना के अन्तर्गत राजस्थान एवं हरियाणा स्थित फीडर एवं मुख्य नहर की रिलाइनिंग के कार्य भी करवाये जा रहे हैं। इस परियोजना के अन्तर्गत कुल 179.53 किलोमीटर लम्बाई में रिलाइनिंग की जानी है। फीडर/मुख्य नहर की 77.45 किलोमीटर लम्बाई में रिलाइनिंग की जा चुकी है एवं इस वर्ष 67.51 किलोमीटर लम्बाई में रिलाइनिंग के कार्य प्रगतिरत है। इसके अतिरिक्त इंदिरा गांधी नहर परियोजना के वितरण तंत्र की प्रस्तावित कुल 2498.69 किलोमीटर के विरुद्ध माह अप्रैल, 2022 तक 1105.15 किलोमीटर लम्बाई में जीर्णोद्धार के कार्य पूर्ण करवा लिये गये हैं।

**नहरों के पानी से सेम की समस्या दूर करने के क्या नए प्रयास किए जा रहे हैं?**

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में सेम समस्या लगभग 40 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुई। सेम ग्रस्त क्षेत्र के लेवल चारों तरफ से नीचे है तथा उनमें सतही एवं भूमिगत जल निकासी का अभाव है। क्षेत्र नीचा होने के कारण तथा आसपास की नहरों से पानी रिसाव होने के कारण सेम समस्या पैदा हुई।

जिला हनुमानगढ़ के टिब्बी, रावतसर, हनुमानगढ़, पीलीबंगा व श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ ब्लॉक में 22851 हैक्टेयर क्षेत्र में भूमि सेमग्रस्त है। इसके निराकरण के लिये लगातार प्रयास किये गये। जिसमें मुख्य रूप से सेमग्रस्त क्षेत्र में ट्यूबवैलों का निर्माण, पम्प स्थापित करना व ड्रेन का निर्माण कर पानी की निकासी इन्दिरा गांधी मुख्य नहर व वितरिकाओं में की गई। जिससे सेम समस्या का आंशिक रूप से निदान हुआ लेकिन विभिन्न कारणों से क्षेत्र में पानी का पुनः भराव हो गया। सेम समस्या के स्थायी समाधान हेतु साइंटिफिक स्टडी करवायी गयी। सेमग्रस्त क्षेत्र का विस्तृत अध्ययन किया एवं 22851 हैक्टेयर क्षेत्र सेमग्रस्त आंकलित किया गया।

सेम समस्या के निराकरण हेतु नये प्रयासों के अन्तर्गत आर.डब्ल्यू.एस.आर.पी.डी. प्रोजेक्ट एस्टीमेट में सेमग्रस्त क्षेत्र के समाधान के लिये राशि रुपये 292.42 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। जिससे मुख्य रूप से 150 किलोमीटर लम्बाई में सेम नाले का जीर्णोद्धार कार्य, नये पम्पिंग स्टेशन स्थापित करना, सभी पम्पों को सौर ऊर्जा से संचालित करना, भूमिगत ड्रेनेज स्थापित करना, पाइप बिछाना आदि कार्य प्रस्तावित किये गये हैं। यह कार्य फरवरी 2025 तक पूर्ण करवा लिये जायेंगे। जिससे सेम समस्या का निवारण संभव हो पायेगा।

**बांधों के रखरखाव के लिए राज्य सरकार क्या विशेष उपाय कर रही है?**

इंदिरा गांधी नहर परियोजना (आईजीएनपी) द्वितीय चरण की नहरों पिछले 20-30 वर्षों में निरन्तर उपयोग और रखरखाव के लिए पर्याप्त धन की कमी के कारण क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिसके परिणामस्वरूप अत्यधिक जलहास होता है। इसलिए नहर प्रणालियों के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण की 3 परियोजनायें (बीकानेर संभाग में 2 व जैसलमेर संभाग में 1) वर्ष 2020-21, 2021-22 में नाबार्ड आर.आई.डी.एफ, अन्तर्गत वित्त पोषण से शुरू की गई हैं। बीकानेर संभाग की परियोजनाओं की लागत 121 करोड़ और 134.55 करोड़ तथा जैसलमेर संभाग की परियोजना की लागत 58.42 करोड़ है। इन कार्यों पर मार्च, 2022 तक 72.92 करोड़ रुपये व्यय हुए हैं। चारणवाला शाखा के जीर्णोद्धार का कार्य भी नाबार्ड आर.आई.डी.एफ अन्तर्गत स्वीकृत हो चुका है जिसे शीघ्र ही आरम्भ करवाया जायेगा। ●

## राजस्थान में 13 लाख 88 हजार घर जल कनेक्शन से लाभान्वित

“ प्रदेश के बड़े भू-भाग में उपलब्ध भूजल पीने योग्य नहीं है। पूरे देश की गुणवत्ता प्रभावित गांव-ढाणियों में से 34 प्रतिशत राजस्थान में हैं। मानसून 2021 में बीसलपुर एवं जवाई बांध जैसे सतही जल स्रोत पूरी तरह से नहीं भरे, इससे भूजल के स्तर में भी बढ़ोतरी नहीं हुई। इन आंकड़ों से राज्य में भू-जल की गम्भीरता का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। प्रदेश में बारहमासी सतही जल स्रोत उपलब्ध नहीं है। यदि हमने समय रहते भू-जल संसाधनों के समुचित उपयोग, संरक्षण एवं प्रबन्धन पर ध्यान नहीं दिया तो वह दिन दूर नहीं जब हमारे राज्य को दक्षिण अफ्रीका के कैपटाउन व महाराष्ट्र के लातूर एवं तमिलनाडू के चेन्नई जैसे शहरों में उत्पन्न हुए भयंकर जल संकट की भयावहता जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। ”



जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ. महेश जोशी का सहायक निदेशक मो. मुस्तफा शेख द्वारा लिए गए साक्षात्कार के महत्वपूर्ण अंश...

### जल जीवन मिशन के कार्यों में राजस्थान की क्या प्रगति है ?

जल जीवन मिशन के कार्य प्रदेश में अपेक्षित गति से चल रहे हैं। जो कमियां हैं उन्हें दूर किया जा रहा है। राजस्थान में एक अप्रैल, 2022 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 105.69 लाख परिवारों को जल जीवन मिशन के तहत जल कनेक्शन दिए जाने हैं। जल जीवन मिशन की शुरुआत के समय 15 अगस्त, 2019 की स्थिति में राजस्थान में 11.47 लाख घरों में घरेलू जल संबंध थे। प्रदेश में मात्र 10 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास ही जल कनेक्शन थे।

### प्रदेश में जल कनेक्शन में कितनी वृद्धि हुई है ?

वर्ष 2019 से लेकर अभी तक प्रदेश में 13.88 लाख नए घरों को जल कनेक्शन से लाभान्वित किया जा चुका है यानि जल संबंधों में कुल 118 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मिशन प्रारंभ होने के बाद से राजस्थान में 13 लाख 88 हजार घरों को जल कनेक्शन से लाभान्वित किया गया है।

### जेजेएम कार्यों की बढ़ती लागत का क्या समाधान है ?

प्रदेश में जल जीवन मिशन के कार्यों को और गति देने के लिए जेजेएम के तहत टेण्डर प्रीमियम एवं प्राइस वेरिएशन क्लॉज अनुमत करने की जरूरत है।

### ईआरसीपी राज्य के लिए कितनी महत्वपूर्ण है ?

पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) से प्रदेश के 13 जिलों में पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित होगी। प्रदेश के पूर्वी भाग में जहां पानी की विकट समस्या है वहां जल जीवन मिशन के मापदंडों के अनुसार 55 लीटर पेयजल प्रति व्यक्ति प्रति दिन उपलब्ध कराने के लिए ईआरसीपी बेहद अहम है। 37 हजार 247 करोड़ रुपये की इस परियोजना में 26 वृहद् एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से 0.8 लाख हैक्टेयर विद्यमान सिंचित क्षेत्रों का पुनरूद्धार तथा 2 लाख हैक्टेयर नए क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

### राज्य में जल की वर्तमान स्थिति कैसी है ?

विश्व में प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष पानी की उपलब्धता 2000 घनमीटर है, देश में प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष 1700 घनमीटर जबकि राजस्थान में प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष पानी की उपलब्धता मात्र 640 घनमीटर है। हमारे यहां पशुधन की अधिकता के कारण पेयजल की मांग भी निर्धारित मापदंडों से अधिक रहती है।

### भू-जल पर कितनी योजनाएं आधारित हैं ?

प्रदेश की 71 प्रतिशत जल योजनाएं पूर्णतः भूजल पर आधारित हैं जबकि करीब 75 प्रतिशत ब्लॉक्स में भू-जल की स्थिति अत्यंत गंभीर है। वर्ष 1984 में राज्य के 203 ब्लॉक सुरक्षित श्रेणी में थे, ये

सभी ब्लॉक आज अत्यधिक दोहित श्रेणी में आ गये हैं। राज्य के कुल 295 ब्लॉक्स में से वर्ष 2020 तक सिर्फ 37 ब्लॉक ही सुरक्षित बचे हुए थे। भूजल के 203 ब्लॉक अत्यधिक दोहित, 25 ब्लॉक क्रिटिकल एवं 29 ब्लॉक क्रिटिकल हैं।

### प्रदेश में भू-जल की स्थिति अभी कैसी है ?

प्रदेश के बड़े भू-भाग में उपलब्ध भूजल पीने योग्य नहीं है। पूरे देश की गुणवत्ता प्रभावित गांव-ढाणियों में से 34 प्रतिशत राजस्थान में हैं। मानसून 2021 में बीसलपुर एवं जवाई बांध जैसे सतही जल स्रोत पूरी तरह से नहीं भरे, इससे भूजल के स्तर में भी बढ़ोतरी नहीं हुई। इन आंकड़ों से राज्य में भू-जल की गम्भीरता का सहज अनुमान लगाया जा सकता है।

### प्रदेश में जल की उपलब्धता बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए ?

प्रदेश में बारहमासी सतही जल स्रोत उपलब्ध नहीं है। यदि हमने समय रहते भू-जल संसाधनों के समुचित उपयोग, संरक्षण एवं प्रबन्धन पर ध्यान नहीं दिया तो वह दिन दूर नहीं जब हमारे राज्य को दक्षिण अफ्रीका के कैपटाउन व महाराष्ट्र के लातूर एवं तमिलनाडू के चेन्नई जैसे शहरों में उत्पन्न हुए भयंकर जल संकट की भयावहता जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है।

### जल संरक्षण के लिए क्या प्रयास होने चाहिए ?

यहां मैं आपको दक्षिण अफ्रीका के कैपटाउन शहर का उदाहरण देना चाहता हूँ जहां स्थिति यहां तक पहुंच गई थी कि जल के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा शहर के गली मोहल्लों में सायरन बजा कर जल की बचत के लिए लोगों को जागरूक किया। पानी का अत्यधिक उपयोग करने वाले लोगों के नाम विभिन्न माध्यमों में प्रकाशित किये गये, होटलों एवं रेस्तरां में पेपर के कप व ग्लास का उपयोग शुरू किया गया जिससे बर्तन धोने में लगने वाले पानी की बचत हो सके। साथ ही, पानी के दुरुपयोग पर दण्डात्मक कार्यवाही जैसे कठोर प्रावधान भी लागू किए गए।

### भौगोलिक परिस्थिति एवं प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता के अनुसार राज्य की क्या स्थिति है ?

राजस्थान में पानी की उपलब्धता कम होने, सतही जल स्रोतों की दूरी अधिक होने एवं आबादी बिखरी होने के कारण न सिर्फ योजनाओं की लागत अधिक आती है बल्कि योजनाओं के क्रियान्वयन में भी अधिक समय लगता है। देश की कुल गुणवत्ता प्रभावित ग्राम ढाणियों में से 34 प्रतिशत राजस्थान में है। कई जिलों में आबादी की बिखरी बसावट के कारण शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने में लागत काफी अधिक आती है। राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण संसाधनों पर अधिक दबाव पड़ता है।

### पेयजल आपूर्ति सुधारने की दिशा में क्या प्रयास किए गए हैं ?

इस बार मार्च माह से ही भीषण गर्मी का दौर चल रहा है। गर्मी के मौसम में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए विभाग ने कलेक्टर्स को 50-50 लाख रुपये कंटीजेंसी प्लान में उपलब्ध कराए हैं एवं पेयजल की कमी वाले क्षेत्रों में टैंकरों से पेयजल आपूर्ति एवं नए ट्यूबवेल खुदवाने जैसे जरूरी कदम उठाए गए हैं। शहरी क्षेत्रों में 63 शहरों में प्रतिदिन 4205 टैंकर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 27 जिलों में 8079 गांव-ढाणियों में 7938 टैंकर ट्रिप प्रतिदिन जल परिवहन किया जा रहा है। आपदा राहत मद में 10 जिलों चूरू, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, पाली, जालोर, सिरोही, जोधपुर, नागौर एवं डूंगरपुर में जल परिवहन की अवधि बढ़ाकर 31 जुलाई, 2022 कर दी गई है। हैण्डपंप हमारी ग्रामीण पेयजल व्यवस्था की लाइफ लाइन है। ऐसे में, अधिकारियों को हैण्डपंप मरम्मत कार्यों की विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। मरम्मत कार्यों के लिए किराए के 560 वाहन एवं 2500 संविदा श्रमिक लगाए गए हैं। एक अप्रैल से चल रहे हैण्डपंप मरम्मत अभियान के तहत अब तक 31354 हैण्डपंपों की मरम्मत कर दी गई है। आमजन की पेयजल समस्या के समाधान के लिए राज्य स्तरीय टोल फ्री नम्बर 181 के अलावा राज्य एवं जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध रूप से निस्तारण किया जा रहा है।

जल जीवन मिशन के तहत अब तक 60 हजार 606 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। इनमें 9 हजार 188 एकल एवं मल्टी विलेज योजनाएं तथा 128 वृहद् परियोजनाएं शामिल हैं। इन स्वीकृत परियोजनाओं से 35 हजार 776 गांवों के लगभग 86 लाख परिवारों को घरेलू जल संबंधों के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की जाएगी। प्रदेश में चार बड़ी पेयजल परियोजनाएं ईसरदा बांध आधारित दौसा एवं सवाई माधोपुर की पेयजल परियोजना, परवन अकावद पेयजल परियोजना (झालावाड़), नवनेरा बांध आधारित पेयजल परियोजना (कोटा) एवं बत्तीसा नाला आधारित सिरोही के गांवों की पेयजल परियोजना क्रियान्वित की जा रही हैं।

### पेयजल गुणवत्ता में सुधार की दृष्टि से क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेयजल गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों के लिए पिछले तीन साल में 1180 आरओ प्लांट लगाए गए हैं तथा 1953 सौर ऊर्जा आधारित डी-फ्लोरिडेशन यूनिट्स स्थापित की गई हैं। जल प्रदाय योजनाओं की पेयजल गुणवत्ता जांच, सर्वेक्षण, नियंत्रण एवं निगरानी के लिए राज्य के सभी 33 जिलों में प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। ये प्रयोगशालाएं जल प्रदाय योजनाओं में जल गुणवत्ता नियंत्रण एवं निगरानी के साथ ही दूषित पेयजल, मौसमी बीमारियों एवं जल जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए जल शुद्धीकरण तथा पेयजल गुणवत्ता की प्रभावी मॉनिटरिंग का कार्य सुचारू रूप से कर रही हैं। ●

## सिंचाई, पेयजल सहित उद्योगों और ऊर्जा संयंत्रों को भी पानी की उपलब्धता सुनिश्चित

“ इन्दिरा गांधी नहर परियोजना से सिंचाई व पेयजल के अतिरिक्त ऊर्जा संयंत्रों को भी पानी दिया जा रहा है। इस नहर से सूरतगढ़, बरसिंहसर, गुढ़ा, रामगढ़, गिरल, राजवेस्ट (बाडमेर) की विभिन्न ताप व सौर ऊर्जा परियोजनाओं को ऊर्जा उत्पादन हेतु पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राजस्थान की महत्वाकांक्षी रिफाइनरी व इसके निकट विकसित होने वाले औद्योगिक क्षेत्र को भी इस नहर से पानी दिया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में भी रीको के कुछ औद्योगिक क्षेत्रों को इस नहर से पानी दिया जा रहा है। ”



जल संसाधन विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री आनन्द कुमार से सहायक निदेशक सम्पत राम चांदोलिया की गई बातचीत के महत्वपूर्ण अंश.....

### इंदिरा गांधी नहर परियोजना में डिग्गी निर्माण एवं फव्वारा पद्धति अथवा जल के कुशल उपयोग एवं न्यूनतम छीजत को लेकर क्या रणनीति है ?

राजस्थान व देश की अधिकांश सिंचाई परियोजनाओं की तरह इंदिरा गांधी नहर परियोजना में भी पारम्परिक 'फ्लड सिंचाई' की जाती है। किन्तु उक्त पद्धति में जलहास की मात्रा ज्यादा होती है। अतः उपलब्ध पानी के कुशलतम उपयोग हेतु परियोजना के द्वितीय चरण की 6 लिफ्ट योजनाओं में (जहाँ पक्के खालों का निर्माण नहीं हुआ था) फव्वारा सिंचाई व्यवस्था स्थापित करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया। सर्वप्रथम वर्ष 2007 में इन लिफ्ट योजनाओं के लगभग 27449 हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र में फव्वारा सिंचाई प्रणाली स्थापित करने का पायलट प्रोजेक्ट आरम्भ किया गया। उक्त पायलट प्रोजेक्ट की सफलता को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा द्वितीय चरण लिफ्ट योजनाओं के शेष 3.20 लाख हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र में भी प्रेशर सिंचाई पद्धति स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इन कार्यों की उपयोगिता व अति आवश्यकता को देखते हुए अब राज्य सरकार द्वारा कार्य करवाया जा रहा है।

पायलट परियोजना अन्तर्गत कराये गये कार्यों में से तेजपुरा माइनर के लिये विभाग ने जल उपयोग क्षमता बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय जल मिशन अन्तर्गत वर्ष 2019 में राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया है।

### नहरी तंत्र के रखरखाव एवं सुदृढीकरण के क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

परियोजना की फीडर नहर का निर्माण वर्ष 1958 में आरम्भ हो गया था तथा वर्ष 1961 में प्रथम बार नौरंगदेसर वितरिका में जल प्रवाहित कर दिया गया था। उसके पश्चात् अन्य नहरों का निर्माण व उनमें जल प्रवाह धीरे-धीरे आरम्भ हो गया।

द्वितीय चरण प्रवाह क्षेत्र की नहरों भी विगत 20-30 वर्षों से सिंचाई व पेयजल उपलब्ध करवा रही हैं। इनके जीर्णोद्धार हेतु भी विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है तथा धीरे-धीरे वरीयतानुसार अलग-अलग नहर प्रणालियों का वित्त पोषण नाबार्ड अन्तर्गत स्वीकृत करवा कर कार्य करवाया जा रहा है। इस हेतु अब तक बीकानेर संभाग में 3 व जैसलमेर संभाग में एक प्रोजेक्ट से नाबार्ड से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। तीन कार्य प्रगतिरत हैं तथा शेष एक शीघ्र आरम्भ करवाया जायेगा।

### प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने हाल ही में पेश किए गए बजट में कृषि बजट अलग से पेश किया था जो किसान कल्याण की प्रतिबद्धता का द्योतक है, क्या कहना चाहेंगे आप ?

कृषकों के लिये अलग कृषि बजट प्रस्तुत किया जाना किसानों के कल्याण के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाता है। इस बजट के माध्यम से इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के लिये 2727 करोड़ रुपये की 11 घोषणाएं की गई हैं, जो विगत वर्षों में की गई घोषणाओं की तुलना में बहुत ज्यादा है। इन घोषणाओं की क्रियान्विति द्वारा परियोजना क्षेत्र में फव्वारा सिंचाई प्रणाली का विकास, नहरों के जीर्णोद्धार, लिफ्ट योजनाओं के पम्पिंग स्टेशनों की दक्षता बढ़ाने के कार्यों द्वारा जहां सिंचाई प्रणाली के आधारभूत ढांचे का विकास होगा वहीं ड्रिप, स्प्रींकलर पर 50 प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा से कृषकों का इस पद्धति की ओर रुझान बढ़ेगा, जिससे अन्ततः उनकी आमदनी बढ़ेगी।

### नहरों में नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यों को लेकर विभाग की क्या प्रगति है ?

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की नहरों द्वारा जल वितरण की प्रभावी मॉनिटरिंग हेतु परियोजना में स्काडा प्रणाली स्थापित की जा

चुकी है। इस प्रणाली से इन्दिरा गांधी फीडर, मुख्य नहर, ब्रांच नहरों एवं सब-ब्रांच नहरों पर अल्ट्रासोनिक उपकरणों द्वारा निरन्तर पानी के प्रवाह का आंकलन किया जाता है। परियोजना के अधिकारी, कर्मचारी अपने फील्ड स्टेशनों पर एवं काश्तकार इन्टरनेट पर उक्त जल प्रवाह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जिससे परियोजना अधिकारियों को नहरों में जल प्रवाह पर प्रभावी नियंत्रण रखने में मदद मिलती है।

विभाग को परियोजना की नहरों में स्काडा आधारित जल मापन व मोनीटरिंग प्रणाली स्थापना सहित नहरों के प्रभावी रखरखाव व संचालन से एकीकृत बहुआयामी सिंचित क्षेत्र विकास के लिये माह फरवरी, 2020 के लिये सी.बी.आई.पी अवार्ड 2020 प्राप्त हुआ है।

परियोजना क्षेत्र में प्रेशर, स्प्रींकलर सिंचाई प्रणाली की स्थापना का कार्य भी आधुनिकीकरण की दिशा में कदम है, जिससे सिंचाई प्रणाली की दक्षता बढ़ाकर कम पानी से अधिक कृषि उत्पादन किया जा सकेगा।

**नहरें समृद्धि की वाहक हैं, उत्पादन क्षमता में इजाफे से अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में इनकी भूमिका कैसी है ?**

इस मरूस्थलीय क्षेत्र में जहां कभी पीने के पानी के लिये भी महिलाओं को कई किलोमीटर दूर पैदल जाना पड़ता था, जहां दूर-दूर तक हरियाली का नाम नहीं था वहां आज खेतों में फसलें लहलहा रही हैं। यह क्षेत्र खाद्यान्न उत्पादन हेतु राज्य का प्रमुख क्षेत्र बन गया है। अकाल की स्थितियों की समाप्ति हुई है। जिसके कारण इस क्षेत्र के निवासियों को जहां अकाल पड़ने पर पलायन करना पड़ जाता था वहां अब विभिन्न आर्थिक गतिविधियों व रोजगार के अवसरों में वृद्धि से उनकी सामाजिक आर्थिक दशा में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

**राजस्थान में नहरों ने मरूस्थलीकरण पर रोक लगाकर इसे हरियाली से आच्छादित किया है, ये कहना कहां तक सही है ?**

नहर निर्माण पश्चात् नहरी जल उपलब्ध होने पर मरूस्थल का प्रसार रोकने, तीव्र मरूस्थलीय आंधियों से टीलों का सरकना रोकने/टिब्बा स्थिरीकरण, सूक्ष्म जलवायु के सुधार व क्षेत्र में हरियाली विस्तार के उद्देश्य से वृहद् स्तर पर वनीकरण किया गया। इसके लिये नहरों व सड़को के किनारे तथा नहरों के निकट ऊंचे टीलों पर वृक्षारोपण किया गया। क्षेत्र में आबादी बढ़ने, कृषि क्षेत्र का विस्तार होने से भूमि व वातावरण में नमी बढ़ने से भी वृक्षों, हरियाली, वन क्षेत्र में वृद्धि हुई। परियोजना क्षेत्र में आज तो कहीं-कहीं इतना सघन वन क्षेत्र है कि नये व्यक्ति के लिये यह कल्पना करना भी कठिन होता है कि कभी यहाँ मात्र रेतीले टीले थे।

**क्या नहरों के पानी को विद्युत उत्पादन औद्योगिक कार्यों में प्रयुक्त कर इनका उपयोग किया जा रहा है ?**

जी हां, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना से सिंचाई व पेयजल के

अतिरिक्त ऊर्जा संयंत्रों को भी पानी दिया जा रहा है। इस नहर से सूरतगढ़, बरसिंहसर, गुढ़ा, रामगढ़, गिरल, राजवेस्ट (बाड़मेर) की विभिन्न ताप व सौर ऊर्जा परियोजनाओं को ऊर्जा उत्पादन हेतु पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राजस्थान की महत्वाकांक्षी रिफाइनरी व इसके निकट विकसित होने वाले औद्योगिक क्षेत्र को भी इस नहर से पानी दिया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में भी रीको के कुछ औद्योगिक क्षेत्रों को इस नहर से पानी दिया जा रहा है।

**इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के लिये किन नदियों से कितना पानी आवंटित है।**

रावी-व्यास नदियों के पानी के बंटवारे हेतु वर्ष 1981 में हुए अन्तर्राज्यीय समझौते में राजस्थान को 8.60 मिलियन एकड़ फीट (एम.ए.एफ.) पानी आवंटित किया गया है, जिसमें से राज्य सरकार द्वारा 7.59 एम.ए.एफ. पानी इन्दिरा गांधी नहर परियोजना को आवंटित किया गया।

**क्या परियोजना वृहद् सिंचित क्षेत्र में एक व्यवस्थित जल वितरण प्रणाली है ?**

परियोजना में जल वितरण कार्यक्रम पंजाब स्थित नदियों व बांधों में पानी की उपलब्धता पर निर्भर करता है। पानी की उपलब्धता के आधार पर भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड द्वारा सहभागी राज्यों का शेयर निर्धारित किया जाता है। उक्त पानी तथा परियोजना क्षेत्र में प्रति बारी सिंचाई हेतु पानी की आवश्यकता व परियोजना से स्वीकृत पेयजल व अन्य गैर कृषि प्रयोजनार्थ पानी की आवश्यकता के आधार सिंचाई हेतु दी जाने वाली पानी की बारियों का आंकलन किया जाता है। जिसके आधार पर नहरों को 3-4 समूहों में विभाजित कर 4 समूह में से एक बार 2 समूह, तीन समूह में एक बार 1 समूह इत्यादि अनुसार चलाने का निर्णय लिया जाता है।

**परियोजना के लिये पंजाब से हिमालय की नदियों का पानी रेगिस्तान तक पहुँचाया गया है। इस अद्भुत कार्य में किन समस्याओं का सामना करना पड़ा।**

इस नहर प्रणाली का निर्माण करना एक अकल्पनीय कार्य था। यह ऐसा क्षेत्र था जहाँ न आबादी थी, न पीने का पानी था तथा सड़कें, संचार व यातायात के साधन भी नहीं थे। कार्मिकों के लिये रहने, खाने-पीने की व्यवस्था नहीं थी। अत्यन्त विषम जलवायु, 49-50 डिग्री तापमान व भयंकर आंधियों में काम करना अत्यन्त मुश्किल था।

प्रारम्भ में परियोजना के निर्माण के लिये निर्माण सामग्री, मशीनरी, ईटों/टाइलों के निर्माण के लिये कोयले की व्यवस्था भी काफी कठिन कार्य था, किन्तु तत्समय की राज्य व केन्द्र सरकारों के आपसी सामंजस्य व सभी कार्यकारी संगठनों के दृढ़ संकल्प व कड़ी मेहनत से इस अद्भुत परियोजना के निर्माण का स्वप्न साकार हुआ। ●



## बेहतर जल प्रबंधन : लापोड़िया गांव

जयपुर जिले में दूध के नजदीक स्थित लापोड़िया गांव में ग्रामीणों ने जल प्रबंधन का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है। इससे गांव में चारों तरफ हरियाली और खुशहाली नजर आ रही है। गांव में ग्रामीणों ने जगह-जगह जल प्रबंधन की बेहतर व्यवस्था की है। इससे गांव में सिंचाई व पेयजल की बेहतर उपलब्धता हुई है। 2-3 सालों में लापोड़िया गांव का चारागाह पूरी तरह से विकसित हो गया। इसके असर से धीरे-धीरे दुधारू पशुओं की तादाद बढ़ने लगी और दूध के उत्पादन में अच्छी-खासी बढ़ोतरी हुई। गांव में सुचारु रूप से चल रही दूध की डेयरी इसका सबूत है। गांव में दुग्ध व्यवसाय अच्छा चल पड़ा। परिवार के उपयोग के बाद बचे दूध को सरस डेयरी को बेचा गया, जिससे अतिरिक्त आय हुई। इससे कितने ही परिवार जुड़े और आज स्थिति यह है कि दो हजार की जनसंख्या वाला यह गांव प्रतिदिन 1600 लीटर दूध सरस डेयरी को उपलब्ध करा रहा है। उनके परिवार के लोग भी पशुपालन से जुड़कर आमदनी कर रहे हैं। ग्रामीणों के प्रयासों से गांव का भू-जल स्तर बढ़ा। लापोड़िया गांव में 103 कुएँ हैं। 40 तालाब ऐसे हैं, जिनका पानी किसी मौसम में नहीं सूखता। हर साल गांव से सामूहिक जल यात्रा निकलती है। यह यात्रा तमाम गाँवों का भ्रमण कर जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करती है। ●

छाया चित्र: सविता चौहान





## ईसरदा बांध पेयजल परियोजना

# ई

सरदा बांध बनास नदी के लेटीट्यूड 26 डिग्री 6 मिनट 30 सैकण्ड नॉर्थ एवं लॉन्गिट्यूड 76 डिग्री 0 मिनट 30 सैकण्ड ईस्ट में राजधानी जयपुर से लगभग 125 किमी. वाया टोंक एवं टोंक से 25 किमी. दूर बीसलपुर बांध के डाउन स्ट्रीम में ग्राम बनैठा, तहसील उनियारा, जिला टोंक के पास बनास नदी पर बनाया जा रहा है, जो बीसलपुर बांध से लगभग 60 किमी. दूरी पर है। इस परियोजना की मूल प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग 530.00 करोड़ रुपये की जारी की गई थी। इसके पश्चात भूमि अवाप्ति अधिनियम 2013 लागू होने पर परियोजना का संशोधित परियोजना प्रतिवेदन राशि 1856 करोड़ रुपये का तैयार किया गया।

ईसरदा बांध परियोजना का निर्माण दो चरणों में किया जाना निर्धारित किया गया है। जिसमें प्रथम चरण में डेम निर्माण कार्य पूर्ण भराव तल 262.00 मीटर तक पूर्ण किया जाना है। किन्तु पानी का भण्डारण आर.एल. 256.00 मीटर तक ही किया जाना है। (आर.एल. 256.00 मीटर तक बांध की पानी भराव क्षमता 3.24 टी.एमसी. है)। बांध से जिला दौसा के 5 शहरों एवं 1079 ग्रामों (तहसील लालसोट के 302 ग्राम, बसवा तहसील के 229 ग्राम, महुआ तहसील के 161 ग्राम, दौसा तहसील के 248 ग्राम, सिकराय तहसील के 139 ग्राम) में पेयजल आपूर्ति एवं जिला सवाईमाधोपुर के 1 शहर व 177 ग्रामों को

**अजय त्यागी**

अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जल संसाधन

पीने के पानी की आपूर्ति की जानी है जिसमें बौलीं तहसील के 99 ग्राम, चौथ का बरवाड़ा तहसील के 17 ग्राम एवं मलारना डूंगर तहसील के 61 ग्राम सम्मिलित हैं। इस प्रकार कुल दोनों जिलों के 6 शहरों एवं 1250 ग्रामों में लगभग 24.55 लाख लोगों को पेयजल आपूर्ति इस बांध से किया जाना है।

इस बांध के निर्माण से टोंक जिले को भी अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा अपस्ट्रीम में पानी भराव से भू-गर्भ जल स्तर में बढ़ोतरी होगी एवं पानी की गुणवत्ता में भी सुधार होगा, साथ ही पेयजल के स्रोत भी रिचार्ज होंगे। जिससे टोंक के अपस्ट्रीम में स्थित ग्राम एवं शहरों को भी पेयजल उपलब्ध होगा।





द्वितीय चरण में बांध की पूर्ण भराव क्षमता आर.एल. 262 मीटर (भराव क्षमता 10.77 टी.एम.सी) तक पानी संग्रहित किया जावेगा।

ईसरदा बांध परियोजना निर्माण की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (प्रथम चरण) बजट हैड स्टेट प्लान ग्रामीण में राशि 1038.65 करोड़ की जारी की गई। परियोजना की तकनीकी स्वीकृति राशि 666.70 करोड़ 06.10.2017 को जारी की गई।

ईसरदा बांध निर्माण परियोजना का कार्यदेश राशि 615.17 करोड़ का 21.12.2018 को जारी किया गया।

वर्तमान में बांध के 28 ब्लॉकों एवं लेफ्ट साइड विंग वॉल एन.ओ.एफ. ब्लॉकों की मिट्टी खुदाई का कार्य हो चुका है तथा इन सभी ब्लॉकों में सीमेंट-कंक्रीट का कार्य प्रगतिरत है। बांध का लगभग 35 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है तथा बांध के पूर्ण होने की संभावित तिथि अक्टूबर, 2023 नियत है।

बांध के बांयी ओर में लगभग 3 किमी. का मिट्टी का बांध बनाया जावेगा। इसी प्रकार दांयी ओर में लगभग 749 मीटर मिट्टी का बांध एवं 2 पहाड़ियों के बीच में प्रथम सैडल बांध 324 मीटर एवं दूसरा सैडल बांध 354 मीटर का बनाया जावेगा। मिट्टी का बांध बनाने का कार्य प्रगतिरत है।

बांध के ओवरफ्लो में 28 रेडियल गेट लगाये जायेगे जो 15.50 मी. x 13 मी. के होंगे। इसमें दो स्टॉप लॉग गेट एवं गेन्ट्री क्रेन लगायी जाएगी। रेडियल गेटों का संचालन स्काडा सिस्टम से किया जाएगा।

### वन भूमि प्रत्यावर्तन

बांध के प्रथम चरण के निर्माण में 117.866 हैक्टेयर वन भूमि डूब में आयेगी। जिसकी वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा द्वितीय/अन्तिम वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति दिनांक 04.10.2019 को जारी की जा चुकी है।

### भूमि अवाप्ति

बांध के प्रथम चरण में पानी के भराव क्षेत्र में 12 ग्रामों की भूमि एवं परिसम्पत्तियां प्रभावित होंगी। प्रथम चरण में बांध एलाइनमेन्ट एवं डूब क्षेत्र के अन्तर्गत टोंक जिले के 08 गांव एवं सवाई माधोपुर जिले के 4 गावों की भूमि प्रभावित होगी।

बांध के प्रथम फेज में आर.एल 256 मीटर तक पानी भरे जाने पर बांध एलाइनमेन्ट एवं डूब क्षेत्र अन्तर्गत कुल 1214.136 हैक्टेयर भूमि अवाप्ति की जानी है, जिसमें से 500.69 हैक्टेयर निजी भूमि एवं 595.58 हैक्टेयर राजकीय भूमि तथा 117.866 हैक्टेयर वन भूमि है।

बांध एलाइनमेन्ट में आने वाले 12 गावों के भूमि/परिसम्पत्ति अवाप्ति हेतु राशि रुपये 95.59 करोड़ रुपये के अवार्ड जारी किये जा चुके हैं तथा अतिरिक्त कलेक्टर (पुनर्वास) एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी, बीसलपुर परियोजना, देवली द्वारा संबंधित खातेदारों को मुआवजे का भुगतान किया जा रहा है।

बांध के द्वितीय चरण में पानी के भराव क्षेत्र में 37 ग्रामों की भूमि एवं परिसम्पत्तियां प्रभावित होंगी। जिसमें प्रथम चरण के 12 ग्राम भी सम्मिलित हैं। उक्त सभी 25 ग्राम टोंक जिले के डूब क्षेत्र में आएंगे जिनके द्वितीय चरण के मुआवजे की कार्यवाही प्रगतिरत है। द्वितीय चरण हेतु एस्टीमेट/डीपीआर तैयार की जा रही है।

### पुनर्वास

पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन नीति का अनुमोदन संभागीय आयुक्त अजमेर द्वारा किया जा चुका है। पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु विभाग द्वारा ग्राम मोहम्मद नगर पंचायत टेंयर अरनियामाल टोंक में 10 हैक्टेयर, ग्राम बनेठा तह. उनियारा में 21.57 हैक्टेयर, ग्राम शिवाड़ तह. चौथ का बरवाड़ा जिला सवाईमाधोपुर 4.51 हैक्टेयर एवं ग्राम ईसरदा तह. चौथ का बरवाड़ा जिला सवाईमाधोपुर में 5.0 हैक्टेयर भूमि आवंटित की है। आवंटित भूमि पर विस्थापितों हेतु कॉलोनियों का प्लान तैयार कर आवश्यक सुविधाओं हेतु निर्माण कार्य प्रगतिरत है। ●





## परवन वृहद् बहुउद्देशीय परियोजना बदलेगी हाड़ौती की तस्वीर

**रा**जस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। यहां की भौगोलिक विषमता में अरावली के पहाड़ से लेकर रेगिस्तान और मैदान से लेकर चंबल की घाटियां तक आती हैं। राज्य का कुल क्षेत्रफल 342.67 लाख हैक्टेयर है। इतने बड़े भू-भाग में से लगभग 272.11 लाख हैक्टेयर क्षेत्र कृषि योग्य है, जो कि देश के कृषि योग्य क्षेत्र का लगभग 14 प्रतिशत है। इसके विपरीत राजस्थान में पीने और सिंचाई योग्य पानी की उपलब्ध मात्रा बहुत कम है। प्रदेश में देश के कुल सतही जल का मात्र 1.16 प्रतिशत ही उपलब्ध है। भूगर्भीय जल भी समय के साथ गहराई में चला गया है, जिसका दोहन दुष्कर कार्य है। राजस्थान का बड़ा हिस्सा इससे प्रभावित है। प्रदेश में बारहमासी नदियों का भी अभाव है। इन कारणों से वर्षा ही एकमात्र ऐसा विकल्प रह गया है जिसका जल संग्रहित कर प्रदेश की जल जरूरतों को पूरा किया जा सके। राजस्थान में वर्षा जल को अधिक से अधिक मात्रा में संग्रहित करने के लिए वृहद् बहुउद्देशीय सिंचाई और पेयजल परियोजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है। परवन वृहद् बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना एक महत्वपूर्ण परियोजना है।

परवन वृहद् बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना कोटा, बारां एवं झालावाड़ जिले के लिए अतिमहत्वपूर्ण परियोजना है। इस परियोजना के पूर्ण होने से इन तीनों जिलों के निवासियों को पेयजल, सिंचाई, विद्युत एवं वन्य जीवों को लाभ मिलेगा। इस परियोजना के अन्तर्गत तीनों जिलों के कुल 637 गांवों में 2.01 लाख हैक्टेयर में सिंचाई सुविधा तथा कुल 1821 गांवों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। परियोजना के अन्तर्गत जल के उपयोग हेतु सम्पूर्ण सिंचित क्षेत्र को स्काडा नियंत्रित प्रेशराइज्ड पाइप द्वारा फव्वारा सिंचाई पद्धति के माध्यम से सिंचित किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना की विद्युत आवश्यकता की आपूर्ति सोलर पावर प्लांट से की जायेगी। राज्य सरकार द्वारा परियोजना के लिए 7355.23 करोड़ की पुनः संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है।

### परवन बांध एवं परियोजना से लाभ

इस परियोजना के अन्तर्गत 490 मिलियन घन मीटर क्षमता का मीटर ऊंचा कंक्रीट बांध में 16x15 मीटर साइज के 15 रेडियल गेट्स का निर्माण किया जा रहा है। परियोजना से 2 लाख 1 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना के अन्तर्गत 317 मिलियन घनमीटर जल सिंचाई हेतु आरक्षित कर कोटा, बारां एवं झालावाड़ जिलों के 637 ग्रामों में 2.01 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में दाब आधारित पाइपों से फव्वारा पद्धति से सिंचाई हेतु 4 से 5 हैक्टेयर तक के सब चक तक सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी और परियोजना में शत प्रतिशत सिंचाई माइक्रो इरीगेशन पर आधारित होगी।

परियोजना में कोटा, बारां एवं झालावाड़ जिलों के 1821 ग्रामों

आलोक आनंद

सहायक निदेशक, जनसंपर्क



में पेयजल सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। क्षेत्र में रहने वाली बड़ी आबादी को पीने के लिए साफ पानी उपलब्ध हो जाएगा। परियोजना के अन्तर्गत 79 मिलियन घनमीटर जल उद्योगों हेतु आरक्षित कर 2970 मेगावाट विद्युत उत्पादन हेतु उपलब्ध कराया जायेगा। सोलर मिलियन घनमीटर जल शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को उपलब्ध कराया जायेगा।

### सिंचाई के लिए आधारभूत ढांचा

इस परियोजना के अन्तर्गत 2.01 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को सिंचित किये जाने का प्रावधान है। इस हेतु दो मुख्य नहर एवं दो फीडरों की सहायता से 2.01 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को प्रेशराइज्ड पाइप तकनीक के माध्यम से सिंचित किया जाना प्रस्तावित है। सिंचित क्षेत्र विकास का कार्य दो पैकेज प्रथम चरण व द्वितीय चरण में किया जा रहा है जिसमें से प्रथम चरण के अन्तर्गत 1.31 लाख हैक्टेयर में सिंचाई हेतु दो मुख्य नहरों, 61 पम्पिंग स्टेशन, डी.आई. व एच.डी.पी.ई. पाइप नेटवर्क तथा डिग्रियों में 3 घण्टे तक का जल अवरोध, 200 हैक्टेयर तक की स्काडा नियंत्रित आउटलेट प्रबन्धन प्रणाली एवं 4से 5 हैक्टेयर तक के सबचक पर जल उपयोक्ता संगमों द्वारा मानवीय रूप से संचालित एवं नियंत्रित सिंचाई प्रणाली का विकास किया जाना है। ●



# मुख्यमंत्री ने दी रोजा इफ्तार की दावत

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर पवित्र रमजान महीने के 21वें रोजे पर दी मुबारकबाद



मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेशभर से आए रोजेदारों से मुलाकात की और उन्हें तहेदिल से रमजान की मुबारकबाद दी। दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज के सैयद गुलाम किबरिया ने मुख्यमंत्री की दस्तारबंदी की। रोजा इफ्तार के बाद जयपुर शहर मुफ्ती कारी अब्दुल सत्तार ने मगरिब की नमाज अदा कराई। अजमेर से दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज की ओर से सैयद गुलाम किबरिया और मदरसा बोर्ड के पूर्व



अध्यक्ष मौलाना फज्जे हक ने नमाज से पूर्व मुल्क और सूबे की खुशहाली, तरकी के लिए दुआ करवाई। रोजा इफ्तार से पहले मगरिब की नमाज के लिए जनाब हाफिज वली मोहम्मद ने अजान दी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत राजस्थान स्टेट हज कमेटी द्वारा हज हाउस, करबला में आयोजित दावत-ए-इफ्तार कार्यक्रम में भी शामिल हुए। ●

## प्रदेश में हर पात्र व्यक्ति को मिले सामाजिक सुरक्षा



**रा**ज्य सरकार समाज के वंचित, असहाय सहित सभी जरूरतमंदों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान कराने के लिए संवेदनशील है। राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के प्रति गंभीरता दिखाते हुए हर पात्र व्यक्ति को विभिन्न योजनाओं के जरिये लाभ पहुंचाया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, पालनहार योजना, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। इससे

जरूरतमंदों को आगे बढ़ने के अवसर मिल रहे हैं।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत राज्य में 92 लाख पेंशनर्स को पेंशन दी जा रही है। हर जरूरतमंद को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिले, इसे सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने संबंधित विभागाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। ●



# माउंट आबू के जलाशय



## जन जीवन से जल का गहरा नाता

**मा**उंट आबू के जलाशयों व जलस्रोतों से माउंट आबू में नया पारिस्थितिकी तंत्र विकसित हुआ है।

जब बात जलाशयों की हो तो माउंट आबू की प्रसिद्ध नक्की झील का विचार सबसे पहले मन में आता है, ये झील कई पौराणिक और ऐतिहासिक घटनाओं की साक्ष्य तो रही ही है, साथ ही वर्तमान में माउंट आबू का प्रथम आकर्षण भी कहलाती है। इस झील के बारे कई कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। उसमें से सबसे प्रमुख इसके नाम को लेकर है, जिसके बारे में कहा जाता है की बालम रसिया और कुँवारी कन्या (जिनको शंकर भगवान और माता पार्वती का रूप माना जाता है) की कहानी में लगी एक शर्त के कारण इस झील को बालम रसिया द्वारा रातोंरात नाखूनों से एक रात में खोदा गया था। इस लोक कथा पर जयशंकर प्रसाद द्वारा एक लघु कहानी “बालम रसिया” भी लिखी गयी। इस झील के किनारे कई ऐतिहासिक स्थान मौजूद हैं जिनमें से विवेकानंद गुफा सबसे प्रसिद्ध है। इस गुफा में बैठकर स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था, साथ ही इस झील में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की

**डॉ. रविन्द्र गोस्वामी**  
भारतीय प्रशासनिक सेवा

अस्थियां भी गांधी घाट पर प्रवाहित की गई थी।

इस झील का आध्यात्मिक महत्त्व भी है और ये कहा जाता है कि नज़दीक ही स्थित प्राचीन रघुनाथ मंदिर में माता सीता की मूर्ति इस झील में विद्यमान है। गरासिया जनजाति के लिए तो ये झील की तरह पवित्र है और साल में एक बार भरने वाले मेले में गरासिया जनजाति द्वारा अपने पूर्वजों की अस्थियां यहाँ प्रवाहित की जाती हैं।

हाल ही में इस झील के किनारे राजस्थान के सबसे ऊँचे तिरंगे का लोकार्पण भी किया गया और साथ ही लघु रूप में राजस्थान के 7 आश्चर्यों को भी स्थापित किया गया है। यहाँ गर्मी के मौसम में शाम के समय में एक अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। गर्मी में जब पानी की सभी जगह कमी हो जाती है तब फलाहारी चमगादड़ों द्वारा झुंड में शाम को पानी पीने का दृश्य रोमांचित करने वाला होता है।

नक्की झील के तरह ही मिनी नक्की झील भी माउंटआबू में विद्यमान है जो कि ओरियाँ गाँव की ओर जाते समय रास्ते में आती है।

इसी तरह माउंट आबू का ऊपरी कोदरा बाँध अपनी अलग छाप रखता है। यह बांध प्राचीन अभियांत्रिकी कौशल को दर्शाता है और इस बाँध में गुरुत्वाकर्षण बल का उपयोग कर किसी समय पूरे माउंट आबू को 24 घंटे पानी की आपूर्ति की जाती थी, इस बांध का निर्माण सर आर्थर लोथियन के प्रयासों से हुआ था। इस बाँध का आज भी जलापूर्ति में उपयोग किया जाता है। एक और महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल ट्रेवर्स टैंक है, जिस का निर्माण तत्कालीन सिरोही महाराजा श्री केसर सिंह ने कराया था। इस टैंक की खूबी है कि यहाँ आपको कई दुर्लभ वन्यजीव दिख जाएँगे, यहाँ पूर्व में मगरमच्छ छोड़े गए थे, जो आज भी यहाँ मौजूद है।



आप जब माउंटआबू जाएं तो यहाँ के जल जीवन को देख कर महसूस करें कि “जल जीवन” का “जन जीवन” से कितना गहरा नाता होता है। ●





# राजस्थान की गौरवमयी गाथा

Some Interesting Facts about Rajasthan

## राजस्थान में जल-संकट समाधान

जल संरक्षण की परम्परागत विधियाँ – कल, आज और कल

**रा**जस्थान के लोगों ने पानी की प्रत्येक बूँद का व्यवस्थित उपयोग करने वाली कई लोक-कथाएँ एवं आस्थाएँ विकसित की हैं, जिनके आधार पर ही अमृतरूपी प्राकृतिक जल का संचय करके कठिन परिस्थितियों वाले जीवन को सहज बनाया है। पश्चिमी राजस्थान में जल के महत्त्व पर पंक्तियाँ लिखी गई हैं उनमें पानी को घी से बढ़कर बताया गया है। परम्परागत तरीकों से राज्य के निवासियों ने अपने क्षेत्र के अनुरूप जल भण्डारण के विभिन्न तरीकों को विकसित किया है। ये पारम्परिक जल संग्रहण की प्रणालियाँ काल की कसौटी पर खरी उतरती हैं।

इनके विकास में ऐतिहासिक तत्वों के साथ ही विविध भौगोलिक कारकों का प्रभाव भी है। वस्तुतः राजस्थान एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ वर्ष भर बहने वाली नदियाँ नहीं हैं। यहाँ पानी से सम्बन्धित समस्याएँ, अनियमित तथा कम वर्षा और नदियों में अपर्याप्त पानी को लेकर उत्पन्न होती हैं।

ये प्रणालियाँ विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक परिस्थितियों के कारण अपने प्रभावशाली स्वरूप में उभरीं। साथ ही इनका विकास भी स्थानीय पर्यावरण के अनुसार हुआ है। इसलिये सम्पूर्ण भारत में राजस्थान की जल संचयन विधियाँ अपनी अलग विशेषता रखती हैं।



“घी ढुळयाँ म्हारो की नीं जासी।  
पाणी ढुळयाँ म्हारो जीव बळे।।”

**डॉ. गोरधन लाल शर्मा**  
राजस्थान प्रशासनिक सेवा

भारत में मानसून की अनियमितता के कारण सम्पूर्ण देश में कहीं-न-कहीं अनावृष्टि, अतिवृष्टि एवं आंशिक वृष्टि का खतरा बना रहता है। राजस्थान की जलाभाव के मामले में विशिष्ट स्थिति है। राज्य का अधिकांश भाग रेगिस्तान है जहाँ प्रायः वर्षा बहुत कम होती है।

राजस्थान में स्थापत्य कला के प्रेमी राजा-महाराजाओं तथा सेठ-साहूकारों ने अपने पूर्वजों की स्मृति में अपने नाम को चिरस्थायी बनाने के उद्देश्य से इस प्रदेश के विभिन्न भागों में कलात्मक बावड़ियों, कुओं, तालाबों, झालरों एवं कुंडों का निर्माण करवाया। राजस्थान में पानी के कई पारम्परिक स्रोत हैं, जैसे- नाड़ी, तालाब, जोहड़, बन्धा, सागर, समंद एवं सरोवर। कुएँ पानी के महत्त्वपूर्ण स्रोत हैं। राजस्थान में कई प्रकार के कुएँ पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त बावड़ी या झालरा भी हैं जिनको महत्त्वपूर्ण माना जाता है।

राजस्थान में जल संचयन की परम्परागत विधियाँ उच्च स्तर की हैं। इनके विकास में राज्य की धार्मिक एवं सांस्कृतिक मान्यताओं का प्रमुख योगदान है। जहाँ प्रकृति एवं संस्कृति परस्पर एक दूसरे से समायोजित रही हैं। राजस्थान के किले तो वैसे ही प्रसिद्ध हैं पर इनका जल प्रबन्ध विशेष रूप से देखने योग्य है तथा ये शिक्षाप्रद भी हैं।

जल संचयन की परम्परा वहाँ के सामाजिक ढाँचे से जुड़ी हुई हैं तथा जल के प्रति धार्मिक दृष्टिकोण के कारण ही प्राकृतिक जलस्रोतों को आज भी पूजा जाता है। जल उचित प्रबन्धन हेतु पश्चिमी राजस्थान में आज भी सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में पराती में चौकी रखकर उस पर बैठकर स्नान करते हैं जिससे शेष बचा पानी अन्य उपयोग में आ सके।

राजस्थान में जल संचयन की निम्नांकित संरचनाएँ महत्वपूर्ण हैं-

### खड़ीन और धोरा

खड़ीन जल संरक्षण की पारम्परिक विधियों में बहुउद्देशीय व्यवस्था है। यह परम्परागत तकनीकी ज्ञान पर आधारित होती है। खड़ीन मिट्टी का बना बाँधनुमा अस्थायी तालाब होता है, जो किसी ढालवाली भूमि के नीचे निर्मित करते हैं। इसके दो तरफ मिट्टी की पाल उठाकर तीसरी ओर पत्थर की मजबूत चादर लगाई जाती है। खड़ीन की यह पाल धोरा कहलाती है। धोरे की लम्बाई पानी की आवक के हिसाब से कम ज्यादा होती है। पानी की मात्रा अधिक होने पर खड़ीन को भर कर पानी अगले खड़ीन में प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार धीरे-धीरे यह पानी सुखाकर खड़ीन की भूमि को भी कृषि योग्य बनाया जा सकता है।



खड़ीनों में पानी को ढालू स्थानों पर एकत्रित करके फसलें ली जाती हैं। जिस स्थान पर पानी एकत्रित होता है उसे खड़ीन तथा इसे रोकने वाले बाँध को खड़ीन बाँध कहते हैं। खड़ीनों द्वारा शुष्क प्रदेशों में बिना अधिक परिश्रम के फसलें ली जा सकती हैं क्योंकि इसमें न तो अधिक निराई-गुड़ाई की आवश्यकता होती है, न ही रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों की। इन खड़ीनों के पास कुआँ भी बनाया जाता है, जिसमें खड़ीन से रिसकर पानी आता रहता है, जिसका उपयोग पीने के लिये किया जाता है।

### नाड़ी या पोखर और आगोर

नाड़ी एक प्रकार का पोखर होता है, जिसमें वर्षा जल संचित होता है। इसका जलग्रहण क्षेत्र विशिष्ट प्रकार का नहीं होता है। राजस्थान में सर्वप्रथम पक्की नाड़ी के निर्माण का विवरण सन् 1520 में मिलता है, जब राव जोधाजी ने जोधपुर के निकट एक नाड़ी बनवाई थी। पश्चिमी राजस्थान में लगभग प्रत्येक गाँव में कम से कम एक नाड़ी अवश्य मिलती है। नाड़ी बनवाते समय वर्षा के पानी की मात्रा एवं जलग्रहण क्षेत्र को ध्यान में रखकर ही जगह का चुनाव करते हैं। रेतीले मैदानी क्षेत्रों में नाड़ियाँ 3 से 12 मीटर गहरी होती हैं।



इनका जलग्रहण क्षेत्र (आगोर) भी बड़ा होता है। यहाँ पर रिसाव कम होने के कारण इनका पानी सात से दस महीने तक चलता है। केन्द्रीय शुष्क अनुसन्धान संस्थान, जोधपुर के एक सर्वेक्षण के अनुसार नागौर, बाड़मेर एवं जैसलमेर में पानी की कुल आवश्यकता में से 37.06 प्रतिशत जरूरतें नाड़ियों द्वारा पूरी की जाती हैं। वस्तुतः नाड़ी भू-सतह पर बना प्राकृतिक स्थान होता है, जिसमें वर्षा जल आकर संग्रहित होता रहता है।

### बावड़ी या वापी

राजस्थान में कुआँ व सरोवर की तरह ही वापी (बावड़ी) निर्माण की परम्परा अति प्राचीन है। यहाँ पर हड़प्पा युग की संस्कृति में बावड़ियाँ बनाई जाती थीं। प्राचीन शिलालेखों में बावड़ी निर्माण का उल्लेख प्रथम शताब्दी से मिलता है प्राचीनकाल में अधिकांश बावड़ियाँ मन्दिरों के सहारे बनी हैं। बावड़ियाँ और सरोवर प्राचीनकाल से ही पीने के पानी और सिंचाई के महत्वपूर्ण जलस्रोत रहे हैं। आज की तरह जब घरों में नल अथवा सार्वजनिक हैण्डपम्प नहीं थे तो गृहणियाँ प्रातःकाल एवं सायंकाल कुएँ, बावड़ी व सरोवर से ही पीने का पानी लेने जाया करती थीं। बावड़ी का जल लवणीय नहीं होता है क्योंकि इनका निर्माण बड़े ही वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है।



राजस्थान में बावड़ी निर्माण का प्रमुख उद्देश्य वर्षा जल का संचय रहा है। आरम्भ में ऐसी भी बावड़ियाँ हुआ करती थीं जिनमें आवासीय व्यवस्था हुआ करती थी। यदि समय रहते इनका जीर्णोद्धार किया जाये तो ये बावड़ियाँ जल संकट का समाधान बन सकती हैं।

### झालरा

झालरों का कोई जलस्रोत नहीं होता है। यह अपने से ऊँचाई पर स्थित तालाबों या झीलों के रिसाव से पानी प्राप्त करते हैं। इनका स्वयं का कोई आगोर नहीं होता है। झालरों का पानी पीने के लिये उपयोग में नहीं आता है वरन् इनका जल धार्मिक रीति-रिवाजों को पूर्ण करने, सामूहिक स्नान एवं अन्य कार्यों हेतु उपयोग में आता है।



अधिकांश झालरों का आकार आयताकार होता है, जिनके तीन ओर सीढ़ियाँ बनी होती हैं। अधिकांश झालरों का वास्तुशिल्प अब्दुत प्रकार का होता है। जल संचय की दृष्टि से ये अपना विशिष्ट महत्त्व रखते हैं। इनके संरक्षण के प्रति तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है।

### तालाब और बेरी

वर्षा पानी को संचित करने के लिये तालाब प्रमुख स्रोत रहे हैं। प्राचीन समय में बने इन तालाबों में अनेक प्रकार की कलाकृतियाँ बनी हुई हैं। इन्हें हर प्रकार से रमणीय एवं दर्शनीय स्थल के रूप में विकसित किया जाता रहा है। इनमें अनेक प्रकार के भित्ति चित्र इनके बरामदों, तिबारों आदि में बनाए जाते हैं। कुछ तालाबों की तलहटी के समीप कुआँ बनाते थे जिन्हें 'बेरी' कहते हैं।



तालाबों की समुचित देखभाल की जाती थी जिसकी जिम्मेदारी समाज पर होती थी। आध्यात्मिक भावना से बने तालाबों का रख-रखाव अच्छा हुआ है, परन्तु आज इन तालाबों की भी स्थिति दयनीय हो चुकी है तथा इन पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। राजस्थान के

कई ग्रामीण क्षेत्रों में जलाभाव के कारण ग्रामीण महिलाओं को बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है, जिसके कारण उनका अधिकांश समय जल की व्यवस्था करने में ही चला जाता है।

### झीलें

राजस्थान में जल का परम्परागत ढंग से सर्वाधिक संचय झीलों में होता है। यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध झीलें स्थित हैं, जिनके निर्माण में प्रशासन एवं आम जनता का सम्मिलित योगदान रहा है। झीलों के महत्त्व का अनुमान झीलों की विशालता से लगाया जा सकता है।



उदयपुर में विश्व प्रसिद्ध झीलों- जयसमंद, उदयसागर, फतेहसागर, राजसमंद एवं पिछोला में काफी मात्रा में जल संचय होता रहता है। इन झीलों से सिंचाई के लिये जल का उपयोग होता है। इसके अतिरिक्त इनका पानी रिसकर बावड़ियों में भी पहुँचता है जहाँ से इसका प्रयोग पेयजल के रूप में करते हैं।

### टोबा

नाड़ी के समान जल संग्रह केन्द्र 'टोबा' कहलाता है। इसका आगोर नाड़ी से अधिक गहरा होता है। इस प्रकार थार के रेगिस्तान में टोबा महत्त्वपूर्ण स्रोत है। सघन संरचना वाली भूमि जिसमें पानी रिसाव कम होता है, टोबा निर्माण हेतु उपयुक्त स्थान माना जाता है। इसका ढलान नीचे की ओर होना चाहिए। इसके जल का उपयोग मानव व मवेशियों द्वारा किया जाता है। टोबा के आसपास नमी होने के कारण प्राकृतिक घास उग जाती है।



मानसून के आगमन के साथ ही लोग सामूहिक रूप में टोबा के पास ढाणी बनाकर रहने लगते हैं। सामान्यतया: टोबाओं में 7-8 माह तक पानी ठहरता है। राजस्थान में प्रत्येक गाँव में पशुओं एवं जनसंख्या के हिसाब से टोबा बनाए जाते हैं। एक टोबे के जल का उपयोग उसकी संचयन क्षमता के अनुसार एक से बीस परिवार तक कर सकते हैं। इसके संरक्षण का कार्य विशिष्ट प्रकार से किया जाता है।

### कुंड, कुंडी या टांका

कुंडी राजस्थान के रेतीले ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षाजल को संग्रहित करने की महत्वपूर्ण परम्परागत प्रणाली है, इसे कुंड भी कहते हैं। इसमें संग्रहित जल का मुख्य उपयोग पेयजल के लिये करते हैं। यह एक प्रकार का छोटा सा भूमिगत सरोवर होता है। जिसको ऊपर से ढँक दिया जाता है। कहीं-कहीं पर प्रदूषण को रोकने के लिये इस जलस्रोत के ढक्कन पर ताला भी लगा दिया जाता है। इसका निर्माण मरुभूमि में किया जाता है, क्योंकि मरुस्थल का अधिकांश भूजल लवणीयता से ग्रस्त होने के कारण पेय रूप में स्वीकार्य नहीं है। अतः वर्षाजल का संग्रह इन कुंडों में किया जाता है।



कुंड का निर्माण सभी जगह होता है पहाड़ पर बने किलों में, पहाड़ की तलहटी में, घर की छत पर, आँगन में, मन्दिर में, गाँव में, गाँव के बाहर बिलग क्षेत्र में तथा खेत आदि में। इसका निर्माण सार्वजनिक रूप में लोगों, सरकार तथा निजी निर्माण स्वयं व्यक्ति या परिवार विशेष द्वारा करवाया जाता है। निजी कुंड का निर्माण घर के आँगन या चबूतरे पर किया जाता है, जबकि सामुदायिक कुंडियाँ पंचायत भूमि में बनाई जाती हैं जिनका उपयोग गाँव वाले करते हैं। गाँवों में इन बड़े कुंडों के पास दो खुले हौज भी बनाते हैं जिनकी ऊँचाई भी कम रखी जाती है। इनका उद्देश्य आसपास से गुजरने वाले भेड़-बकरियों, ऊँट एवं गायों आदि की पेयजल व्यवस्था के लिये होता है।

### पारम्परिक स्रोतों के जल में सन्दूषण

कई क्षेत्रों का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि अधिकांश स्थानों पर बावड़ियों के ऊपर वृक्ष थे जिनसे पत्तियाँ आदि गिरने के कारण

जैविक नाइट्रेट की वृद्धि हो गई तथा अन्य स्थानों पर इन जलस्रोतों पर मानवीय प्रदूषण की समस्या देखी गई। मुख्यतया ये अतिक्रमण, दुकान एवं मकानों के कचरे डालने के रूप में देखे गए। इन प्रदूषित जलस्रोतों में घुलनशील ऑक्सीजन तथा जैव ऑक्सीजन माँग का मानक भी अधिक पाया गया। जिसके कारण हुई अत्यधिक शैवाल वृद्धि ने जलीय जीवों के जीवन को भी खतरे में डाल दिया है। अतः जो पारम्परिक जलस्रोत अतीत में पेयजल आपूर्ति में सक्षम थे, आज प्रदूषण के शिकार हो रहे हैं।

### ऊपरी छत से वर्षा जल संरक्षण (रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग)

हमारे देश में प्रतिवर्ष भू-सतह पर गिरने वाले 4000 घन किलोमीटर जल का आधे से दो तिहाई हिस्सा बेकार बह जाता है। दूसरी तरफ तेजी से बढ़ती जनसंख्या के लिये भूजल का अन्धाधुन्ध दोहन तथा पक्के मकानों, फर्शों व पक्की सड़कों के रूप में फैलता कंक्रीट का जंगल भूजल भण्डार के लिये खतरे का संकेत दे रहा है। भूजल के अत्यधिक दोहन से उत्पन्न हुए गम्भीर संकट का मुकाबला करने के लिये देश के कई भागों में वर्षा के पानी के संग्रह की योजना तैयार की गई है। इसके तहत वर्षाकाल में भवनों की छतों से बहने वाले पानी को संग्रहित करने की अनिवार्यता लागू की जा रही है। वस्तुतः छत (रूफटॉप) से वर्षा जल संग्रहण तकनीक गिरते भूजल को बढ़ाने का कारगर कदम है।

आधुनिक युग में भवनों की छत प्रायः आर.सी.सी., आर.बी.सी. की बनाई जाती है जिसमें छत पर एकत्रित होने वाली वर्षा और अन्य जल की निकासी का प्रबन्ध भली-भाँति किया जा सकता है। कई जगह इसको कुछ निकासी छिद्रों द्वारा नीचे गिरने दिया जाता है और कुछ भवनों में इसे पाइप के द्वारा भू-तल में उतारा जाता है। इस तरह बहने वाले वर्षाजल को पाइप के माध्यम से कुएँ तक लाया जाता है।

### प्राकृतिक जल संचय हेतु सुझाव

- वर्षा के पानी को स्थानीय जरूरत एवं भौगोलिक स्थितियों के हिसाब से संचित किया जाये।
- भूमि के अन्दर जल पहुँचाने के लिये जहाँ भी सम्भव हो छोटे-छोटे तालाब बनाकर उनमें वर्षाजल एकत्रित करें।

इस पाइप का एक किनारा वर्षाजल एकत्रित करने वाले पाइप से बाँधा जाता है तथा दूसरा किनारा कुएँ के अन्दर सुविधाजनक स्थिति में छोड़ा जाता है। कुएँ में छोड़े जाने वाले सिरे के मुँह पर एक प्लास्टिक की महीन जाली लगाई जाती है जिससे कि धूल मिट्टी के कणों को कुएँ में जाने से रोका जा सके। इस विधि को अपनाने से कुओं के जलस्तर में वृद्धि देखी गई। अतः वर्षा जल को छत से एकत्रित करना भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण का प्रभावी कदम है। ●





## पाली में रेल से पानी : सरकार के भगीरथ प्रयास

राज्य सरकार ने रेलवे को किया भुगतान

**मा** रवाड़ के पाली जिले में रीते परम्परागत जल स्रोतों से पानी के संकट के मद्देनजर राज्य सरकार के भगीरथी प्रयास अब प्यासे हलक तर कर रहे हैं। पाली शहर में लोगों को सुचारु पेयजल आपूर्ति के लिए राज्य सरकार ने विशेष पहल कर जोधपुर से पाली तक अप्रैल से वाटर ट्रेन शुरू कर की है। वाटर ट्रेन 50-50 हजार लीटर क्षमता के 40 टैंकरों में 20 लाख लीटर पानी के साथ जोधपुर से रवाना होकर पाली पहुंच रही है। वाटर ट्रेन प्रतिदिन तीन फेरे कर जोधपुर से पाली को रोजाना 60 लाख लीटर की जलापूर्ति की जा रही है। ट्रेन के फेरों सहित अन्य जल स्रोतों से पाली शहर में कुल 25 मिलियन लीटर प्रतिदिन पानी दिया जा रहा है।

जोधपुर के तखत सागर से प्राप्त जल को वाटर ट्रेन से परिवहन की व्यवस्था शुरू की गई है। आगामी मानसून में जंवाई बांध में वांछित मात्रा में जल आवक होने तक जोधपुर से पाली शहर के लिए वाटर ट्रेन का निर्बाध संचालन होगा। जिला प्रशासन और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) शहरवासियों तक पेयजल पहुंचाने के लिए जुटा हुआ है। इधर, जोधपुर से रोहट के मध्य नई पाइप लाइन के लिए भी 28 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी की गई है।

**पहले फेरे में 20 लाख लीटर पानी पहुंचा**

करीब तीन लाख लोगों की प्यास बुझाने के लिए पहले फेरे में ही रेल 20 लाख लीटर पानी लेकर पहुंची। प्रतिदिन तीन रैक संचालित किए जा रहे हैं। प्रत्येक रैक में 40 वैगन हैं और प्रत्येक वैगन में 50

पाली शहर में रोजाना 80 लाख लीटर की जलापूर्ति

डॉ. राजकमल पारीक  
वरिष्ठ पत्रकार

हजार लीटर पानी है। हालांकि जवाई बांध में पानी में आवक तक ट्रेन चलेगी लेकिन फिलहाल निर्धारण 106 दिन का किया गया है, जिसमें 400 से अधिक फेरे होंगे।

**ऐसे है व्यवस्था**

यह ट्रेन पाली मारवाड़ रेलवे स्टेशन पर टैंकरों को खाली करती है। यह पानी पाली-जोधपुर मार्ग स्थित विभागीय हैडवर्क्स की 52 डिगियों में एकत्रित किया जा रहा है और वहां से पंप के जरिए पाली नगर के सिटी टैंक के पास स्थित फिल्टर प्लांट पर भेजा जाता है।



फिल्टर होने के बाद पानी की सप्लाई पाली शहर में की जा रही है। राज्य सरकार ने पाली शहर के लिए इस वाटर ट्रेन के संचालन के लिए जोधपुर में रेल टैंकों में जल भरने के लिए तखत सागर एवं न्यू पावर हाउस डिस्कॉम में पम्प की स्थापना की है। वहीं भगत की कोठी स्थित रेलवे यार्ड में हाईड्रेंट स्थापित किये गए हैं। इसी प्रकार पाली मारवाड़ रेलवे स्टेशन पर टैंकों को खाली कर पाली-जोधपुर मार्ग स्थित विभागीय हैड वर्क्स की डिग्गी में एकत्र करने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही करीब 52 कुएं अधिग्रहण किए हैं और आठ ट्यूबवैल से मदद मिल रही है। अन्य पारंपरिक स्रोतों की पहचान कर अधिग्रहण की तैयारी है। टैंकों पर जीपीएस लगा रखे हैं ताकि वे निगरानी में रहे।

### सुचारू आपूर्ति के लिए सरकार प्रतिबद्ध

राज्य सरकार गर्मी के मौसम में प्रदेश के सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध एवं सुचारू पेयजल आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के निर्देशन में प्रदेश में विशेष चिन्हित गांव, शहर और कस्बों में जनता की पेयजल आवश्यकताओं व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। इसी के तहत पाली शहर के लिए विशेष ट्रेन से जल परिवहन आरम्भ कर दिया गया है। वहीं प्रदेश के सभी क्षेत्रों में संचालित पेयजल परियोजनाओं के माध्यम से नियमित आपूर्ति के साथ ही अतिरिक्त आवश्यकता वाले क्षेत्रों में सड़क मार्ग पर टैंकों के माध्यम से भी जल परिवहन किया जा रहा है।



छाया: हेमलत कुमावत

### राज्य सरकार ने किया रेलवे को अग्रिम भुगतान

पाली शहर में वाटर ट्रेन से जल परिवहन के लिए रेलवे ने प्रत्येक फेरे का शुल्क 4 लाख 5 हजार 972 रुपये निर्धारित किया है। राज्य सरकार ने जोधपुर से पाली नगर को पेयजल परिवहन के लिए रेलवे को शुल्क सहित राज्य आपदा प्रबन्धन मद से 17.71 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी की है। इस प्रकार पाली शहर में वाटर ट्रेन से जल परिवहन के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रतिदिन 16 लाख रुपये की राशि वहन की जाएगी। सरकार की ओर से रेलवे को 50 हजार रुपये की आरंभिक रजिस्ट्रेशन फीस के अलावा छह फेरों की अग्रिम राशि जमा करवा दी गई है। ●



## जैसलमेर में जल प्रबन्धन के प्रतीक

## गढ़सीसर...जैतसर...

**था** र मरुस्थल की स्वर्ण नगरी जैसलमेर में जल प्रबन्धन का अपना इतिहास रहा है। कभी चौमासे के 120 दिन की औसतन अवधि महज दस दिन में सिमट जाती थी। ऐसे में प्रकृति प्रदत्त इस अमृत को सहेजने में लोगों ने सामूहिक श्रमदान से घड़सीसर के सृजन का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है।

महारावल घड़सी ने विक्रम संवत् 1391 (सन् 1335)में अपनी देखरेख में सरोवर निर्माण कार्य शुरू किया। सरोवर से निकली मिट्टी से पाल की ऊंचाई बढ़ रही थी। अचानक एक दिन पाल पर घड़सी का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस वज्रपात के बावजूद रानी विमला ने अपने पति का सपना पूरा किया और इसका नामकरण हुआ घड़सीसर। घड़सीसर से गढ़सीसर और गढ़ीसर नाम के प्रचलन से इस कृति का अपना इतिहास है जिसमें लोगों का दर्द छिपा है। यहां पाल पर राजा-रानी की छतरी है।

पर्यावरणविद् स्वर्गीय अनुपम मिश्र की चर्चित पुस्तक “आज भी खरे हैं तालाब” में घड़सीसर का नैसर्गिक चित्रण इन शब्दों में किया गया है- “रेत में दो रंग है। नीला रंग है पानी का और पीला रंग है तीन चार मील के तालाब का और कोई आधी गोलाई में बने घाट, मंदिरों, बुर्ज और बारादरी का। लेकिन यह सपना दिन में दो बार बस एक ही रंग में दिखाई देता है। उगते और डूबते समय के सूरज में गढ़सीसर अपना मन भर सोना उड़ेल देता है। मन भर यानी मापतौल वाला मन नहीं अपितु सूरज का मन भर जाए इतना...। घड़सीसर की जुगलबंदी में एक अद्भुत गीत बन गया जो पनिहारियों के अधरों से गुंजित होता है।

कभी तीन मील लम्बे और एक मील चौड़े आगार वाले इस तालाब का आगोर(जलग्रहण क्षेत्र) लगभग 120 वर्ग मील क्षेत्र में फैला हुआ था। थार में बूंद-बूंद जलराशि संजोने की साधना में कभी अतिवृष्टि से नेष्टा (ओवरफ्लो) के बहाव की नौ तालाबों- नौताल, गोविन्दसर, जोशीसर, गुलाबसागर, भाटियासर, सूदासर, मोहतासर, रतनसर और किसनघाट तक जुगलबंदी की गई थी। थोड़ा पानी बच भी गया तो कुएंनुमा बेरियों में समा जाता। आधुनिकीकरण एवं विकास के समयचक्र ने घड़सीसर को अतिक्रमण, सौन्दर्यीकरण व बाजारीकरण

गुलाब बत्रा  
वरिष्ठ पत्रकार



की राह दिखाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है।

गढ़सीसर जल है तो जीवन है..का प्रतीक है। लेकिन जैतसर तो थार में इंजीनियरिंग कौशल का नायाब नमूना है। करीब 175 साल के अंतराल पर बनाया गया जैतसर बांधनुमा तालाब पर बड़े बगीचे की वजह से बड़ा बाग के नाम से लोकप्रिय है। इस कृति में पत्थरों से बने बांध को जैसलमेर की उत्तर दिशा में खड़ी पहाड़ियों से आने वाले पानी को रोकने का माध्यम बनाया गया। जैतसर के दूसरी तरफ पानी से सिंचित बड़ा बाग दोनों का विभाजन है। कहने को बांध की दीवार देखने में अच्छी खासी चौड़ी सड़क है जिसकी सीमा घाटी पार कर सामने की पहाड़ी तक है। इस दीवार के नीचे सिंचाई नाली है। नहर बांध की तरफ सीढ़ीनुमा रूप लिए हुए हैं। यह करिश्मा है अभियांत्रिकी दक्षता का।

यद्यपि जलवायु परिवर्तन के परिचक्र में जैसलमेर अतिवृष्टि के साथ बाढ़ का भी साक्षी बना। भारत की प्राचीन सभ्यता, संस्कृति का प्रवाह नदी तटों से जुड़ा है। इसलिए शहरों की बसावट में जल प्रबन्धन प्राथमिकता रही। थार मरुस्थल के इस भाग में इस परम्परा को जीवंत रखा गया। रियासत के दीवान मोहता के हस्तलिखित ग्रंथ में 344 तालाबों के उल्लेख का इतिवृत्त इतिहासकार श्री नंदकिशोर शर्मा ने संजोया हुआ है। ●





## पोकरण परमाणु परीक्षण से पर्यटन को लगे पंख

**रा**जस्थान के सीमावर्ती जैसलमेर जिले के पोकरण में 48 वर्ष पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के कार्यकाल में भारत के प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण के श्रीगणेश के साथ ही थार मरुस्थल में पर्यटन युग का नया मार्ग प्रशस्त हुआ।

भारतीय काल गणना के अनुसार संयोगवश बुद्ध पूर्णिमा थी, उस रविवार 18 मई, 1974 के दिन। समूची दुनिया को चौकाने तथा विश्व के छठे शक्तिशाली परमाणु देश का गौरव हासिल करने वाले इस गोपनीय मिशन का सांकेतिक नाम था- "स्माइलिंग बुद्ध"। हमारी सेना की देखरेख में जोधपुर-जैसलमेर राजमार्ग स्थित पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज में निकटवर्ती लोहारकी-मंगला गांव से जुड़े इलाके में रविवार सुबह परमाणु परीक्षण की सफलता पर शांति के उद्घोषक महात्मा बुद्ध भी मुस्करा उठे। थार मरुस्थल के जनजीवन में इसे भूकम्प का एहसास समझा गया। रेडियो तथा समाचार पत्रों से लोगों को परमाणु परीक्षण की जानकारी मिली।

हमारी परमाणु क्षमता से विचलित अमरीका ने भारत को परमाणु सामग्री एवं ईंधन की आपूर्ति रोकने की घोषणा में तनिक भी

गुलाब बत्रा

वरिष्ठ पत्रकार

हिचकिचाहट नहीं की। आर्थिक प्रतिबंधों की परवाह न करते हुए श्रीमती गांधी ने इसे शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण करार देकर दुनिया को अपनी मंशा जताने में विलम्ब नहीं किया। लेकिन इस ऐतिहासिक घटनाक्रम के संदर्भ में इंदिराजी ने पर्यटकों के लिए जैसलमेर में अनूठी शिल्पकला के खजाने के द्वार खोल दिए। अब जैसलमेर विश्व पर्यटन मानचित्र पर अपनी धाक जमा चुका है। भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बार्क) के तत्कालीन निदेशक डॉ. राजा रमन्ना एवं वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक श्री होमी सेठना की अगुवाई में लगभग 75 वैज्ञानिकों एवं इंजीनियरों की टीम ने करीब सात वर्ष तक अथक परिश्रम से परमाणु जगत में शामिल होने वाले इस मिशन को पूरा कर स्वतंत्र भारत के इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठ लिखा। इस टीम में मिसाइल मैक नाम से प्रख्यात एवं भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम भी शामिल थे।

जिस कुशलता से भारत के प्रथम परमाणु परीक्षण से जुड़े मिशन को रहस्य के पर्दे में रखा गया, उसी तर्ज पर इंदिरा जी ने परीक्षण के कुछ दिनों पश्चात परमाणु परीक्षण स्थल का अवलोकन किया। परमाणु



वैज्ञानिक डॉ. राजा रमन्ना एवं डॉ. होमी सेठना भी उनके साथ थे। इस ऐतिहासिक स्थल के दर्शन से अभिभूत इंदिरा जी ने दिल्ली लौटने से पहले अकस्मात जैसलमेर में पत्थरों पर कलात्मक नक्काशी से सुसज्जित पटवों की हवेलियों सहित पुरामहत्त्व की अन्य इमारतों को देखा। शिल्प सौन्दर्य के इस भंडार को देखकर वे आश्चर्यचकित थी। लेकिन इन हवेलियों की जर्जर अवस्था देखकर वे चिंतित हो गईं। शिल्प कला की अनुरागी इन्दिरा जी ने अपने मानस में कला वैभव की समृद्ध सम्पदा के संरक्षण-संवर्धन का संकल्प ले चुकी थी।

पोकरण-जैसलमेर के दौर के बाद राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री हरिदेव जोशी को पत्र लिखकर तत्कालीन प्रधानमंत्री ने पुरातत्व महत्त्व के राष्ट्रीय स्मारकों की सार-संभाल के लिए प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। इन्दिरा जी के करिश्माई नेतृत्व की बदौलत स्वर्णनगरी जैसलमेर की तस्वीर बदलते देर नहीं लगी। समयचक्र में आकर्षक नक्काशीदार हवेलियों की आभा तथा अन्य दर्शनीय स्थलों की प्रसिद्धि सात समन्दर पार तक जा पहुंची है और विदेशी पर्यटकों की आवाजाही बढ़ गई। परमाणु परीक्षण के छह माह पश्चात ही प्रदर्शित फिल्म सोनार किला ने तो जैसलमेर को बंगाली पर्यटकों का तीर्थधाम बना दिया। एक फ्रांसीसी इंजीनियर की फोटोग्राफी के कमाल ने फ्रेंच पर्यटकों के लिए इसे काफी मशहूर बना डाला। जैसलमेर के इतिहासकार श्री नंदकिशोर शर्मा के अनुसार इससे पहले इंग्लैण्ड निवासी माइकल ब्रूमेन ने डॉक्यूमेन्ट्री “मिरेकल ऑफ इण्डिया” बनाई। वर्ष 1979 से फरवरी माह में आयोजित होने वाले मरू मेले से इस थार की विश्व पर्यटन मानचित्र पर गहरी छाप अंकित हो गई है।

अल सुबह सूर्य की किरणों से प्रदीप्त त्रिकूट पर्वत पर ग्यारहवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में बने इस दुर्ग की 99 बुर्जे स्वर्ण सी चमक उठती है तो रात्रि में फ्लड लाइट्स के प्रकाश में इस लिविंग फोर्ट का नजारा देखते ही बनता है। दुर्ग के प्रवेश द्वार से ही पीले पत्थरों पर नयनाभिराम

नक्काशी तथा जगह-जगह प्रदर्शित हस्तकलात्मक वस्तुओं पर पर्यटकों की निगाहें ठहर जाती हैं।

### पर्यटन

समन्दर की तरह सम के सुनहरी रेतीले टीलों पर ऊंटों पर सवार पर्यटकों में सूर्यास्त (सनसेट) देखने की होड़ लगती है। सम के इलाके में पर्यटक टैंट नगरी में रहना पसंद करते हैं और संगीत नृत्य से सजी महफिलें कैम्प फायर की शान बढ़ाते हैं। गढ़सीसर झील में नौका विहार ऐतिहासिक धरोहर कुलधरा, बड़ा बाग, जैन मंदिर, तनोट माता मंदिर तथा अन्य दर्शनीय स्थल पर्यटकों को आकर्षित करने की प्रतिस्पर्धा में रहते हैं।

अन्तरराष्ट्रीय सीमा से सटे घोटारू में मिट्टी की ईंटों से अरेबियन शैली में निर्मित 700 साल पुराना किला है। इस किले में माताजी के मंदिर में पूजा अर्चना होती है। किशनगढ़ किला 100 साल पुराना है जो सिंध एवं मुगल शैली के मिश्रण का प्रतीक है। दोनों किले सीमा सुरक्षा बल के पास है। फॉसिल्स पार्क थार की प्राचीनता को दर्शाता है। एक जमाने में जैसलमेर खाड़ी देशों एवं भारत के बीच व्यापारिक मार्ग था। जैसलमेर के साथ-साथ पड़ोसी सीमावर्ती बाड़मेर जिले के दर्शनीय स्थल भी पर्यटकों के आकर्षण के केन्द्र बनते जा रहे हैं। किराडू तथा जूना मंदिर इत्यादि स्मारक खजुराहों की याद दिलाते हैं। नाकोड़ा जी जैन मतावलम्बियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है।

फिल्मों की शूटिंग के लिए जैसलमेर आकर्षण का केन्द्र है तो पिछले दशक में सेलीब्रेट मैरिज डेस्टिनेशन के रूप में भी इसे प्रसिद्धि मिली। कभी मृग-मरीचिका को दर्शाते धोरों के गर्म सन्नाटे को चीरती हवाओं ने अब पवन ऊर्जा के नाते इस स्वर्ण नगरी को पंखा नगरी उपनाम दिया है तो प्राकृतिक गैस तेल के उत्खनन में प्रदेश की अर्थव्यवस्था की मजबूती में भागीदार भी बनाया है। परमाणु परीक्षण के पश्चात तो पोकरण “माइल स्टेशन” पर आ गया है तो इंदिरा गांधी नहर के अमृत ने थार को सर्वस्व बनाने की राह दिखाई है।

राजस्थान सरकार की नई पर्यटन नीति के अन्तर्गत पर्यटन केन्द्रों के विस्तारीकरण से प्रदेश में भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक स्थलों से जुड़े विभिन्न अंचलों में पर्यटन को नई गति मिली है। ●



छाया : सुजस

जून-2022 की आकाशीय स्थिति

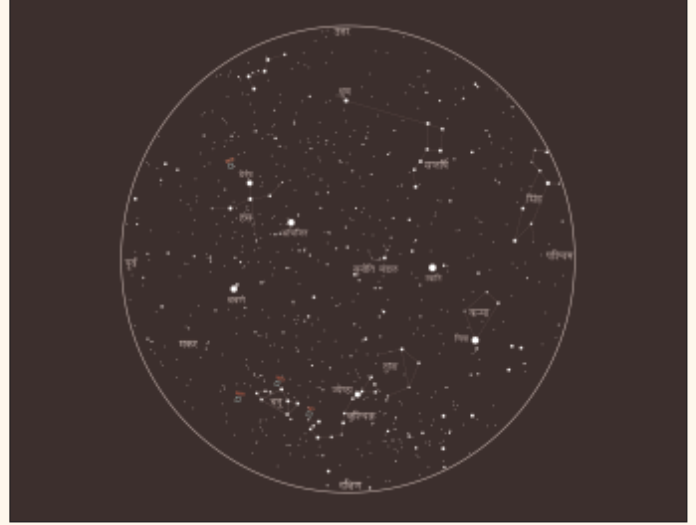
## जून में पांच ग्रहों को देखने का सुनहरा अवसर

सन्दीप भट्टाचार्य

सहायक निदेशक, बिड़ला तारामण्डल

**ज**ून माह में पाँचों प्रमुख ग्रहों को भोर में देखने-पहचानने का सुनहरा अवसर बना है। बुध, शुक्र, मंगल व शनि एक के ऊपर एक पूर्वी क्षितिज से लेकर मध्याकाश तक तड़के बहुत ही जोरदार नजारा पेश कर रहे हैं। टिमटिमाते झिलमिलाते तारों के बीच इन्हीं पाँच ग्रहों को हम कोरी आँखों से देख पाते हैं। कोरी आँखों की बजाय बाइनोक्युलर या एक छोटी दूरबीन से हर ग्रह की एक अलग ही खासियत नजर आ जाती है। जैसे शुक्र की कलाएं, बृहस्पति के चन्द्रमाएं और शनि के वलय आदि। सूर्य का नजदीकी सबसे छोटा ग्रह बुध 2 जून से पूर्वी क्षितिज पर भोर में अपनी जगह बनायेगा। 3 जून से यह सीधी गति में और 16 जून को क्षितिज से अपनी अधिकतम ऊँचाई पर होगा। सुबह-सवेरे दमकते शुक्र से आधी ऊँचाई पर, जरा बायीं ओर, बुध को ढूँढ़ने का प्रयास सफलता दिलवा सकता है। 27 जून को पूर्वी क्षितिज पर चाँद के थोड़ा ही नीचे, दांयी ओर, इसे देखा जा सकता है। सबसे चमकदार ग्रह शुक्र पिछले कई महीनों से भोर का तारा बनकर पूर्वी क्षितिज पर दीप्तिमान है। अभी यह क्षितिज पर दिनों दिन नीचे सरक रहा है और सुबह-सवेरे पूर्वी क्षितिज पर सभी को अपनी ओर खींच रहा है। दरअसल रात्रि आसमान में चन्द्रमा के बाद यही सबसे चमकदार पिण्ड है। महारथी मंगल मीन राशि के धुंधले तारों के बीच भोर से भी पहले पूर्वी क्षितिज पर दिख जायेगा। लाल ग्रह को गुलाबी रंगत में आप पहचान लेंगे। तारों की झिलमिलाहट खत्म होने के पहले पूर्वी क्षितिज पर नजर दौड़ाइये, बृहस्पति के पीछे, यानी पूर्व में, इसे ढूँढ़ना आसान है। ग्रहराज बृहस्पति मीन राशि में पहुँच चुका है। यह एक राशि में एक वर्ष रहता है। सबसे विशाल ग्रह आधी रात बाद पूर्वी क्षितिज पर उदय हो रहा है और सुबह तक लगभग मध्याकाश में पहुँच जायेगा। सफेद उज्वल आभा में यह तारों से काफी ज्यादा चमकदार है और एक छोटी दूरबीन से इसके इर्द-गिर्द घूम रहे चार चन्द्रमा भी दिख जाते हैं। वलयधारी शनि मकर को छोड़ कुम्भ राशि में पहुँच चुका है। 4 जून से यह वक्री हो रहा है। ग्रहों में सबसे सुन्दर शनि धीरे-धीरे संध्याकाश की ओर बढ़ रहा है। यह आधी रात से पहले ही पूर्वी क्षितिज पर दिखने लगेगा और भोर तक मध्याकाश को पार करता पश्चिमी भाग में पहुँच रहा है। एक छोटी दूरबीन से शनि के सुन्दर वलय भी नजर आ जाते हैं। चन्द्रमा 18 को शनि, 21 को बृहस्पति, 22 को मंगल, 26 को शुक्र, और 27 जून को बुध ग्रह के आसपास होगा। इस विधि से भी ग्रहों को पहचानकर उन पर नजर रखी जा सकती है।

स्वाति अपनी अजीब सी झिलमिलाहट से सभी को आकर्षित करता है। चित्रा कन्या राशि का चमकदार तारा है। धुँधले तारों का एक आकर्षक समूह है - सुनीतिमण्डल। इसमें एक राजमुकुट की छवि उभरती है। डेनेब, अभिजित (Vega) व श्रवण (Altair), इन तीनों



को आपस में जोड़ने पर ग्रीष्म त्रिकोण (Summer Triangle) की रचना होती है। ग्रीष्म त्रिकोण की पूर्वी क्षितिज पर मौजूदगी बता रही है कि गर्मी अपने पूरे शबाब पर है। दक्षिणी आसमान में सुन्दरतम व व्यवस्थित तारामण्डल वृश्चिक राशि को पहचानने का अच्छा अवसर है। इसमें लाल रंग का चमकदार नक्षत्र है - ज्येष्ठा (Antares)। वृश्चिक के ठीक की नोक पर है एम-7। अँधेरी आसमान में कोरी आँखों से ही नजर आने वाली इस पुंज में 30 से भी ज्यादा तारों हैं। इसी आकार प्रकार का एक और प्रकाशपुंज धनु राशि में है। धनु राशि वृश्चिक की पूँछ के पास एक चाय की केतली के आकार में नजर आती है। धनु से पूर्व में एक गोलाकार तारापुंज है - एम-55। सिंह राशि पश्चिमी क्षितिज पर अस्त होने वाली है। सिंह से पूर्व में कन्या व तुला राशि के तारे दमक रहे हैं।

21 जून से सूर्य दक्षिणायन (Summer Solstice) होगा। उस दिन मध्याह्न में दक्षिणी क्षितिज से सूर्य की ऊँचाई अधिकतम होगी। फलतः सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटी रात होगी। सूर्य जून में वृषभ से निकल मिथुन राशि में प्रवेश करता है।

**जून माह में सूर्योदय व सूर्यास्त का समय निम्न प्रकार है-**

	जयपुर		श्रीगंगानगर		उदयपुर		जैसलमेर	
	उदय	अस्त	उदय	अस्त	उदय	अस्त	उदय	अस्त
03 जून	5:33	7:19	5:34	7:33	5:49	7:25	5:56	7:42
15 जून	5:33	7:23	5:33	7:38	5:49	7:29	5:56	7:45
30 जून	5:36	7:27	5:37	7:41	5:52	7:32	5:59	7:49

प्रस्तुत मानचित्र 1 जून को रात्रि 11:30 बजे, 15 जून को 10:30 बजे व 30 जून को रात्रि 09:30 बजे की जयपुर शहर से आकाशीय स्थिति दर्शाता है। ●

## CHIEF MINISTER SHRI ASHOK GEHLOT COMMITTED TO WOMEN EMPOWERMENT



**C**hief Minister, Shri Ashok Gehlot's commitment and aspiration has always been for the empowerment of women in the state. Shri Gehlot believes that without the cooperation of women, which constitutes half of the population, the development and progress of any society, state or country cannot even be thought of. This thinking of the Chief Minister is reflected in every step taken in the direction of women empowerment during his three tenures as Chief Minister of Rajasthan.

Under the dynamic leadership of Shri Gehlot, various schemes are being implemented in the state to promote the honour and dignity of women in every field. New policies for women's upliftment and empowerment have been implemented as per the need of time, while at the same time changes have been made in the old policies to meet the changing scenario and challenges. Shri Gehlot presented the first Gender Based Budget in the year 2012-13. Similarly, two women policies issued in the state have also been issued during his tenure. The Chief Minister's confidence in the administrative ability of women is also evident from the fact that two women chief secretaries in the state have also been appointed during the tenure of his government.

The Chief Minister believes that today the time has changed. Now women cannot be kept confined in a veil (purdah). He had said in a public program that until the purdah system is not given up, women will never be able to move forward. He called upon the women that they will have to move forward with courage & determination and at every step they will find the state government supporting and standing with the women. The State Government, under the leadership of Shri Gehlot, has taken

Alka Saxena

Additional Director & Editor Sujas

effective steps to stop the incidents of atrocities and harassment on women. An officer of the rank of Deputy Superintendent of Police has been deputed in each district, who would look after the cases related to harassment of women. With a view to ensure that no girl child is deprived of education in the state, girl child education has been made free.

Various programs, policies and schemes are being implemented for the upliftment and empowerment of women in order to make them self-reliant and economically independent. At the same time efforts have been made to safeguard their health. The Chief Minister says that the State Government will leave no stone unturned to empower women.

**IM Shakti** With a view to empower and strengthen women, Shri Gehlot launched five schemes of "Indira Mahila Shakti IM Shakti Nidhi" worth one thousand crore rupees for five years on the completion of the first year of the state government. A fund was created in the name of Former Prime Minister Smt. Indira Gandhi from where women and self-help groups will be able to get loans up to one crore rupees to make them self-reliant.

**Women's Education** According to the Chief Minister, an educated woman is the basis for the progress of the entire family. In the four budgets presented by Shri Gehlot so far, many announcements have been made to promote education from villages to Dhans. If there are more than 500 girls in the higher secondary classes of a school, a provision has been made to open a women's college there. Over 33 new women's colleges have been opened in the last three years. To encourage girl child education, schemes like "Indira Gandhi Priyadarshini Swarnim Udan Yojana", "Aapki Beti Yojana", "Gargi Protsahan and Balika Protsahan" Yojana are being implemented.



**State Women Policy 2021** The State Women Policy 2021 has been implemented with the aim of empowering women and providing them a conducive environment to ensure equality, security, participation and other rights of women and girls in the society. Under this policy, focus has been on the overall development of women and girl child, to ensure their survival, to ensure their access to quality health and nutritional services, to promote their well-being, economic, political and social empowerment, their protection along with taking necessary steps in areas like preparation of roadmap on issues like gender responsive budgeting, gender transformative approach etc. While implementing the State Women's Policy, Shri Gehlot had said that the women's policy would inspire crores of women of the state to move forward in every field. This policy will prove to be a milestone in the direction of women empowerment.

**Jagriti-Back to Work Yojana** Working women have to leave the job many times after marriage to take care of the family and other reasons. The Jagriti-Back to Work scheme has been started by the state government to provide such women with the help of the private sector opportunities to get jobs again or work from home. Under this scheme, about 15 thousand women will be provided opportunities for re-job or "work from home", with the help of the private sector in the next three years.

**IM Shakti Udaan Yojana** IM Shakti Udaan Yojana has been implemented by the state government to give wings to the dreams of women keeping their health in priority. Chief Minister Shri Ashok Gehlot's message is that "menstruation" is not a disease, nor is it a matter of shame and hesitation. Society has to change its thinking now, we have to protect the health of women. It is a necessary step in the direction of dignity, respect and privacy of women. In the first phase of "UDAN" scheme, free distribution of 12 sanitary napkins per month to about 26 lakh girl students studying in upper primary, secondary, higher secondary government schools of the state and about 3 lakh adolescent girls in the age group of 18-45 at 1 to 10 identified Anganwadi centres in rural areas was done. In the second phase of the scheme, sanitary napkins will be provided free of cost to all adolescent girls and women in the age group of 18-45 years at Anganwadi centres and other places in all gram panchayats of the state.

#### Major announcements for women in the Budget:2022-23

- With a view to providing education facilities to the girl child near home and reducing the dropouts in schools, 389 secondary level, one thousand 846 upper primary level schools and 115 primary level Girls Schools in the state would be upgraded on merit basis in a phased manner.
- Along with this, in order to provide better facilities of higher education to the girls, it has been announced to open 36 Girls colleges in 19 districts of the state. Apart from this, it has been proposed to upgrade Government Women's Colleges, Taranagar-Churu and Sarwad-Ajmer to PG

colleges and to open new subjects and faculties in 25 Girls' colleges.

- Rajiv Gandhi Knowledge Service & Innovation Hubs are to be opened in Jaipur, Jodhpur and Kota at a cost of Rs.200-200 crores to provide the Plug & Play Facility to service sector, MSMEs and Startups at affordable rates. It has been proposed to identify separate places for women in these Hubs and build W-Hubs.
- For women who can contribute to the livelihood of their families by doing work from home, it has been proposed to start Chief Minister Work from Home-Job Work. Over 20 thousand women are proposed to be benefitted under this scheme in the current financial year and Rs 100 crore will be spent under the scheme.
- In the year 2020-21, Indra Gandhi Maternity Nutrition Scheme was started for Pratapgarh, Banswara, Udaipur, Dungarpur and Baran districts. Enlarging the scope of this scheme, it has been announced to implement it in the entire state. About 3 lakh 50 thousand pregnant women will be benefitted every year and Rs 210 crore will be spent under the scheme.
- Savitri Bai Phule Girls Hostels will be opened with the aim of promoting girl child education. Under this, hostels will be opened in Jaisalmer Chordi-Dausa Nagola (Bhinay)-Ajmer, Tonk, Balotra-Barmer and Chitalwana(Sanchore)-Jalore during the current financial year.
- With a view to providing information about welfare schemes and benefits of government facilities to the eligible families sitting at home, it has been proposed to start the Chief Minister Digital Services Scheme. Under this, it has been announced that women heads of about one crore 33 lakh Chiranjeevi families will be provided smart phones with three years of internet connectivity. An annual expenditure of Rs 2 thousand 500 crore will be made under the scheme. This will also provide the facility of quick redressal of grievances along with getting all kinds of services. ●





# राजस्थान में नहरी पानी की ऑनलाइन मॉनिटरिंग में गंगानगर बनेगा नजीर

## गंग नहर स्काडा में नियंत्रण कक्ष स्थापित

**पे** यजल और नहरी पानी की समस्याओं को दूर करने के लिए राजस्थान सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जल संसाधन (आयोजना) एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग के मंत्री श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीय ने गांगानगर में राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजी परियोजना के अंतर्गत गंग नहर स्काडा नियंत्रण कक्ष का उद्घाटन किया।

रिलाइनिंग होने के बाद पेयजल और किसानों की नहरी पानी की समस्या दूर होगी। नहरी पानी की समस्याओं को निष्पक्ष तरीके से दूर करने के लिए सरकार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने नहरी तंत्र में सुधार के लिए 750 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री का प्रयास है कि अंतिम छोर तक पानी पहुंचे। राजस्थान सरकार नहरों में पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए लगातार पंजाब सरकार के संपर्क में है।

इसके जरिए नहरी पानी के वितरण की समस्या दूर होगी। फिरोजपुर फीडर की मरम्मत के लिए 200 करोड़ रुपये देने पर मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त किया गया।

### सात करोड़ की लागत से लगा स्काडा

7 करोड़ रुपये की लागत से गंग नहर और भाखड़ा सिंचाई प्रणाली में स्काडा सिस्टम लगाया गया है। कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी और किसानों के आय में इजाफा होगा। गंग नहर मुख्य फीडर के खखा, शिवपुर, कालूवाला, साधुवाली, नेतेवाला, सुलेमानकी, फकीरवाली, पीएस, डाबला, बाईफरकेशन, वाई, डी, डी साधुवाली और जेड हैड पर स्काडा सिस्टम लगाया है। गंग नहर मुख्य फीडर के हैडों पर एडीवीएम सेंसर युक्त मशीनें लगाई हैं जबकि हैडों से निकलने वाली वितरिकाओं में पानी की जांच लेवल सेंसर मशीनें करेंगी।

### स्काडा सिस्टम से होगा यह लाभ

स्काडा सिस्टम से नहर में प्रवाहित पानी व अन्य आंकड़े किसान

अनिल कुमार शाक्य  
जनसम्पर्क अधिकारी, श्रीगंगानगर



और आमजन इंटरनेट (सेटेलाइट) से किसी भी जगह या स्थान से देख सकेंगे। किसान अपने मोबाइल पर भी नहर में आने वाले पानी की जानकारी ले सकेगा। इससे सिंचाई प्रणाली पारदर्शी होगी। इसके साथ ही स्काडा से पानी प्रबंधन को बेहतर किया जा सकेगा। भाखड़ा और गंग नहर सिस्टम सिंचाई प्रणाली पारदर्शी करने और किसानों को पूरा पानी देने के उद्देश्य से लगाया जा रहा है। किसानों के साथ अधिकारी भी नहरों में चलने वाले पानी से हर समय अपडेट रहेंगे। स्काडा सिस्टम शुरू होने के बाद नहरों में पानी कम-ज्यादा को लेकर होने वाली शिकायतों से भी अवाम को राहत मिलेगी।

वहीं इंदिरा गांधी नहर परियोजना में पहले से ही स्काडा सिस्टम लगा हुआ है। यहां पर फीडर, मुख्य नहर, ब्रांच व सब ब्रांच नहरों के स्टेशनों पर अल्ट्रासोनिक उपकरणों से निरंतर पानी के प्रवाह का आंकलन किया जाता है। प्रोजेक्ट के इंजीनियर व कर्मचारी अपने फील्ड स्टेशनों पर और किसान इंटरनेट के जरिए लगातार जानकारी लेते हैं। ऐसे में नहर के अंतिम छोर पर मिलने वाले पानी की पूरी जानकारी मिलती है। यह सिस्टम किसानों के लिए भी काफी फायदेमंद है। ●

## गंग कैनाल की वेबसाइट, एंड्रॉयड एप और संदेश एप की लॉन्चिंग

**न** हरो में उपलब्ध पानी की निगरानी और उसके वितरण में अब तलक कई परेशानियां आती रही हैं। मसलन कभी नहर में पानी नहीं होता, तो कभी नहर में होने के बावजूद पानी किसानों तक नहीं पहुंच पाता। नहरी पानी के वितरण में भेदभाव जैसी बातें भी सामने आती रही हैं, लेकिन अब नहरी पानी की ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए

रेगुलेशन कंप्यूटेशन सिस्टम डवलप कर श्रीगंगानगर जिला राजस्थान के लिए नजीर बन गया है।

श्रीगंगानगर जिला प्रशासन की ओर से गंगनहर के रेगुलेशन को कंप्यूटराइज्ड किया गया है। इस सिस्टम के जरिए गंग नहर के पानी में उतार-चढ़ाव और नहर की सभी 23 वितरिकाओं के खुलने तथा बंद

होने जैसी जानकारी अब किसानों को ऑनलाइन उपलब्ध हो सकेंगी। राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र और जल संसाधन विभाग श्रीगंगानगर द्वारा तैयार इस वेबसाइट पर नहरी पानी की संपूर्ण जानकारी अपलोड की गई है। 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन “गंग कैनल रेगुलेशन कंप्यूटराइजेशन सिस्टम” को लॉन्च करते हुए जिला कलक्टर श्रीमती रुक्मिणी रियार सिहाग ने गंग कैनल की वेबसाइट, एंड्रॉयड एप और संदेश एप की लॉन्चिंग भी की। वेबसाइट गंगनहर के किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इससे नहरी पानी की उपलब्धता और उसके वितरण में अधिक पारदर्शिता आएगी। साथ ही, किसान भी नहर में पानी की उपलब्धता और उसके वितरण से अपडेट हो सकेंगे।

अब वेबसाइट के जरिए नहर किसानों से बात करेगी। गंग नहर के पोर्टल का प्रयास तभी सफल होगा, जब किसान इससे जुड़ेंगे और अपनी समस्याएं अधिकारियों से साझा करेंगे। किसानों के सुझाव से ही कमियों को दूर करते हुए पोर्टल को और बेहतर बनाने के प्रयास किसान होंगे। 6 महीने तक इस पोर्टल को अपनाएं और इसका उपयोग करें। पोर्टल और उससे मिलने वाली जानकारियां जिला प्रशासन व किसानों के लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होंगी। कई बार नहर में अचानक पानी की मात्रा कम होने या बढ़ जाने पर किसान आशंकित होते थे, लेकिन रेगुलेशन सिस्टम पोर्टल में यह आशंका नहीं रहेगी। भविष्य में नहरी पानी की सूचना देने के साथ-साथ पोर्टल के माध्यम से किसानों को सरकारी योजनाओं, मंडी भाव सहित उपयोगी जानकारी भी देने का प्रयास रहेगा।

मोबाइल ऐप पर अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करवाने के बाद किसान अपने क्षेत्र की नहर में कब, कितने दिन और कितनी मात्रा में पानी उपलब्ध होगा, जैसी जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे। इससे जहां एक

ओर नहरी पानी के वितरण में पारदर्शिता आएगी, वहीं किसानों को नहरों में पानी की उपलब्धता की जानकारी आसानी से मिल सकेगी। गंग नहर प्रणाली तंत्र के तकनीकी ऑटोमेशन एवं कंप्यूटराइजेशन के लिए वेबसाइट एवं एंड्रॉयड एप का (हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी) का निर्माण जिला कलक्टर के मार्गदर्शन-निर्देशन में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एवं जल संसाधन विभाग द्वारा किया गया है।

गंग नहर की वेबसाइट पर रेगुलेशन की रिपोर्ट हर 3 घंटे बाद अपडेट होगी। इसके साथ ही यह जानकारी भी दी जाएगी कि किस नहर में कितने दिन पानी चलेगा, पिछले 1 महीने और 1 वर्ष में कितने दिन पानी चला। कितने दिन निर्धारित मात्रा से अधिक पानी चला और कब नहर बंद रही। मोबाइल ऐप के जरिए हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी में जानकारी दी जाएगी।

### सभी वितरिकाओं के किसानों को एसएमएस से मिलेगी जानकारी

गंग नहर के रेगुलेशन सिस्टम के कंप्यूटराइज्ड होने से सबसे बड़ा फायदा नहर की वितरिकाओं से जुड़े किसानों को होगा। कंप्यूटराइज्ड रेगुलेशन सिस्टम की मदद से जल संसाधन विभाग गंग नहर की संबंधित वितरिकाओं के किसानों को एसएमएस भेजेगा, जिससे किसानों को वितरिकाओं के खुलने और बंद होने की सूचना समय रहते मिल जाएगी। किसानों को पता होगा कि उनकी पानी की बारी है या नहीं। अगर पानी में कमी की वजह से नहर या वितरिका बंद होती है तो उसकी वजह भी किसानों को पता होगी। इस व्यवस्था के सुचारू होने के बाद नहरी पानी से जुड़ी अन्य उपयोगी जानकारियों को किसानों तक पहुंचाने में जल संसाधन विभाग जल उपभोक्ता संघों के अध्यक्षों का भी सहयोग लेगा। ●





## जल जीवन मिशन ने बदली गांवों की तस्वीर और ग्रामवासियों की तकदीर

महिलाओं का मीलों का सफर हुआ कम, बच्चे जाने लगे समय पर स्कूल

“जल ही जीवन है” “जल है तो कल है” जैसी उक्तियां अक्सर वही लोग अनुभूत कर पाते हैं जिन्होंने कभी ना कभी पानी की समस्या का सामना किया हो या पानी की कमी महसूस की हो। ऐसे ही कुछ कहानियां हैं जयपुर जिले के पावटा ब्लॉक के भूरी भड़ाज गांव के ग्रामवासियों को अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता था। बच्चे समय पर स्कूल नहीं जा पाते थे। घर की औरतों का जल की जरूरतों को पूरा करने में समय अधिक लगने से खाना भी समय पर नहीं बन पाता था। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। अब जल जीवन मिशन के तहत हर घर में शुद्ध एवं ताजा पानी की उपलब्धता होने से हर समस्या का समाधान हो गया तथा इससे पूरे गांव के विकास को मानो पंख लग गये। ग्रामवासियों का जीवन सरस व सुगम हो गया है।

### जल जीवन मिशन ने कैलाश के जीवन में किया उजाला

54 वर्षीय कैलाश जांगिड़ जिन्हें 2018 में आंखों की परेशानी के कारण दिखना बंद हो गया था, इनकी पत्नी का देहांत 10 साल पहले ही हो गया था। कुछ समय बाद पिता का भी देहांत हो गया। वृद्ध माता एवं बच्चों की जिम्मेदारी कंधों पर थी, सारे घर का काम करके पानी भरना इनकी ही जिम्मेदारी थी, पानी भरने में इन्हें चार से पांच घंटे लग जाते थे। ये बहुत सालों से पानी के लिये परेशान थे, पांच सौ मीटर दूर से पानी भरकर लाना उसके बाद स्वयं भोजन बनाना, वृद्ध माता की सेवा करना नियमित दिनचर्या का हिस्सा थी। कभी



धर्मिता चौधरी  
जनसंपर्क अधिकारी

कभार नहीं दिखने के कारण ये गिर भी जाते थे। ऐसी परिस्थितियों में कैलाश का जीवन दुष्कर हो रहा था। जल जीवन मिशन ने इनके जीवन में उजाला भर दिया।

### जीवन हुआ सरल, जब घर आया जल जीवन मिशन

50 वर्षीय भगवती देवी पिछले 10 वर्षों से पानी के लिये परेशान थी। पति दैनिक मजदूरी करते हैं, भगवती देवी को एक किमी. दूर से पानी लाना पड़ता था, इसलिए न तो घर में समय पर खाना बन पाता था ना ही वह समय पर बच्चों को स्कूल भेज पाते थे। जल जीवन मिशन योजना आने के बाद घर में ही नल कनेक्शन हो गया, अब वे घर के दूसरे कार्य भी समय पर कर पाती हैं। इसी प्रकार की कहानियां 30 वर्षीय कृपा देवी, 55 वर्षीय प्रेम देवी, 37 वर्षीय सरोज देवी एवं 35 वर्षीय हंसा देवी की भी हैं, जो कि कई किमी. दूर से सिर पर घड़ा रख कर पानी लेकर आती थीं और उसके बाद घर के अन्य कार्य करती थीं, जिसकी वजह से ना बच्चे समय पर स्कूल जा पाते थे और ना ही पति काम पर। यहां तक कि खाना भी समय पर नहीं बन पाता था लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। जहां पहले पानी भरने में पांच-छह घंटे लग जाते थे अब वही पूरा पानी 30 मिनट में भर जाता है। बच्चे समय पर स्कूल जा पाते हैं, और पति समय पर अपने कार्य स्थल पर पहुंच जाते हैं। ●

## ऑपरेशन संबल बना सहारा

## जरूरतमंद लोगों को मिला सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं का लाभ



बनवारी लाल यादव  
जनसंपर्क अधिकारी

योजना की पात्रता रखते हैं लेकिन उन्हें लाभ नहीं मिल रहा है। अब तक ऐसे करीब 30 हजार लोगों की पहचान की जा चुकी है। दूसरे चरण में अधिकारियों द्वारा पात्रता वाली योजना में आवेदन करने के लिए मदद करते हैं। साथ ही, इससे संबंधित आवश्यक दस्तावेज बनाने में भी अधिकारियों द्वारा सहायता की जाती है। तीसरे चरण में संबंधित विभाग द्वारा आवेदन स्वीकृति के लिए मॉनिटरिंग की जाती है।

**ज**यपुर के सांगानेर पंचायत समिति के भमोरिया गांव की बादाम देवी का नाम उन लोगों में शुमार है, जिनका जीवन ऑपरेशन संबल जैसे अभियान ने बदल दिया है। साल 2018 में श्रीमती बादाम देवी के पति की असामयिक मौत से उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। 2 बच्चों के पालन-पोषण व पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी बादाम देवी पर आ गई। सास-ससुर की भी मौत हो चुकी थी। ऐसे में बच्चों के पालन-पोषण और शिक्षा की व्यवस्था करना उनके लिए चुनौती बन गयी। बादाम देवी बताती है कि जयपुर जिला कलक्टर श्री राजन विशाल की पहल पर चलाए जा रहे अभियान 'ऑपरेशन संबल' ने उनकी जिंदगी की बहुत सी मुश्किलों को आसान कर दिया। इस अभियान के तहत उन्हें पालनहार योजना के बारे में जानकारी मिली। अब बच्चों की शिक्षा और पालन के लिए पालनहार योजना के तहत उन्हें पेंशन मिलने लगी है।

राज्य सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी विभिन्न योजनाओं में पात्र लोगों को शामिल करने के लिए जयपुर जिला प्रशासन ने अनूठी पहल करते हुए ऑपरेशन संबल अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत ऐसे लोगों की पहचान कर उन्हें योजनाओं से जोड़ा जा रहा है जो पात्र हैं और किसी कारण से योजना से नहीं जुड़ पाए हैं। 16 मार्च 2022 से शुरू हुए ऑपरेशन संबल में अब तक करीब 21,420 लोगों को लाभान्वित किया जा चुका है। अभियान के माध्यम से अब तक 18,678 लोगों को पेंशन मिलनी आरंभ हो गई है और 2,742 बच्चों को पालनहार योजना में जोड़ा जा चुका है।

जयपुर जिला कलक्टर द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन संबल में तीन चरणों में कार्य किया जा रहा है। पहले चरण में जिले की सभी ग्राम पंचायतों पर सर्वे कर ऐसे लोगों की पहचान की गई है जो कि किसी

ऑपरेशन संबल अभियान के नवाचार के बारे में जिला कलक्टर श्री राजन विशाल ने बताया कि अब तक करीब 30 हजार ऐसे लोग चिन्हित किए गए हैं जो पात्र होने के बावजूद योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं। चिन्हित सभी लोगों को लाभ मिले इसके लिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है इन सभी लोगों के आवेदन करवा कर कोशिश है कि जिले के सभी लाभार्थियों का लाभ मिलना आरंभ हो जाए।

### अभियान में 8 योजनाओं का मिल रहा है लाभ

ऑपरेशन संबल अभियान के तहत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन, राजस्थान सामाजिक सुरक्षा, लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन के साथ ही पालनहार योजना में पात्र लोगों को जोड़ा जा रहा है। ●





राज्य उपभोक्ता हैल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1800-180-6030

## उपभोक्ता की समस्या का हल तुरन्त

**प्र**त्येक व्यक्ति एक उपभोक्ता है और प्रत्येक उपभोक्ता को उपभोक्ता अधिकारों एवं कानूनों की जानकारी होना आवश्यक है। एक बेहतर एवं उत्कृष्ट राष्ट्र की आधारशिला स्थापित करने में जिम्मेदार व सशक्त उपभोक्ता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

उपभोक्ता जागरूकता के महत्व का समझते हुए प्रदेश की संवेदनशील राज्य सरकार ने उपभोक्ता शिक्षा, उपभोक्ता संरक्षण और उपभोक्ता जागरूकता को प्राथमिकता प्रदान की है। इसी क्रम में उपभोक्ता विवादों के निवारण की वैकल्पिक व्यवस्था एवं उपभोक्ताओं की समस्याओं का निराकरण करने के लिए राज्य में उपभोक्ता हैल्पलाइन संचालित की जा रही है। उपभोक्ता हैल्पलाइन का टोल फ्री नंबर 1800-180-6030 है। हैल्पलाइन उपभोक्ताओं से संबंधित समस्त समस्याओं के निराकरण के लिए निःशुल्क परामर्श प्रदान करती है और उपभोक्ता मंचों में परिवाद दायर करने के लिए मार्गदर्शन भी देती है। हैल्पलाइन प्रत्येक कार्य दिवसों में प्रातः 10 से सायं 5 बजे तक कार्य करती है।

### हैल्पलाइन के उद्देश्य

राज्य उपभोक्ता हैल्पलाइन की स्थापना मुख्य रूप से निम्न उद्देश्य की पूर्ति के लिए की गई है :-

**सपना शाह**  
जनसम्पर्क अधिकारी

- शिकायतों का शीघ्र समाधान करना।
- राज्य स्तर पर वैकल्पिक उपभोक्ता प्रतितोष निवारण ढांचे का विकास करना।
- अधिकतम विवादों का कोर्ट के बाहर समाधान करना।
- ग्रामीण उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाना।
- राज्य स्तरीय स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन का क्षमता संवर्धन करना।
- राज्य स्तरीय कार्य तंत्र को अनुभवशील बनाना।
- कंपनियों एवं सेवा प्रदाताओं को उपभोक्ता विवादों के समाधान के लिए अधिक सक्रिय करना।
- क्षेत्रीय भाषा में सेवा प्रदान करना।

हैल्पलाइन पर अब तक कुल 55 हजार 328 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिसमें से 53 हजार 114 शिकायतों का सलाह एवं मार्गदर्शन द्वारा निस्तारण किया गया। उपभोक्ता अपनी शिकायत हैल्पलाइन नंबर के अतिरिक्त वाट्सएप नंबर 7230086030 एवं ई-मेल आईडी stateconsumerhelpline.raj@gmail.com पर भी दर्ज करवा सकते हैं। ●

## बड़बेला तालाब पर बनेगी लव-कुश वाटिका

**मु**ख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने अपनी बजट घोषणा में प्रत्येक जिले में 2 करोड़ रुपये की लागत से लव कुश वाटिका विकसित करने की घोषणा की है। बजट घोषणा के क्रियान्वयन के लिए झालावाड़ जिले के असनावर तहसील के बड़बेला तालाब क्षेत्र को लव-कुश वाटिका के रूप में विकसित करने का निर्णय वन विभाग झालावाड़ द्वारा लिया गया है।

अरावली एवं विन्ध्याचल पर्वतमालाओं का संगम झालावाड़ जिला फ्लोरा, फोना एवं एवीफोना से समृद्ध है। सर्वाधिक वर्षा के कारण राजस्थान के चेरपूँजी के नाम से प्रसिद्ध झालावाड़ जिले में 200 से अधिक प्रजातियों के विदेशी एवं स्थानीय पक्षी पाए जाने के कारण जिला इको टूरिज्म के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है।

लव-कुश वाटिका के रूप में चयनित बड़बेला तालाब एक वेटलैण्ड है जहां पर विदेशी एवं स्थानीय पक्षी अठखेलियां करते नजर आते हैं। यहां हर साल सर्दियों के मौसम में विदेशी पक्षी मेटिंग के लिए आते हैं। जैसे ही सर्दियां खत्म होती हैं ये पावणे पक्षी अपने देश वापस लौट जाते हैं। वन विभाग इन पक्षियों को प्राकृतिक वातावरण, संरक्षण तथा पक्षी प्रेमियों तथा पर्यटकों के लिए इस क्षेत्र को ईको टूरिज्म के रूप में विकसित करने जा रहा है।

### बड़बेला में ये पक्षी पाए जाते हैं

बड़बेला वेटलैण्ड पर सारस क्रेन, बारहैडेड गूज, नर्दन पिनटेल, पेन्टेड स्टार्क, यूरेसियन स्पून बिल, रूडी शैलडक, वाइट ब्रेस्टेड वाटरहेन, कामन मूरहेन, ग्रेहेरॉन, ब्लैक विग्ड स्टिलट, रेड वेटेड लेपविंग, लिटिल इग्रेट, लिटिल कामॉरिन्ट, लिटिल रिग्ड, हाउस स्पेरा, ब्लू रोक पिजन, इजिप्शियन वल्चर सहित विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं।

### बड़बेला में 2 करोड़ की लागत से होंगे विभिन्न विकास कार्य

बड़बेला तालाब पर इको टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने के

हेमन्त सिंह

सहायक निदेशक, जनसम्पर्क

लिए 2 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न विकास कार्य किए जाएंगे। जिसमें बड़बेला तालाब के चारों तरफ 1.25 करोड़ से पाथ-वे का निर्माण, 5 लाख रुपये से कच्चे रोड से पक्के रोड को जोड़ने के लिए लिंक रोड, खरंजा निर्माण कार्य, तालाब पर पक्षियों के आश्रय के लिए 5 लाख रुपये से मडफ्लेट का निर्माण, 10 लाख रुपये की लागत से तालाब के चारों ओर स्थानीय प्रजाति की घांस लगाने के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए जाएंगे, पक्षियों की अठखेलियां वन प्रेमियों व पक्षी प्रेमियों के निहारने के लिए 15 लाख रुपये की लागत से तालाब पर वाच टॉवर का निर्माण कराया जाएगा, तालाब के चारों ओर 10 लाख की लागत से बर्ड वॉचिंग के लिए वॉकिंग ट्रेल का निर्माण, 7.5 लाख की लागत से बोरवेल खोदने एवं सोलर पम्प लगाने का कार्य किया जाएगा। इसके अतिरिक्त करीब 20 लाख रुपये से बर्ड वॉचिंग के लिए शैल्टर, एन्ट्री गेट, गार्ड चौकी, साइन बोर्ड्स, पर्यटकों के लिए आवश्यक सुविधाओं सहित अन्य कार्य किए जाएंगे। ●





## अजमेर का नया आकर्षण है झीलें, आ रहे हजारों सैलानी

उदयपुर की तर्ज पर विकसित हो रही आनासागर और फॉयसागर झीलें

**कि**

सी भी शहर की खूबसूरती में झील सबसे बड़ा आकर्षण होती हैं। अजमेर भी एक ऐसा शहर है जहां एक नहीं बल्कि दो झीलें शहर की सुन्दरता बढ़ाती हैं।

ऐतिहासिक आनासागर और फॉयसागर झीलों पर रोजाना हजारों पर्यटकों का जमावड़ा रहता है। हाल ही में स्मार्ट सिटी योजना और अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा करवाए गए सौन्दर्यीकरण और विकास कार्यों के बाद इन झीलों की सुंदरता और निखर आई है।

ऐतिहासिक आनासागर झील का निर्माण अजमेर के राजा अर्णोराज ने करवाया था। करीब 10 किलोमीटर के वृत्त क्षेत्र में फैली यह झील सदियों से शासकों और आमजन को लुभाती आई है। झील के किनारे पर खूबसूरत बारादरी और संगमरमर की इमारतों के साथ ही बजरंगगढ़ और सर्किट हाउस बना हुआ है। झील के किनारों पर 8.5 किलोमीटर लम्बा पाथ वे, बर्ड पार्क, लेक व्यू फ्रंट पार्क, सेवन वंडर्स और छतरियां बनाई गई हैं। झील का वॉक वे पैदल सैर करने वालों के साथ ही साइक्लिंग करने वालों की भी पसंदीदा जगह बन गया है। प्रतिदिन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, प्रजापिता ब्रह्मा के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं के साथ ही खूबसूरत नजारों से भरपूर पुष्कर घूमने आने वाले सैलानी आनासागर झील के किनारे कुछ समय जरूर गुजारते हैं। झील के पश्चिमी छोर पर बना पार्क सैलानियों और शहरवासियों के लिए आकर्षण का नया केन्द्र बन गया है। झील पर शाम को म्यूजिकल फाउंटैन आपको देश-विदेश के बड़े शहरों के जल

भानु प्रताप सिंह गुर्जर

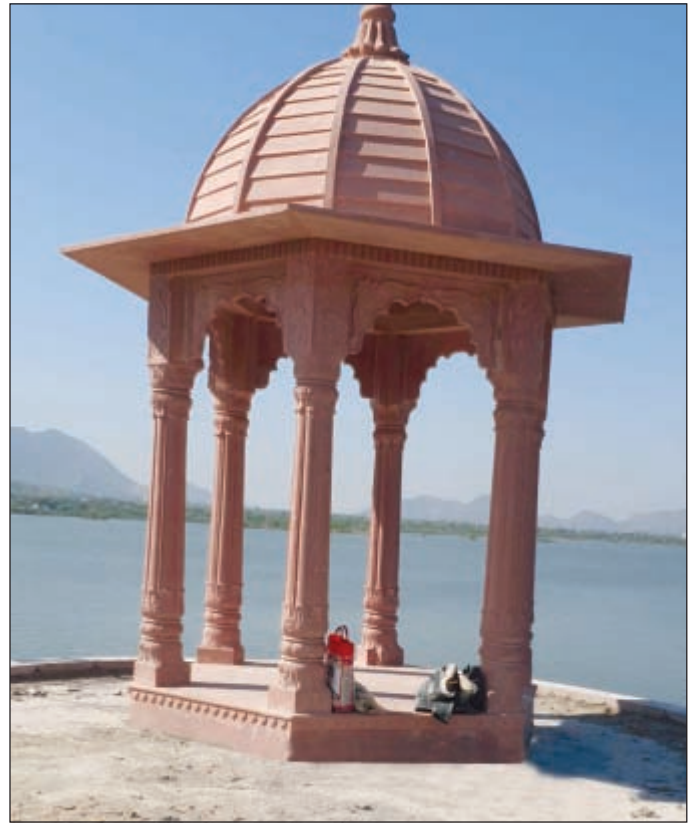
जनसम्पर्क अधिकारी, अजमेर





स्रोतों का अहसास कराता है।

इसी तरह फॉयसागर झील का निर्माण एक शताब्दी पूर्व अजमेर शहर की पेयजल एवं सिंचाई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया था। अरावली पर्वत शृंखला की गोद में प्राकृतिक नजारों से



भरपूर यह झील भी पर्यटन का नया केन्द्र बन गई है। हाल ही में अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा झील के किनारे पर सौन्दर्यीकरण के कार्य करवाए गए हैं। इसके तहत फॉयसागर की पाल पर नई चौपाटी, पाथ-वे, छतरियां बनाई गई है। यहां पाल के नीचे भी फुटपाथ बनाया गया है। पूरी पाल पर उच्च किस्म के पौधे, हैरिटेज लाइट व अन्य सौन्दर्यीकरण भी करवाया गया है। ●



## मेवाड़ अंचल का विश्व विख्यात जलतंत्र

रे

गिस्तान के लिए शुमार राजस्थान का दक्षिणी भाग मेवाड़ अंचल अपने विश्वविख्यात परंपरागत जल तंत्र के लिए सदियों से जाना पहचाना जाता है। उदयपुर शहर की फतेहसागर, पिछोला, उदयसागर, स्वरूप सागर झील के साथ ही 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जयसमंद झील अथाह जल संचय का प्रमुख स्रोत हैं। शहर की झीलें एक दूसरे से सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं और प्राकृतिक प्रवाह से पानी एक से दूसरी झील में आता है। दूसरी तरफ जयसमंद झील एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। यह दो पहाड़ियों के बीच में गोमती नदी पर बनी हुई है जिसमें 9 नदियों और 99 नालों का पानी संग्रहित करने की क्षमता है। अरावली की पहाड़ियों से घिरी हुई होने के कारण इन सभी झीलों का नैसर्गिक सौंदर्य भी अतुलनीय है।

आलेख एवं छाया : डॉ. कमलेश शर्मा, उपनिदेशक



## चांद बावड़ी, आभानेरी

**रा**जस्थान में जल संचयन एवं प्रबंधन परम्परा की समृद्ध विरासत सदियों से विकसित रही है। जयपुर-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित दौसा जिले के सिकन्दरा से उत्तर की ओर स्थित है, आभानेरी। शिल्प और स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने, जल संचयन व संरक्षण की धरोहर आभानेरी की चांद बावड़ी का ऐतिहासिक महत्त्व अनूठा है। देश-विदेश से पर्यटक जल संरक्षण की इस विरासत को देखने के लिए यहां आते हैं।



तब

तस्वीर बदलाव की



अब



राजस्थान सरकार के एलेगशिष कार्यक्रम और अन्य योजनाओं की विस्तृत जानकारी  
<https://jankalyan.rajasthan.gov.in> पर देखी जा सकती है।

#DIPRRajasthan



प्रकाशक व मुद्रक - सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशक, पुरुषोत्तम शर्मा द्वारा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के लिए, शासन सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) से प्रकाशित  
सम्पादक-श्रीमती अलका सक्सेना, मै.कृष्णा प्रिन्टर्स, डी-14, सुदर्शनपुरा, जयपुर से मुद्रित, 'राजस्थान सुजस'-पृष्ठ संख्या 60, लागत मूल्य 30.56 रुपए • 5,00,000 प्रतियां